ई-पत्रिका
₹ 49/-

▶ **भारत की रणनीतिक हकीकत**
स्वायत्तता, समावेश एवं वैश्विक उत्तरदायित्व का संतुलन

▶ **ढाका की नई राह**
दिल्ली से दूरी, इस्लामाबाद से नज़दीकी

CULT CURRENT

वर्ष: 8 अंक: 7 जुलाई, 2025

WE MAKE VIEWS

ट्रंपघात

अग्रणी है अमेरिका, या हार रहा मैदान?

Let's 360°

- Media Consultancy
- Web solution
- Advertising
- Publication
- Languages Services
- Survey & Research
- Branding
- AV Production
- Campaign management
- Event organizer
- PR partner, PR associate
- Content writer & provider
- Media analyst

URJAS MEDIA VENTUE IS PERHAPS THE ONLY CONSULTING FIRM THAT CAN GIVE YOUR ORGANISATION A 360 DEGREE MEDIA BUSINESS GROWTH CONSULTING THROUGH IT'S 360 CAPABILITIES. FOR US, CONSULTING DOES NOT ONLY MEAN MECHANICAL COST REDUCTION THROUGH BETTER IT APPLICATIONS, WE FIND OUT WHAT YOUR ORGANISATION REALY NEEDS AND GIVE YOU AN INTELLECTUAL SOLUTION THAT HELP YOU REDUCE COST AS WELL AS HELPS YOURS BUSINESS GROW AND BEAT THE COMPETITION.

NOW!! OUR CONSULTANT WILL GET BACK TO YOU IN 24 HOURS AND PUT YOU IN TO THE HIGH GROWTH PATH

URJAS MEDIA
VENTURE

BEAT THE COMPETITION

www.urjasmedia.com

SMS 'BUSINESS GROWTH'
TO +91-8826-24-5305 OR
E-MAIL info@urjasmedia.com

गुमनाम नायक

जुगाड़ से जज़्बा तक: कुमैल की प्रेरक उड़ान

अली कुमैल

बिजनौर, उत्तर प्रदेश के 23 वर्षीय अली कुमैल ने यह साबित कर दिखाया है कि हालात भले कठिन हों, लेकिन जज़्बा हो तो कुछ भी मुमकिन है। 10वीं के बाद पढ़ाई छूट गई, लेकिन सपनों से रिश्ता नहीं। AC मैकेनिक की नौकरी करते हुए उन्होंने अपने शौक के लिए 50,000 रुपये जोड़े और लकड़ी व लोहे से एक अनोखा इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर तैयार कर डाला। 40% लकड़ी और 60% लोहे से बना यह ट्रैक्टर अब न केवल उनके गांव में बल्कि पूरे देश में सराहना पा रहा है। कुमैल का यह नवाचार दिखाता है कि जुनून और मेहनत मिलकर चमत्कार कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर छाए इस गुमनाम नायक से हम सबको प्रेरणा मिलती है—जहां चाह, वहां राह!

संपादकीय

राष्ट्रीय संपादक
संजय श्रीवास्तव

संपादक
श्रीराजेश

प्रबंध संपादक
सच्चिदानंद पाण्डेय

रोमिंग संपादक
डॉ. राजाराम त्रिपाठी

राजनीतिक संपादक
अंशुमान त्रिपाठी

मेट्रो संपादक
शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव
डॉ. रुद्र नारायण

अंतर्राष्ट्रीय संपादक
श्रीश पाठक

कारपोरेट संपादक
गगन बत्रा

खेल संपादक
जलज श्रीवास्तव

डिजीटल संपादक
सुनीता त्रिपाठी

सहायक संपादक
संदीप कुमार

उप संपादक
मनोज कुमार
संतु दास

साहित्य संपादक
अनवर हुसैन

कला संपादक
जया वर्मा

वेब एवं आईटी विशेषज्ञ
अनुज कुमार सिंह

फोटो संपादक
विवेक पाण्डेय

विशेष संवाददाता
कमलेश झा
विकास गुप्ता

संवाददाता
संदीप सिंह
अनिरुद्ध यादव

ब्यूरो प्रमुख (अंतर्राष्ट्रीय)
अकुल बत्रा (अमेरिका)
सी.शिवरतन (नीदरलैंड)
जी. वर्मा(लंदन)
डॉ. मो. फहीम अकबर (पाकिस्तान)
ए. असगरजादेह (ईरान)
डॉ. निक सेरी (मलेशिया)

ब्यूरो प्रमुख (राष्ट्रीय)
आर. रंजन (नई दिल्ली)
संजय कुमार सिंह (लखनऊ)
कैप्टन सुधीर सिन्हा (रांची)
निमेष शुक्ल (पटना)
नागेन्द्र सिंह (कोलकाता)
राकेश रंजन (गुवाहाटी)

विपणन
सत्यजीत चौधरी
महाप्रबंधक

ऑनलाइन प्रसार
सृजीत डे

वर्षः 8 अंकः 7 जुलाई, 2025

fb.com/cultcurrent Follow us: @Cult_Current cultcurrent@gmail.com

URJAS MEDIA VENTURE
Head office: Swastik Apartment, GF, Pirtala, Agarpara, Kolkata 700 109, INDIA, Tel: +91 6289-26-2363
Corporate Office: 14601, Belaire Blvd, Houston, Texas 77083 USA Tel: +1 (832) 670-9074
Web: http://cultcurrent.in

Cult Current is a monthly e-magazine published by Urjas Media Ventures from Swastik Apartment, GF, Pirtala, Agarpara, Kolkata 700 109.
Editor: Srirajesh

Disclaimer: All editorial and non-editorial positions in the e-magazine are honorary. The publisher and editorial board are not obligated to agree with all the views expressed in the articles featured in this e-magazine. Cult Current upholds a commitment to supporting all religions, human rights, nationalist ideology, democracy, and moral values.

COVER STORY

26

निर्दयता की क़ीमत	36
टैरिफ की तकरार	38
सुरक्षा नहीं, सौदा ट्रंप की नाटो नीति	42
ट्रम्प का अहंकार , धरती का संताप	46
अमेरिकी मीडिया ट्रंप के शासन में परीक्षा	49
USAID में कटौती वैश्विक तबाही	50
अमेरिका का पाकिस्तान मोह	52
युद्ध एवं प्रभुत्व की कूटनीति	54
अफ्रीका: सैन्य शासन का नया युग	58
ढाका की नई राह	60
लाल सागर का संकट	64
भारत की वैश्विक कूटनीति	68
रणभूमि 2.0 भारत की एआई शक्ति	72
जलवायु शरणार्थी: अगला वैश्विक संकट	74

12 **आकाशगामी भारत**
विज्ञान, शक्ति व संकल्प की कहानी

16 **भारत की रणनीतिक हकीकत**
स्वायत्तता, समावेश एवं वैश्विक उत्तरदायित्व का संतुलन

CONTENTS

ऑस्कर में कमल!
साउथ का स्टार, अब ग्लोबल मंच पर
76

Small talk

एलनाज़ का दोहरे धोखे का ड्रामा!

ईरानी-जर्मन अभिनेत्री एलनाज़ नोरौज़ी, जो भारतीय फिल्मों में अपने किरदारों और करण जौहर के रियलिटी शो 'द ट्रेटर' में दिमागी खेलों की महारत के लिए जानी जाती हैं, ने हाल ही में एक बड़ा खुलासा किया है! एक फिल्मी पत्रिका को दिए एक चटपटे इंटरव्यू में एलनाज़ ने बताया कि उन्हें उनके चार साल पुराने बॉयफ्रेंड ने धोखा दिया। लेकिन रुकिए- कहानी और भी पेचीदा है! पता चला कि इस धोखे में उनकी सबसे करीबी दोस्त भी शामिल थी! जी हां, उनका बॉयफ्रेंड पूरे समय उनकी बीएफएफ के साथ भी रिलेशन में था। हैरान रह गए? एलनाज़ भी रह गई थीं! जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें कभी शक हुआ, तो एलनाज़ ने साफ कहा—बिलकुल नहीं। ●

2025 में तहलका मचाने वाली खोजें

कॉस्मिक रहस्य का समाधान!

एक नई क्रांतिकारी शोध में ब्रह्मांड के 'लापता' पदार्थ की स्थिति का पता लगा लिया गया है, साथ ही अब तक का सबसे दूरस्थ फास्ट रेडियो बर्स्ट (एफआरबी) भी रिकॉर्ड किया गया है। हार्वर्ड-स्मिथसोनियन सेंटर फॉर एस्ट्रोफिज़िक्स (सीएफए) और कैलटेक के खगोलशास्त्रियों ने एफआरबी को एक उपकरण के रूप में उपयोग करते हुए यह खोज की कि ब्रह्मांड के सामान्य पदार्थ का तीन-चौथाई से भी अधिक हिस्सा आकाशगंगाओं के बीच फैली बेहद पतली गैस में मौजूद है। ●

प्लास्टिक जो बैक्टीरिया से लड़े!

नॉटिंघम विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने प्लास्टिक की सतह पर ऐसे विशेष पैटर्न खोजे हैं, जो बैक्टीरिया को बढ़ने से काफी हद तक रोक सकते हैं। यह खोज मेडिकल उपकरणों—जैसे कि कैथेटर—पर संक्रमण रोकने में बेहद उपयोगी साबित हो सकती है। बायोफिल्म्स एक चिपचिपी परत होती हैं जो बैक्टीरिया को शरीर की प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक प्रणाली से बचाती हैं। चूंकि कई चिकित्सा उपकरण प्लास्टिक से बने होते हैं और अस्पतालों में आमतौर पर उपयोग किए जाते हैं। ●

पृथ्वी से निकल रहा सोना!

वैज्ञानिकों ने एक चौंकाने वाला प्रमाण खोजा है कि सोने जैसे कीमती धातु पृथ्वी के भीतरी कोर से निकलकर मेंटल तक पहुंच रही हैं- और अंततः सतह पर, जैसे कि हवाई जैसे स्थानों में प्रकट हो रही हैं। रुथेनियम में सूक्ष्म समस्थानिक (isotopic) अंतर पहचानने की एक नई तकनीक का उपयोग करते हुए, शोधकर्ताओं ने एक विशेष संकेत पकड़ा जो पृथ्वी के गहरे कोर से आने वाली सामग्री की ओर इशारा करता है। ●

नई क्वांटम एम्प्लीफायर: अब 90% कम ऊर्जा में काम!

क्वांटम कंप्यूटर वे समस्याएँ हल करने की क्षमता रखते हैं जो आज के सबसे शक्तिशाली सुपरकंप्यूटरों के लिए भी असंभव हैं—चाहे वह दवा खोज हो, साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता या लॉजिस्टिक्स। अब स्वीडन की चाल्मर्स यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है, जो हमें उस भविष्य के और करीब ले जाती है। उन्होंने एक अल्ट्रा-प्रभावी एम्प्लीफायर विकसित किया है जो केवल तब सक्रिय होता है जब क्वांटम बिट्स (क्यूबिट्स) से डेटा पढ़ा जाना होता है। ●

भारतीय SUV बाज़ार में दहाड़ती आई मारुति जिम्नी 5-डोर!

मारुति सुज़ुकी ने अपनी बहुप्रतीक्षित 5-डोर जिम्नी को भारत में आधिकारिक रूप से लॉन्च कर दिया है, जिससे उसकी SUV रेंज को एक नया विस्तार मिला है। एडवेंचर पसंद करने वालों के लिए डिज़ाइन की गई यह गाड़ी मजबूत बॉडी, दमदार ऑफ-रोड क्षमता, और AllGrip Pro 4x4 सिस्टम के साथ आती है। इसमें 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन और सुविधाजनक, खुला इंटीरियर भी दिया गया है। ●

नियुक्ति

लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा, कमांडर-इन-चीफ

1 जून 2025 को लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा को भारत की एकमात्र त्रि-सेवा थिएटर कमान अंडमान और निकोबार कमान का नया कमांडर-इन-चीफ नियुक्त किया गया। उन्होंने एयर मार्शल साजू बालकृष्णन का स्थान लिया, जो इससे पूर्व इस प्रतिष्ठित पद पर कार्यरत थे।

इस्तीफा

संजीव पुरी,
चेयरमैन व प्रबंध निदेशक, आईटीसी लि.

17 जून 2025 को संजीव पुरी ने आईटीसी लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक पद से अवकाशप्राप्ति के बाद इस्तीफा दे दिया। अपने कार्यकाल के दौरान संजीव पुरी ने ITC को सिर्फ तंबाकू उत्पादों तक सीमित कंपनी से एक बहु-आयामी व्यवसाय समूह में परिवर्तित कर दिया।

उन्होंने कहा

आयतुल्ला अली ख़ामेनेई
ईरान के सर्वोच्च नेता

"हमने अमेरिका को ज़ोरदार तमाचा मारा है — अगर वे फिर से रेड लाइन पार करते हैं, तो उन्हें और हमलों का सामना करना पड़ेगा।"

प्रिंस विलियम
वेल्स के राजकुमार

"जलवायु संकट तात्कालिकता और उद्देश्य की मांग करता है — यदि हम आदिवासी नेतृत्व को नजरअंदाज करते हैं, तो प्रकृति की सदियों पुरानी बुद्धिमत्ता खो बैठेंगे।"

श्रद्धांजलि

स्वामी विवेकानंद
(12/01/1863-04/07/1902)

स्वामी विवेकानंद भारत के सबसे पूज्यनीय आध्यात्मिक नेताओं में से एक थे, जिन्होंने वेदांत दर्शन को विश्व पटल पर प्रतिष्ठा दिलाई। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में नरेंद्रनाथ दत्त के रूप में हुआ था। वे एक विलक्षण बुद्धिजीवी थे जिनके भीतर जिज्ञासु मस्तिष्क और सत्य की खोज की तीव्र लालसा थी। उनकी यह आध्यात्मिक खोज उन्हें उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस के चरणों तक ले गई, जिन्होंने उनके जीवन को पूरी तरह से रूपांतरित कर दिया। गुरु की प्रेरणा से उन्होंने मानवता की सेवा को अपना धर्म बना लिया।

गुरु के महाप्रयाण के बाद विवेकानंद ने सन्यास की दीक्षा ली और भारत भ्रमण पर निकल पड़े। इस यात्रा में उन्होंने देश की गहराई में छिपी दरिद्रता, अज्ञानता और सामाजिक अन्याय को निकट से देखा। इसका उत्तर उन्होंने एक तेजस्वी आह्वान के रूप में दिया—'आध्यात्मिक और राष्ट्रीय पुनर्जागरण'।

1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म महासभा में जब उन्होंने 'Sisters and Brothers of America' से अपना भाषण आरंभ किया, तो पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। इस भाषण के बाद उन्होंने न केवल भारत को वैश्विक मंच पर गौरव दिलाया, बल्कि हिंदू धर्म की सहिष्णुता, सार्वभौमिक भाईचारे और आत्मबल की भावना को पूरी दुनिया से परिचित कराया।

1897 में उन्होंने 'रामकृष्ण मिशन' की स्थापना की, जिसका उद्देश्य आध्यात्मिकता और सामाजिक सेवा को एक सूत्र में पिरोना था। उनका प्रसिद्ध उद्घोष—'उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए'—आज भी करोड़ों लोगों की आत्मा को प्रेरणा देता है। 4 जुलाई 1902 को मात्र 39 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया, परंतु उनका जीवन और विचार आज भी जीवंत हैं। ●

भारत ने आतंकवाद पर दोहरे मानदंडों का किया विरोध

चीन के क्विंगदाओ में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की बैठक के संयुक्त वक्तव्य पर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हस्ताक्षर न करने से कई सवाल उठ रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि एससीओ के कुछ सदस्य देशों के बीच कुछ मुद्दों पर सहमति नहीं बनने के कारण संयुक्त वक्तव्य जारी नहीं हो सका। राजनाथ सिंह 25 और 26 जून को क्विंगदाओ में आयोजित दो दिवसीय एससीओ बैठक में दिए गए अपने बयान में राजनाथ सिंह ने 'ऑपरेशन सिंदूर' का जिक्र भी किया, जिसे पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में शुरू किया गया था। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले में पीड़ितों को उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर गोली मार दी गई थी, और संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकी समूह लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े द रेजिस्टेंस फ्रंट ने हमले की जिम्मेदारी ली है। ●

दक्षिण कोरिया में ली जे-म्युंग राष्ट्रपति निर्वाचित

एक एक नाटकीय राजनीतिक बदलाव में, ली जे-म्युंग 3 जून को मौजूदा राष्ट्रपति यून सुक-योल के महाभियोग के बाद दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। विपक्षी दल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता ली ने आर्थिक सुधार, सामाजिक कल्याण के विस्तार और उत्तर कोरिया के साथ नए सिरे से राजनयिक संबंधों के वादे के साथ एक प्रगतिशील मंच पर प्रचार किया। उनकी अध्यक्षता सियोल की विदेश नीति में एक तेज बदलाव का प्रतीक है, क्योंकि यह चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच अपनी रणनीतिक स्थिति पर पुनर्विचार करता है। ●

ट्रम्प ने लगाया यूरोपीय संघ पर 50% टैरिफ

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा सभी यूरोपीय संघ के आयात पर 50% का व्यापक टैरिफ लगाने की योजना की घोषणा के बाद व्यापार तनाव बढ़ गया, जिसमें ऑटोमोबाइल और एयरोस्पेस जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को लक्षित किया गया है। 9 जुलाई से प्रभावी होने वाला यह निर्णय पिछली देरी को उलट देता है और ब्रुसेल्स से तत्काल जवाबी कार्रवाई के खतरों को आकर्षित किया है। अर्थशास्त्रियों ने चेतावनी दी है कि एक-दूसरे पर जवाबी कार्रवाई करने से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला गंभीर रूप से बाधित हो सकती है और मुद्रास्फीति तेज हो सकती है। ●

वर्ल्ड बैंक ने घटाया वैश्विक विकास पूर्वानुमान

विश्व बैंक ने 2025 के अपने वैश्विक विकास पूर्वानुमान को 2.7% से घटाकर 2.3% कर दिया है, जिसमें बढ़ते व्यापार विवादों, विशेष रूप से अमेरिका, चीन और यूरोपीय संघ के बीच, को आर्थिक स्थिरता के लिए प्रमुख बाधा बताया गया है। वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के लगभग 70% के कमजोर प्रदर्शन करने का अनुमान है, निवेश का आत्मविश्वास, उपभोक्ता खर्च और निजी क्षेत्र की वृद्धि सभी स्थिर हैं। मुद्रास्फीति का दबाव लगातार बना हुआ है, और उभरते बाजार विशेष रूप से कमजोर हैं। ●

बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट ने जमात पर लगे प्रतिबंध हटाया

एक एक विवादास्पद फैसले में, बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामी पार्टी जमात-ए-इस्लामी (JI) पर लगे लंबे समय के प्रतिबंध को हटा दिया और पूर्व नेता अजहरुल्ला इस्लाम को बरी कर दिया। यह निर्णय पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व में क्रांति के बाद के ढांचे के प्रमुख तत्वों को उलट देता है। 2026 के मध्य तक राष्ट्रीय चुनावों के साथ, JI की कानूनी बहाली गठबंधन की राजनीति को महत्वपूर्ण रूप से नया आकार दे सकती है। ●

अमेरिकी शुल्क खत्म कराने के लिए ब्रिटेन हुआ सक्रिय

बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर एंड्रयू बेली ने बढ़ते व्यापार की अप्रत्याशितता पर चिंता जताई है, जो ट्रम्प युग के स्टील टैरिफ से शुरू हुई है जो यूके के खिलाफ अभी भी लागू हैं। जवाब में, ब्रिटेन ने घरेलू उत्पादकों की रक्षा के लिए स्टील आयात को सीमित कर दिया है, जबकि व्यापार सचिव जोनाथन रेनॉल्ड्स ने 2030 तक ऑटोमोटिव क्षेत्र के लिए 2.5 बिलियन पाउंड के समर्थन पैकेज का अनावरण किया। यूके वाशिंगटन पर स्टील शुल्क हटाने के लिए दबाव डाल रहा है।●

जी7 ने हिरोशिमा प्रक्रिया में AI प्रशासन सिद्धांतों को दिया अंतिम रूप

जी7 देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता विनियमन के लिए 11 मुख्य सिद्धांतों को ₹हिरोशिमा प्रक्रिया₹ के हिस्से के रूप में औपचारिक रूप दिया है, पारदर्शिता, नैतिक उपयोग और डेटा गोपनीयता के प्रति साझा प्रतिबद्धताओं को मजबूत किया है। जैसे-जैसे यूरोपीय संघ अपने एआई अधिनियम को लागू करने के करीब पहुंच रहा है, ओपन-सोर्स नवाचार बनाम राज्य निरीक्षण पर बहस तेज हो रही है। इस बीच, चीन डीपसीक जैसे उद्यमों के माध्यम से अपनी एआई महत्वाकांक्षाओं को तेज करता है, जिससे पश्चिमी शक्तियों के बीच अधिक समन्वय का आह्वान किया जाता है। आगामी मंत्रिस्तरीय बैठकें भविष्य के एआई प्रशासन को परिभाषित करने की संभावना है, विशेष रूप से मॉडल परीक्षण सीमा, एल्गोरिथम पारदर्शिता और डेटा-साझाकरण जनादेश के संबंध में। आने वाला महीना वैश्विक एआई मानदंडों और नियामक परिदृश्यों को नया आकार दे सकता है। ●

ओईसीडी ने वैश्विक जीडीपी पूर्वानुमान को घटाया

ओईसीडी ने 2025 और 2026 दोनों के लिए अपने वैश्विक जीडीपी दृष्टिकोण को 2.9% तक घटा दिया है, इस संशोधन का श्रेय बढ़ती व्यापार बाधाओं, विशेष रूप से अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ को दिया गया है। प्रमुख संकेतक बाधित आपूर्ति श्रृंखलाओं, बढ़ती उपभोक्ता कीमतों और निवेशकों के विश्वास को कम करने की ओर इशारा करते हैं। अगले साल अमेरिका के सिर्फ 1.6% की दर से बढ़ने की उम्मीद है, जबकि चीन की अर्थव्यवस्था लक्षित प्रोत्साहन के कारण अपेक्षाकृत स्थिर बनी हुई है। ●

तेल की कीमतें गिरने से सऊदी अरब का कर्ज बढ़ा

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने भविष्यवाणी की है कि सऊदी अरब का ऋण-से-जीडीपी अनुपात 2028 तक बढ़कर 44.5% हो जाएगा, जिसमें राजकोषीय घाटा 5% के करीब पहुंच जाएगा, जो पिछले अनुमानों से कहीं अधिक है। घटती तेल की कीमतों और हाल के ओपेक+ उत्पादन कटौती ने राज्य के राजस्व धाराओं पर दबाव डाला है। जवाब में, रियाद वैट बढ़ाने और नवीकरणीय ऊर्जा की ओर अपने संक्रमण को तेज करने पर विचार कर रहा है। बाजार पर नजर रखने वाले अब अगली ओपेक+ बैठक का इंतजार कर रहे हैं, जो यह निर्धारित कर सकती है कि सऊदी अरब उत्पादन बढ़ाता है या उत्पादन कटौती को बनाए रखता है। इस महीने लिए गए निर्णय राज्य के वित्तीय प्रक्षेपवक्र और वैश्विक ऊर्जा बाजारों दोनों को प्रभावित करेंगे। ●

पीएम मोदी की वैश्विक कूटनीति यात्रा भारत की विदेश नीति को आकार देगी

जुलाई के शुरू में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस और ऑस्ट्रिया की यात्रा निर्धारित है, जो नई सरकार बनाने के बाद उनकी पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा है। वैश्विक ध्यान रूस दौरे पर है - यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद उनकी मास्को की पहली यात्रा। पश्चिम की बारीकी से नजरों के साथ, मोदी की राष्ट्रपति पुतिन के साथ बैठक ऐसे समय में हो रही है जब भारत रणनीतिक तटस्थता और वैश्विक दबाव के बीच एक तंग रस्सी पर चल रहा है। चर्चा ऊर्जा, रक्षा और व्यापार सहयोग पर केंद्रित होने की उम्मीद है। ऑस्ट्रिया की यात्रा 40 वर्षों से अधिक समय में किसी भारतीय पीएम द्वारा पहली यात्रा होगी, जिसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और यूरोपीय निवेशकों को आकर्षित करना है। घरेलू स्तर पर, यात्रा एक संकेत देती है कि भारत वैश्विक विभाजन के बीच भी अपने राजनयिक संतुलन पर जोर देना चाहता है। ●

अब पूरे देश में लागू होंगे नए आपराधिक कानून

एक जुलाई से, भारत एक नए कानूनी युग में प्रवेश करेगा, क्योंकि यह तीन औपनिवेशिक युग के कानूनों - भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम - को भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम से बदल देगा। इसका उद्देश्य क्या है? तेज़ मुकदमे, सुव्यवस्थित जांच प्रक्रियाएं और मजबूत पीड़ित सुरक्षा। उदाहरण के लिए, अब ऑनलाइन एफआईआर दर्ज की जा सकती है। ●

नीट-यूजी विवाद बढ़ा: SC याचिकाओं पर करेगा सुनवाई

नीट -यूजी 2024 का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रश्न पत्र लीक और अनुचित अंकन के छिटपुट आरोपों के रूप में जो शुरू हुआ, वह अब छात्र विरोध, कानूनी याचिकाओं और राजनीतिक तूफान से जुड़े एक राष्ट्रव्यापी घोटाले में बदल गया है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) अपनी पारदर्शिता की कमी के लिए कड़ी आलोचना के अधीन है, खासकर 67 छात्रों द्वारा कथित तौर पर पूर्ण 720 अंक प्राप्त करने के बाद - जिससे सांख्यिकीय भौंहें उठ गई हैं। ●

भारत का यूपीआई हुआ ग्लोबल

भारत का एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) अंतरराष्ट्रीय हो रहा है - और जुलाई वह महीना है जब चीजें वास्तव में गति पकड़ना शुरू कर देंगी। फ्रांस, श्रीलंका, भूटान, यूएई और सिंगापुर के साथ रोलआउट साझेदारी के बाद, भारतीय यात्री अब विदेश में यूपीआई के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं, रूपांतरण शुल्क से बच सकते हैं और तेजी से लेनदेन को सक्षम कर सकते हैं। एनआरआई को भी अपने घरेलू ऐप्स के माध्यम से सीधे भारतीय बैंक खातों में पैसा भेजने में सक्षम होने से लाभ होगा। ●

मानसून पूरे शबाब पर - कई राज्यों में बाढ़ की चेतावनी जारी

मानसून आधिकारिक तौर पर समय से पहले पूरे देश को कवर कर चुका है, और हालांकि यह कृषि के लिए अच्छी खबर है, लेकिन इसके साथ जोखिम भी बढ़ रहे हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने असम, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में लाल और नारंगी अलर्ट जारी किए हैं। कई क्षेत्रों में पहले से ही अचानक बाढ़, उफनती नदियां और भूस्खलन देखने को मिल रहे हैं। ●

लोस अध्यक्ष के चुनाव में दिखेगी एनडीए की ताकत

जैसे ही संसद का मानसून सत्र शुरू होगा, सभी की निगाहें लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव पर टिकी होंगी, एक पद जो न केवल प्रक्रिया का प्रतीक है, बल्कि शक्ति का भी प्रतीक है। जबकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, अब यह स्थिर सरकार चलाने के लिए टीडीपी और जद (यू) जैसे सहयोगियों पर निर्भर है। कथित तौर पर ये सहयोगी प्रमुख पदों पर अपनी बात रखने की मांग कर रहे हैं - स्पीकर उनमें से एक है। एक आम सहमति वाले उम्मीदवार की संभावना है। ●

इसरो की चंद्रयान-4 और गगनयान लॉन्चिंग की तैयारी

भारत की अंतरिक्ष एजेंसी, इसरो, एक मील का पत्थर महीने के लिए तैयार हो रही है। दो प्रमुख मिशनों - गगनयान, भारत की पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान, और चंद्रयान-4, एक अनुवर्ती चंद्र मिशन - के लिए तैयारियां जुलाई में पूरी गति पकड़ रही हैं। इस महीने अंतरिक्ष यात्री सुरक्षा, सिस्टम के पुनः प्रवेश और मॉड्यूल डिटेचमेंट के लिए महत्वपूर्ण परीक्षणों की उम्मीद है। यदि सफल रहा, तो गगनयान 2025 की शुरुआत तक लॉन्च हो सकता है, जिससे भारत अंतरिक्ष में मनुष्यों को भेजने वाले देशों के कुलीन क्लब में शामिल हो जाएगा। इस बीच, चंद्रयान-4 का उद्देश्य चंद्र नमूना वापसी पर ध्यान केंद्रित करके चंद्रयान-3 की ऐतिहासिक सफलता को आगे बढ़ाना है। ये मिशन न केवल वैज्ञानिक हैं - वे राष्ट्रीय गौरव और तकनीकी आत्मनिर्भरता के प्रतीक हैं। ●

मुंबई कोस्टल रोड: एक नये युग का होगा आगाज

वर्षों की देरी और विवादों के बाद, मुंबई की महत्वाकांक्षी कोस्टल रोड परियोजना आखिरकार जुलाई के अंत तक खुलने वाले अपने पहले चरण के पूरा होने के करीब है। मरीन ड्राइव से वर्ली तक 10.6 किलोमीटर के खंड से यात्रा के समय को 45 मिनट से घटाकर केवल 10 मिनट करने की उम्मीद है, जिससे शहर के दम घुटने वाले यातायात से कुछ राहत मिलेगी। सुरंगों, ऊंचे सड़कों और इको-पार्क के साथ, परियोजना को शहरी सौंदर्यीकरण को बढ़ावा देने के रूप में भी विपणन किया जा रहा है। ●

जल्द लागू होगा भारत का डिजिटल गोपनीयता कानून

भारत का डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, जो 2023 में पारित हुआ, जुलाई में औपचारिक रूप से अधिसूचित होने की उम्मीद है, जो डेटा विनियमन के एक नए युग के लिए मंच तैयार कर रहा है। नियम यह परिभाषित करेंगे कि कंपनियां उपयोगकर्ता डेटा को कैसे एकत्र करती हैं, संग्रहीत करती हैं और संसाधित करती हैं, उल्लंघन के लिए सख्त दंड के साथ। Google, Meta और Amazon जैसी तकनीकी दिग्गज पहले से ही गोपनीयता शर्तों और बुनियादी ढांचे को अपडेट कर रही हैं, जबकि भारतीय स्टार्टअप तैयारी के लिए दौड़ रहे हैं। कानून उपयोगकर्ता सहमति, डेटा सुधार के अधिकार और डेटा दुरुपयोग के लिए निवारण तंत्र की अवधारणा को पेश करता है। जबकि उपभोक्ता अधिकार नीति के केंद्र में हैं, आलोचकों का तर्क है कि कानून सरकार को एजेंसियों को जांच से छूट देने के लिए बहुत अधिक शक्ति देता है। ●

श्रीराजेश, संपादक

भारतीय विदेश नीति की झलक

जब चुप्पी की जगह गरज ने ली

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर करने से भारत का इनकार एक साहसिक कूटनीतिक बदलाव को दर्शाता है, जो आतंकवाद के प्रति पूर्ण असहिष्णुता और वैश्विक मंचों पर रणनीतिक स्वायत्तता की दृढ़ घोषणा है।

चीन के क्विंगदाओ में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की बैठक के संयुक्त बयान पर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हस्ताक्षर करने से इनकार, भारतीय विदेश और सुरक्षा नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देता है। यह घटना न केवल क्षेत्रीय राजनीति में भारत की दृढ़ स्थिति को रेखांकित करती है, बल्कि वैश्विक मंच पर आतंकवाद के मुद्दे पर भारत के मुखर दृष्टिकोण और दृढ़ संकल्प को भी दर्शाती है।

यह बैठक एक ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ पर हुई जब वैश्विक शक्ति संतुलन स्पष्ट रूप से ध्रुवीकरण की ओर बढ़ रहा है। एक तरफ, यूरोपीय देश नाटो ढांचे के भीतर अपने सैन्य खर्च को बढ़ा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ, चीन एससीओ जैसे संगठनों को 'पश्चिम के जवाब' के रूप में स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। इस भू-राजनीतिक परिदृश्य में, भारत की स्वायत्तता और रणनीतिक स्पष्टता का महत्व बढ़ जाता है।

अपनी टिप्पणियों में, राजनाथ सिंह ने स्पष्ट रूप से, बिना पाकिस्तान का नाम लिए, 'कुछ देशों' पर सीमा पार आतंकवाद को राज्य नीति के उपकरण के रूप में उपयोग करने का आरोप लगाया। उन्होंने विशेष रूप से पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले को 'धार्मिक पहचान के आधार पर लक्षित एक क्रूर कृत्य' के रूप में उल्लेख किया, और इसके जवाब में भारत द्वारा शुरू किए गए 'ऑपरेशन सिंदूर' का उल्लेख किया। इस जवाबी कार्रवाई ने एक निर्णायक संदेश भेजा- भारत अब निष्क्रिय राजनयिक निंदा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आतंक के स्रोतों को सक्रिय रूप से निष्क्रिय करने के लिए तैयार है।

यह रुख एक बड़े रणनीतिक बदलाव को दर्शाता है जहां भारत अब केवल कूटनीतिक निंदा पर निर्भर रहने के बजाय आतंकवाद के स्रोतों को निष्प्रभावी करने के लिए एक सक्रिय नीति अपना रहा है।

राजनाथ सिंह ने इस बात पर ज़ोर दिया कि आतंकवाद के दोषियों और प्रायोजकों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए, और एससीओ को इस मामले पर एकजुट रुख अपनाना चाहिए। हालांकि, संयुक्त बयान में पहलगाम हमले का जिक्र न होने और बलूचिस्तान में हुई घटनाओं पर पाकिस्तान की चिंताओं को शामिल करने के कारण, भारत ने समझौते पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। यह कदम चीन की मध्यस्थता के प्रति भारत की अस्वीकृति और आतंकवाद से निपटने के लिए एक अधिक संतुलित दृष्टिकोण की मांग को दर्शाता है।

इस मुद्दे में चीन की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण रही है। पहलगाम हमले की 'तटस्थ जांच' की वकालत करके, चीन ने स्पष्ट रूप से भारत की संवेदनशीलता को चुनौती दी और बलूचिस्तान का उल्लेख करके अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान का समर्थन किया। यह सुझाव देता है कि चीन एससीओ मंच का उपयोग भारत के रणनीतिक हितों का मुकाबला करने और पाकिस्तान को कूटनीतिक कवर प्रदान करने के लिए कर रहा है।

जबकि कुछ राजनीतिक विश्लेषकों और विपक्षी दलों ने भारत के रुख को 'कूटनीतिक विफलता' के रूप में चित्रित किया है, यह वास्तव में एक सैद्धांतिक और रणनीतिक दृढ़ता है। भारत ने प्रभावी रूप से यह स्पष्ट कर दिया है कि

वह अब 'सहमति' के नाम पर आतंकवाद जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर समझौता नहीं करेगा।

2017 में एससीओ में शामिल होने के बाद, भारत अब केवल एक प्रतीकात्मक भागीदार नहीं है, बल्कि संगठन के नीति-निर्माण में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का स्पष्टवादी रुख संगठन के भीतर एक नैतिक नेतृत्वकर्ता के रूप में इसकी स्थिति को मजबूत करता है।

चीन का उद्देश्य एससीओ के माध्यम से मध्य एशिया, दक्षिण एशिया और रूस के बीच एक वैकल्पिक सुरक्षा ढांचा स्थापित करना है, जो पश्चिमी गठबंधनों का मुकाबला करता है। हालांकि, यह सामंजस्य तभी संभव है जब चीन पारदर्शिता और निष्पक्षता का प्रदर्शन करे, एक पहलू जो अभी तक स्पष्ट नहीं है, खासकर भारत जैसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र विदेश नीति सिद्धांतों वाले देशों के साथ।

बलूचिस्तान का संदर्भ और पहलगाम को छोड़ना यह स्पष्ट संकेत है कि चीन पाकिस्तान की विदेश नीति संबंधी चिंताओं को एससीओ के भीतर अनावश्यक प्राथमिकता दे रहा है। इस दृष्टिकोण से न केवल भारत के साथ तनाव बढ़ने की संभावना है बल्कि एससीओ की विश्वसनीयता और उद्देश्यों पर भी सवाल उठते हैं।

भारत की विदेश और रक्षा नीति अब पहले से कहीं अधिक स्पष्ट, आत्मविश्वासपूर्ण और सक्रिय है। आतंकवाद पर भारत का रुख स्पष्ट हैः कोई समझौता नहीं, कोई चुप्पी नहीं। एससीओ जैसे मंचों पर, भारत केवल प्रतीकात्मक भागीदार नहीं बनना चाहता है, बल्कि महत्वपूर्ण मामलों पर प्रभावशाली भागीदारी चाहता है।

यह घटना इस बात पर भी प्रकाश डालती है कि भारत वैश्विक मंचों पर अपनी सुरक्षा चिंताओं को लेकर अधिक मुखर होने को तैयार है, भले ही इसका परिणाम असहज कूटनीतिक टकराव क्यों न हो। यह दृष्टिकोण 'मूल्य-आधारित विदेश नीति' और 'रणनीतिक स्वायत्तता' का प्रतीक है, जो आने वाले वर्षों में भारत को एक मजबूत वैश्विक खिलाड़ी के रूप में आकार देगा।

srirajesh.journalist @srirajesh editor@cultcurrent.com

आकाशगामी भारत

विज्ञान, शक्ति व संकल्प की कहानी

शुभांशु शुक्ला का ऐतिहासिक अंतरिक्ष मिशन भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक निर्णायक मोड़ है — जो वैज्ञानिक प्रतिभा, तकनीकी नवाचार और वैश्विक महत्वाकांक्षा का प्रतीक बनकर उभरा है। यह मिशन न केवल भारत को अंतरिक्ष अभियानों में अग्रणी देशों की श्रेणी में और ऊपर ले जाता है, बल्कि भावी अंतरग्रहीय अन्वेषण के द्वार भी खोलता है। राष्ट्रीय गर्व और युवाओं के लिए प्रेरणा का यह प्रतीकात्मक मिशन भारत की अंतरिक्ष शक्ति को नई ऊँचाइयों तक ले जाने वाला कदम है।

शुभांशु शुक्ला का अंतरिक्ष मिशन भारतीय अंतरिक्ष महत्वाकांक्षा के लिए एक युगांतरकारी कदम है, जिसने वैज्ञानिक, तकनीकी और रणनीतिक क्षेत्रों में भारत की छवि को वैश्विक मंच पर मजबूती से स्थापित किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने पहले भी कई मील के पत्थर स्थापित किए हैं, जैसे कि मंगलयान और चंद्रयान श्रृंखला, लेकिन यह मिशन न केवल एक तकनीकी उपलब्धि है, बल्कि यह युवा वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन गया है। इस मिशन की सफलता भारत को अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में अग्रणी देशों की श्रेणी में खड़ा करती है। यह मिशन भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के समावेश का प्रतीक है। इसमें उपयोग किए गए उन्नत सेंसर, प्रोपल्शन सिस्टम और संचार तकनीक भारतीय शोधकर्ताओं की प्रतिभा और कौशल का प्रमाण हैं। उदाहरण के लिए, मिशन में उपयोग किए जाने वाले एडवांस्ड इमेजरी सेंसर्स पृथ्वी की सतह की उच्च-रिज़ॉल्यूशन तस्वीरें लेने में सक्षम हैं, जिनका उपयोग कृषि, शहरी नियोजन और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में किया जा सकता है। इसी तरह, आयन थ्रस्टर्स जैसे आधुनिक प्रोपल्शन सिस्टम मिशन को अधिक कुशलता से संचालित करने और लंबी दूरी तय करने में मदद करते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस मिशन की सफलता भविष्य में भारत को और भी महत्वाकांक्षी और जटिल अंतरिक्ष परियोजनाओं के लिए एक मजबूत तकनीकी आधार प्रदान करेगी। यह न केवल नई तकनीकी खोजों को प्रोत्साहित करेगा, बल्कि अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में भी नए अवसर पैदा करेगा, जो देश को अंतरिक्ष क्षेत्र में अधिक प्रतिस्पर्धी और आत्मनिर्भर बनाने में सहायक होगा।

शुभांशु शुक्ला के इस मिशन की सफलता ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की वैज्ञानिक प्रतिष्ठा को और भी बढ़ाया है। अंतरिक्ष अनुसंधान में अपनी जगह बनाने के लिए भारत ने हमेशा जटिल तकनीकी चुनौतियों का सामना किया है। इस मिशन ने यह साबित कर दिया है कि भारतीय वैज्ञानिक न केवल सीमित संसाधनों में भी वैश्विक मानकों को प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि नवाचार के माध्यम से अंतरिक्ष विज्ञान में अपनी अनूठी पहचान भी बना सकते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ सहयोग करके, भारत ने अपनी वैज्ञानिक क्षमताओं का प्रदर्शन किया है और वैश्विक अंतरिक्ष समुदाय में एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में उभरा है। आज के वैश्विक परिदृश्य में, जहां अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है, यह मिशन भारत के लिए न केवल गौरव का विषय है, बल्कि एक मजबूत आधार भी प्रदान करता है। यह मिशन, गगनयान जैसे आगामी मानव अंतरिक्ष मिशनों के लिए भी मार्ग प्रशस्त करता है। इस उपलब्धि का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि यह देश के युवा वैज्ञानिकों के लिए एक प्रेरणा का काम कर रही है। इस मिशन ने युवा मनों में अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति उत्साह और रुचि का संचार किया है। विश्वविद्यालयों और अनुसंधान केंद्रों में अब इस मिशन पर आधारित विशेष सेमिनार, कार्यशालाएं और चर्चाएं आयोजित की जा रही हैं। उदाहरण के लिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे संस्थानों में इस मिशन से प्रेरित होकर अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए पाठ्यक्रम और अनुसंधान परियोजनाएं शुरू की गई हैं। ये पहल न केवल नई प्रतिभाओं को सामने लाने में मदद करेंगी, बल्कि उन्हें

अंतरिक्ष अनुसंधान के उच्च मानकों को प्राप्त करने में भी सहायता करेंगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इस मिशन के बाद आने वाले वर्षों में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में अध्ययन, नवाचार और सहयोग का स्तर और भी उन्नत होगा।

आर्थिक दृष्टिकोण से भी इस मिशन का महत्वपूर्ण योगदान है। अंतरिक्ष मिशन में विकसित तकनीकी समाधान, जैसे कि सैटेलाइट लॉन्च सिस्टम, संचार प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष सामग्री, देश के उद्योगों और अनुसंधान संस्थानों के लिए नए अवसर पैदा करेंगे। इन क्षेत्रों में निवेश से न केवल रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, बल्कि वैश्विक बाजार में भी भारत का योगदान काफी बढ़ेगा। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निर्यात की संभावना भी खुलेगी, जिससे देश की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और तकनीकी आत्मनिर्भरता सुनिश्चित होगी। उदाहरण के लिए, **एंस्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसरो की वाणिज्यिक शाखा, पहले से ही विदेशी ग्राहकों को सैटेलाइट लॉन्च सेवाएं प्रदान कर रही है, और इस मिशन की सफलता से इस क्षेत्र में और अधिक अवसर मिलेंगे। सामरिक और रणनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो, यह मिशन भारत की सुरक्षा और रक्षा क्षेत्र में तकनीकी उन्नयन का एक महत्वपूर्ण कदम है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग आधुनिक समय में संचार, नेविगेशन और निगरानी प्रणालियों को मजबूत बनाने में किया जा रहा है। इस मिशन द्वारा प्राप्त अनुभव और तकनीकी आधार से रक्षा प्रणालियों के लिए भी नई सोच विकसित होगी, जिससे देश की समग्र सुरक्षा रणनीति में मजबूती आएगी। भारत की नेविगेशन सैटेलाइट प्रणाली (NavIC), जो सटीक नेविगेशन सेवाएं प्रदान करती है, इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

अंततः, शुभांशु शुक्ला के अंतरिक्ष मिशन ने भारतीय अंतरिक्ष महत्वाकांक्षा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का वादा किया है। यह मिशन न केवल तकनीकी और वैज्ञानिक उपलब्धियों का प्रतीक है, बल्कि यह देश की सामरिक, आर्थिक और शैक्षिक क्षमताओं को भी मजबूत करेगा। आज के इस महत्वाकांक्षी प्रयास से देश के भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों में एक नई ऊर्जा और प्रोत्साहन मिलेगा, जो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को विश्व के अग्रणी देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाएगा। यह मिशन भारत को एक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो न केवल देश के लिए गर्व का विषय है, बल्कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय के लिए भी प्रेरणादायक है। भविष्य में, इस मिशन के अनुभव और ज्ञान का उपयोग अंतरग्रहीय मिशनोंजैसे कि शुक्रयान और भविष्य के मंगल मिशनों में किया जा सकता है। •

> ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की **Axiom**-4 यात्रा 41 वर्षों बाद भारत की अंतरिक्ष प्रयोगशाला (**ISS**) में वापसी है। प्रमुख वैज्ञानिक प्रयोगों का नेतृत्व करते हुए उन्होंने गर्व से कहाः 'यह भारत का मानव अंतरिक्ष भविष्य है।'
>
> **हार्दिक दिलीप जाखड़िया**,
> मार्केटिंग मैनेजर, मुंबई

यह लेख युवा पत्रकार श्रेया गुप्ता, आकांक्षा शर्मा, धनीष्ठा डे और रिया गोयल के इनपुट पर आधारित है।

भारत वाणी: Axiom-4

शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा मेरे लिए गर्व और प्रेरणा का स्रोत है। एक छोटे शहर के छात्र और एयरोस्पेस प्रेमी के रूप में, मैं उन्हें साहस, अनुशासन और भारत की उभरती अंतरिक्ष आकांक्षाओं का प्रतीक मानता हूँ।

भाग्यलक्ष्मी मनोज, बी.टेक., एयरोस्पेस इंजीनियरिंग, मुंबई

शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष उड़ान मेरे लिए गर्व और भावनाओं से भरा क्षण है। वे साहस और आशा का प्रतीक बनकर ब्लैकबोर्ड से लेकर तारों तक छोटे शहरों के छात्रों के सपनों को साकार कर रहे हैं।

अर्चिस्मान बनर्जी, मुंबई

यह मिशन भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक स्वाभिमानी छलांग है - आत्मनिर्भरता को गति देता हुआ, युवाओं को प्रेरित करता हुआ और हमारी वैश्विक नेतृत्व क्षमता को सटीकता व नवाचार से सिद्ध करता हुआ।

जेइशा हालदार, प्रशिक्षु, IIST, केरल

इस सफल मिशन ने भारत की अंतरिक्ष विज्ञान में बढ़ती शक्ति, वैश्विक क्षमता और नवाचार के प्रति प्रतिबद्धता को उजागर किया है — जो अंतरराष्ट्रीय सहयोग और ग्रहीय अन्वेषण के लिए एक नई राह प्रशस्त करता है।

दिव्यज्योति साहा, खगोलभौतिकी विशेषज्ञ एवं विज़िटिंग फेलो-इंटर्न, टाटा इंस्टीच्यूट ऑफ फण्डामेंटल रिसर्च, मुंबई

Axiom-4 मिशन एक गर्वजनक और प्रेरक मील का पत्थर है। शुभांशु शुक्ला की उपलब्धि युवा इंजीनियरों को प्रेरित करती है, और वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण तथा डीप स्पेस रिसर्च में भारत की बढ़ती क्षमता का प्रतीक है

माहिर अली काज़ी, फेनमैन एयरोस्पेस इंटर्न, मुंबई

भारत का हालिया अंतरिक्ष मिशन वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति बनने की दिशा में एक निर्णायक छलांग है। एयरोस्पेस के इच्छुक युवाओं के लिए यह प्रेरणास्पद और आश्वस्तिकर संकेत है — भारत सितारों के लिए तैयार है।

समर्थ आर. कुलकर्णी, ISRO इंटर्न, मुंबई

शुभांशु शुक्ला भारत की नई पीढ़ी की अंतरिक्ष दृष्टि का प्रतिनिधित्व करते हैं — जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नवाचार और ग्रहीय महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित है। उनका योगदान **ISRO** को विश्वसनीय लॉन्चरों से लेकर पुनः उपयोगी और डीप-स्पेस तकनीकों की ओर ले जा रहा है।

रंजय धर, वरिष्ठ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बेंगलुरु

राकेश शर्मा के 'सारे जहाँ से अच्छा' से लेकर शुभांशु शुक्ला के 'क्या कमाल की राइड थी' तक — भारत 41 वर्षों बाद अंतरिक्ष में लौटा है, और यह अन्वेषण और गर्व के एक नए युग की शुरुआत है।

सुमल्य डे, सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारी, हैदराबाद

भारत की रणनीतिक हकीकत

स्वायत्तता, समावेश एवं वैश्विक उत्तरदायित्व का संतुलन

Ashley J. Tellis के आलेख '**India's Great-Power Delusions**' के प्रतिक्रिया में भारतीय परिप्रेक्ष्य से वास्तविक हकीकत पर विश्लेषणात्मक आलेख

श्रीराजेश

अक्सर पश्चिमी विश्लेषक भारत की महाशक्ति बनने की संभावनाओं पर पूर्वाग्रह पूर्ण मानसिकता के साथ लिखते हैं, जैसे भारत का भविष्य पूरी तरह से पश्चिमी समर्थन पर निर्भर हो। वे या तो भारत की अत्यधिक प्रशंसा करते हैं या फिर इस धारणा को बढ़ावा देते हैं कि भारत बिना पश्चिमी मदद के आगे नहीं बढ़ सकता। Ashley J. Tellis का आलेख 'India's Great-Power Delusions' भी इसी पूर्वाग्रह का शिकार है, जिसमें भारत की वैश्विक स्थिति, रणनीतिक प्राथमिकताओं और आंतरिक राजनीति को संकीर्ण पश्चिमी नजरिए से देखा गया है। यह लेख इसी एकतरफा आलोचना का संतुलित, और तथ्यों पर आधारित उत्तर है, जो भारत की विदेश नीति की जटिलताओं, लोकतांत्रिक विविधता और आर्थिक विकास की जमीनी हकीकत को सामने रखते हुए एक मजबूत विकल्प प्रस्तुत करता है। हम दिखाएंगे कि भारत की रणनीतिक स्वायत्तता भ्रम नहीं, बल्कि एक सुविचारित नीति है, और भारत की

जब कोई देश अपने लक्ष्यों की ओर दृढ़ता से बढ़ता है, तो आलोचनाओं की बौछार होना स्वाभाविक है। वैश्विक मामलों की प्रतिष्ठित पत्रिका 'फॉरेन अफेयर्स' में 17 जून, 2025 को प्रकाशित एश्ले जे. टेलिस का आलेख '**India's Great-Power Delusions**' भी इसी कड़ी का हिस्सा है। यह आलेख भारत की वैश्विक शक्ति बनने की आकांक्षाओं पर प्रश्नचिह्न लगाता है और उसकी रणनीतिक नीतियों को भ्रमपूर्ण बताता है। लेकिन क्या टेलिस का यह विश्लेषण जमीनी हकीकत से मेल खाता है? क्या भारत वास्तव में अपनी 'रणनीतिक स्वायत्तता' के कारण महाशक्ति बनने से वंचित रह जाएगा? क्या भारत का लोकतांत्रिक ढांचा इतना कमजोर है कि वह वैश्विक नेतृत्व की जिम्मेदारी नहीं निभा पाएगा? यह जवाबी आलेख इन सभी सवालों का तथ्यात्मक और तार्किक जवाब देता है, और यह दर्शाता है कि भारत न तो भ्रमित है, और न ही कमजोर। यह आलेख एक नए भारत की कहानी कहता है - एक ऐसा भारत जो अपनी शर्तों पर, अपने मूल्यों के साथ और अपने तरीके से वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बना रहा है। यह आलेख भारत की रणनीतिक हकीकत को समझने का एक प्रयास है, जो पश्चिमी विश्लेषकों के पूर्वाग्रहों से मुक्त है।

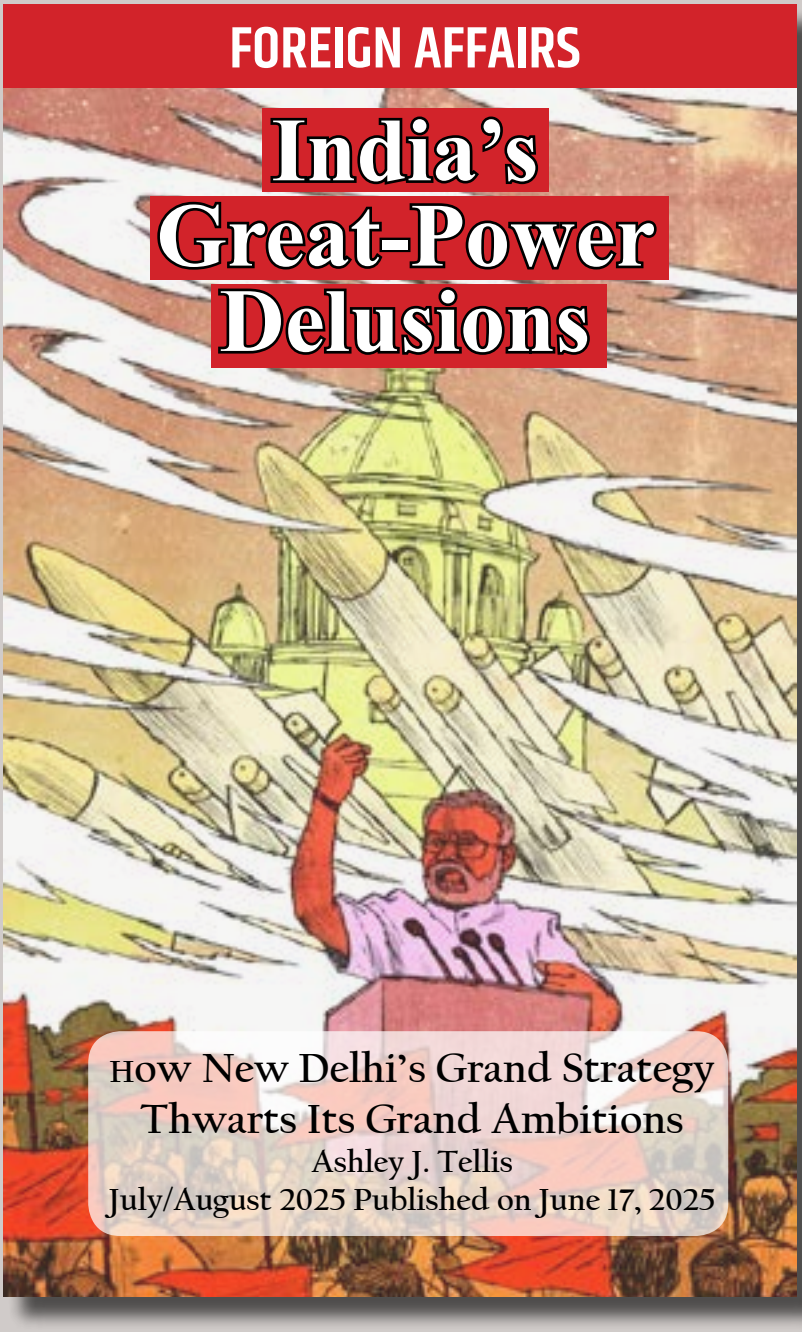

लोकतांत्रिक प्रक्रिया कमजोर नहीं, बल्कि जीवंत है।

भारत की रणनीतिक स्वायत्तता: दूरदर्शिता, न कि भ्रम

टेलिस का मानना है कि भारत का गुटनिरपेक्ष रवैया उसकी वैश्विक शक्ति बनने की राह में रोड़ा है, लेकिन यह विश्लेषण भारत की विदेश नीति की ऐतिहासिक समझ और आज के जटिल वैश्विक परिदृश्य की वास्तविकता को अनदेखा करता है। 'अपने पैर पर खड़ा होना' - भारत की 'रणनीतिक स्वायत्तता' सिर्फ अतीत का बोझ नहीं, बल्कि आज के बहुध्रुवीय और अनिश्चित विश्व व्यवस्था में लचीलेपन की कुंजी है। यह भारत को बिना किसी पूर्व प्रतिबद्धता के विभिन्न हितधारकों के साथ संवाद करने की स्वतंत्रता देता है। 2023 के बाद भारत ने रूस के साथ अपने रक्षा संबंधों को बनाए रखते हुए अमेरिका, फ्रांस और इजराइल के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत किया है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत किसी भी देश के साथ अपने संबंधों को किसी तीसरे देश के चश्मे से नहीं देखता, जो भारत की रणनीतिक स्वायत्तता का स्पष्ट प्रमाण है। 'सांप

भी मरे, और लाठी भी ना टूटे' - भारत ने यह साबित कर दिया है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दे सकता है।

यह सिर्फ शक्ति संतुलन का खेल नहीं है, बल्कि एक विवेकपूर्ण बहुपक्षीय कूटनीति का प्रदर्शन है। यह नीति न केवल चीन को संतुलित करने तक सीमित है, बल्कि भारत को एक 'सेतु राष्ट्र' बनने की क्षमता भी देती है - जो वैश्विक उत्तर और दक्षिण, पूरब और पश्चिम के बीच पुल का काम कर सकता है। Carnegie India के एक अध्ययन के अनुसार, भारत की रणनीतिक स्वायत्तता उसे विभिन्न वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाती है, चाहे वह जलवायु परिवर्तन हो, आतंकवाद हो, या महामारी हो।

आर्थिक परिपक्वता: गति के साथ समावेश का मॉडल:

टेलिस भारत की आर्थिक प्रगति को चीन की तुलना में धीमी बताकर उसे एक अपूर्ण महाशक्ति साबित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उन्होंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया कि भारत की विकास रणनीति समावेशिता, लोकतांत्रिक संरचना और स्थिरता पर आधारित है। 'सबका साथ, सबका विकास' - भारत का आर्थिक विकास एक सतत प्रक्रिया है, जो सभी नागरिकों को लाभान्वित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस संदर्भ में, IMF के 2024 के अनुमानों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है, जो दर्शाते हैं कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और 2027 तक जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ते हुए तीसरे स्थान पर पहुंचने की संभावना है। वर्तमान में यह चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है, जो कि हकीकत है। यह दर्शाता है कि भारत एक मजबूत और तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जिसमें वैश्विक विकास का इंजन बनने की क्षमता है। इसी तरह, विश्व बैंक के अनुसार, भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) - Aadhaar, UPI, CoWIN, ONDC - विकासशील देशों के लिए एक अनुकरणीय मॉडल है। NITI Aayog की एक हालिया रिपोर्ट में यह बताया गया है कि DPI ने भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया है, भ्रष्टाचार को कम किया है, और सरकारी सेवाओं की दक्षता में सुधार किया है। इससे स्पष्ट होता है कि भारत नवाचार और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके अपने नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इतना ही नहीं, भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम दुनिया में तीसरे स्थान पर है, जिसमें 100 से अधिक यूनिकॉर्न शामिल हैं। Brookings के एक अध्ययन में पाया गया है कि भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम नवाचार और रोजगार सृजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, और यह देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है।

इसके विपरीत, चीन की विकास रणनीति भारी ऋण, निर्माण पर अधिक निर्भरता और सीमित पारदर्शिता पर आधारित रही है। 'लालच बुरी बला है' - चीन की तेज आर्थिक वृद्धि का एक बड़ा कारण उसका अधिनायकवादी रवैया भी है, जो लंबे समय में टिकाऊ नहीं

है। Bloomberg के अनुसार, चीन का ऋण-से-जीडीपी अनुपात 300% से अधिक है, जो एक गंभीर चिंता का विषय है। भारत की आर्थिक संरचना भले धीमी हो, लेकिन यह सशक्त, स्थायी और लोकतांत्रिक भागीदारी पर आधारित है।

लोकतंत्र और विविधता: एक जीवंत प्रणाली, सुधार की गुंजाइश के साथ:

टेलिस का यह आरोप कि भारत अब एक उदार लोकतंत्र नहीं रह गया है, एक सरलीकृत निष्कर्ष है। 'धीरे-धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय' - यह सच है कि भारत में राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ा है और कुछ संस्थानों पर दबाव भी है, लेकिन इससे भारत की लोकतांत्रिक जड़ें कमजोर नहीं हुई हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिला और उसे गठबंधन सरकार बनानी पड़ी, यह लोकतंत्र की जीवंतता का प्रमाण है, न कि उसकी मृत्यु का। 'जनता जनार्दन होती है' - भारतीय मतदाताओं ने यह दिखा दिया कि वे किसी भी पार्टी को असीमित शक्ति नहीं देने के लिए तैयार हैं, और वे विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं को प्रतिनिधित्व देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत की न्यायपालिका, चुनाव आयोग और स्वतंत्र मीडिया - चाहे दबाव में हों - फिर भी सक्रिय बने हुए हैं। ये संस्थान लोकतंत्र के स्तंभ हैं और वे सत्ता के दुरुपयोग को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत की न्यायपालिका ने हाल के वर्षों में सरकार के कई फैसलों को चुनौती दी है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की है। इतना ही नहीं, विपक्षी दल 10 राज्यों में सत्ता में हैं, जो संघवाद की शक्ति को दर्शाता है और यह दिखाता है कि भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण है और विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं को प्रतिनिधित्व मिलता है।

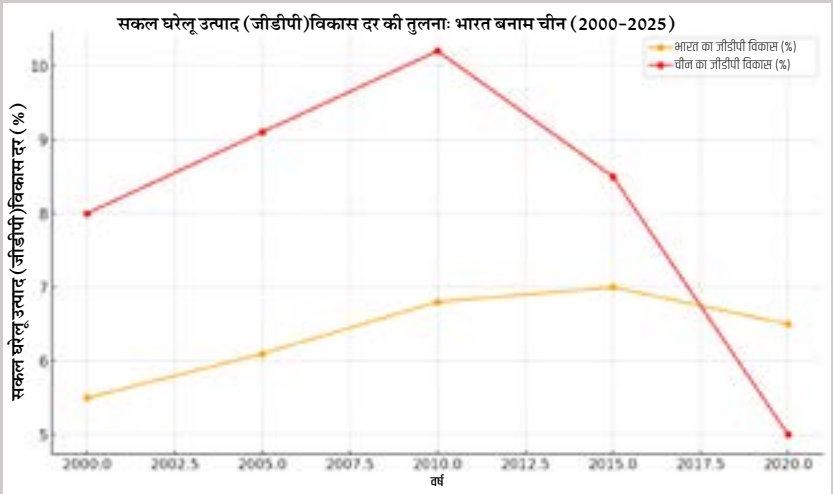

हालांकि, भारत में मानवाधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता के हनन की कुछ घटनाएं चिंताजनक हैं, और इन मुद्दों को संबोधित करने की आवश्यकता है। जैसा कि 'पहले अपने घर को व्यवस्थित करो' कहा जाता है, भारत को अपनी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और मानवाधिकारों के संरक्षण को और मजबूत करना चाहिए। Brookings India के अनुसार, भारत में नागरिक समाज और स्वतंत्र मीडिया को और अधिक सशक्त बनाने की आवश्यकता है, ताकि वे सरकार पर निगरानी रख सकें और जवाबदेही सुनिश्चित कर सकें।

भारत का लोकतंत्र आसान नहीं है, यह संघर्षों से भरा है। यह विविधता से भरा हुआ है, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है। भारत के मतदाता सत्ताधारी दलों को बदलते हैं, नीतियों पर दबाव बनाते हैं, और सांप्रदायिकता के खिलाफ भी प्रतिक्रिया देते हैं। 'विविधता में एकता, भारत की विशेषता' - यही भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव है, और यह भविष्य में भी बनी रहेगी।

वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका: भागीदार, न कि अनुगामी

टेलिस भारत की वैश्विक भूमिका को सीमित बताकर यह भूल जाते हैं कि हाल के वर्षों में भारत ने खुद को एक जिम्मेदार वैश्विक खिलाड़ी के रूप में कैसे स्थापित किया है। 'कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन' - भारत फल की चिंता किए बिना वैश्विक कल्याण के लिए काम करता है। भारत ने G20 की अध्यक्षता (2023) में ग्लोबल साउथ की आवाज को वैश्विक केंद्र में रखा। 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि यह भारत के वैश्विक दृष्टिकोण का प्रतीक था। इससे यह प्रदर्शित हुआ कि भारत विकासशील देशों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिबद्ध है, और वह वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इतना ही नहीं, कोविड महामारी के दौरान भारत ने वैक्सीन मैत्री के तहत 150 से अधिक देशों को टीके दिए, जबकि पश्चिमी देश अपने टीकों को लेकर संरक्षणवादी थे। यह भारत की उदारता और मानवतावादी मूल्यों का प्रमाण था। 'वसुधैव कुटुम्बकम्' - भारत ने पूरी दुनिया को एक परिवार मानकर मदद की, और यह दिखाया कि वह एक जिम्मेदार और परोपकारी वैश्विक शक्ति बनने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जलवायु न्याय, डेटा संप्रभुता और डिजिटल शासन में भारत ने नीति निर्धारण में अग्रणी भूमिका निभाई है, जो यह दर्शाता है कि भारत वैश्विक मुद्दों पर

रचनात्मक और प्रभावशाली भूमिका निभा रहा है, और वह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक महत्वपूर्ण आवाज है।

भारत न तो पूरी तरह से पश्चिम के साथ है, और न ही चीन के नेतृत्व वाले संगठनों में आत्मसात हुआ है। यह सहयोग और संतुलन के उस मध्य मार्ग पर चल रहा है, जो दुनिया को एकतरफा शक्ति से बचाकर समावेशी बहुध्रुवीयता की ओर ले जा सकता है। भारत एक ऐसा खिलाड़ी है जो अपने हितों की रक्षा करते हुए वैश्विक शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। 'संतुलन ही जीवन है' - भारत एक ऐसी वैश्विक शक्ति बनना चाहता है जो सभी के साथ सहयोग कर सके, बिना किसी के अधीन हुए।

चीन से तुलना: आकार नहीं, प्रणाली का सवाल

टेलिस बार-बार भारत की तुलना चीन से करते हैं - जीडीपी, सैन्य क्षमता और वैश्विक प्रभाव के संदर्भ में। लेकिन वे यह समझने में विफल हैं कि चीन और भारत की राजनीतिक अर्थव्यवस्थाएं मौलिक रूप से अलग हैं। 'कौवा चला हंस की चाल, अपनी

भारत अमेरिकी रणनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति में एक "जूनियर पार्टनर" बनने को तैयार नहीं है। यही इसकी रणनीतिक स्वायत्तता की असली परीक्षा है। "मित्र बनो, अनुयायी नहीं" — भारत अमेरिका के साथ आपसी सम्मान पर आधारित संबंध चाहता है, न कि अंधानुकरण पर आधारित।

भी भूल गया' - भारत को चीन की नकल करने की कोई जरूरत नहीं है, उसे अपनी ताकत और मूल्यों के आधार पर विकास करना है। चीन की अर्थव्यवस्था भारी कर्ज से जूझ रही है (Debt-to-GDP ratio ₹300%), जबकि भारत वित्तीय अनुशासन में आगे है। IMF के अनुसार, भारत ने हाल के वर्षों में अपने राजकोषीय घाटे को कम करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, और यह वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही, चीन का विकास अधिनायकवाद से प्रेरित है, जबकि भारत ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विकास और सामाजिक न्याय को साधा है, जो यह दिखाता है कि भारत विकास को लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का एक साधन मानता है, न कि केवल आर्थिक आंकड़ों को बढ़ाने का। चीन की जनसंख्या घट रही है, जबकि भारत जनसांख्यिकीय लाभांश की ओर बढ़ रहा है। UN के अनुसार, भारत की जनसंख्या 2027 में चीन से आगे निकल जाएगी, और यह दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा, जो यह दर्शाता है कि भारत

के पास युवा और गतिशील कार्यबल है जो भविष्य में आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकता है।

भारत को चीन की प्रतिलिपि नहीं बनना है, बल्कि उसे अपनी विशिष्टता के साथ एक शक्ति बनना है। 'अपनी राह खुद चुनो' - भारत को अपने मूल्यों, संस्कृति और इतिहास के आधार पर अपना भविष्य खुद बनाना है। भारत एक ऐसी महाशक्ति बनना चाहता है जो वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि में योगदान दे सके।

अमेरिका और भारत: साझेदारी, अधीनता नहीं:

टेलिस का यह तर्क कि भारत अमेरिका के साथ किसी औपचारिक गठबंधन में शामिल न होकर उसका समर्थन खो देगा, सहयोग और अधीनता के बीच के अंतर को समझने में विफल है। 'हाथ मिलाओ, पर हाथ मत बंधवाओ' - भारत अमेरिका के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन वह अपनी संप्रभुता से समझौता करने को तैयार नहीं है। भारत और अमेरिका के बीच मालाबार नौसैनिक अभ्यास, तकनीकी सहयोग (जेट इंजन हस्तांतरण, सेमीकंडक्टर), LEMOA, COMCASA जैसे रक्षा समझौते और इंडो-पैसिफिक रणनीतिक समन्वय - ये सभी इस बात के प्रमाण हैं कि भारत एक गंभीर और स्थायी भागीदार है।

लेकिन भारत अमेरिकी रणनीतिक लक्ष्यों का 'जूनियर पार्टनर' बनने के लिए तैयार नहीं है, और यही उसकी रणनीतिक स्वायत्तता की असली परीक्षा है। 'मित्र बनो, पिछलग्गू नहीं' - भारत अमेरिका के साथ दोस्ती चाहता है, लेकिन वह उसका अंधानुकरण करने को तैयार नहीं है। अमेरिका को यदि सचमुच स्वतंत्र लोकतांत्रिक शक्तियों का समर्थन करना है, तो उसे भारत की विविध और जटिल रणनीति को समझना होगा, न कि उसे पश्चिमी साँचे में ढालने की कोशिश करनी चाहिए। 'समझौता करो, पर आत्मसमर्पण नहीं' - भारत को अमेरिका के साथ सहयोग करने में फायदा है, लेकिन उसे अपनी संप्रभुता और हितों की रक्षा भी करनी है।

निष्कर्ष: भारत की राह अपनी है, भ्रमित नहीं

टेलिस के लेख का एक केंद्रीय आरोप यह है कि भारत अपनी नीतियों से खुद को ही रोक रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि भारत अपने तरीके से, अपनी जटिलताओं के साथ और अपने मूल्यों के आधार पर एक वैश्विक शक्ति बन रहा है। 'चलते-चलते राह मिलेगी' - भारत को अपनी मंजिल का पता है और वह धीरे-धीरे, लेकिन आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। यह रास्ता पश्चिमी विश्लेषकों के लिए अपरिचित हो सकता है, लेकिन यह भारत की सभ्यता-संगत, लोकतांत्रिक और बहुपक्षीय रणनीति का दर्पण है।

भारत की नीतियां आदर्श नहीं हैं, लेकिन वे अराजक भी नहीं हैं। वे जमीनी हकीकत, ऐतिहासिक स्मृति, सामाजिक विविधता और वैश्विक उतार-चढ़ावों के बीच खींची गई एक संतुलित रेखा हैं। इस मध्य मार्ग में ही भारत की शक्ति छिपी है - एक ऐसी शक्ति जो वैश्विक व्यवस्था को न केवल संतुलित कर सकती है, बल्कि उसे न्यायपूर्ण और टिकाऊ भी बना सकती है। 'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय' - भारत का लक्ष्य पूरी दुनिया के लिए कल्याण और सुख लाना है।

भारत की महानता का मापदंड न केवल उसका सकल घरेलू उत्पाद, सैन्य शक्ति या पश्चिमी अनुमोदन होगा, बल्कि इस बात से होगा कि क्या वह अपनी सार्वभौमिकता में समावेश, सह-अस्तित्व और स्वतंत्रता की भावना को आगे बढ़ा पाया या नहीं। और इस कसौटी पर भारत एक ठोस, सतत और सार्वभौमिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। 'सत्यमेव जयते' - सत्य की ही विजय होती है, और भारत अपने मूल्यों और सिद्धांतों पर अटल रहते हुए आगे बढ़ रहा है। टेलिस का आलेख भारत की क्षमता को कम आंकता है, लेकिन भारत अपनी रणनीतिक बुद्धिमत्ता, लोकतांत्रिक मूल्यों और वैश्विक प्रतिबद्धता के साथ एक समृद्ध और प्रभावशाली भविष्य की ओर अग्रसर है। यह सिर्फ एक महाशक्ति बनने की कहानी नहीं है, बल्कि एक बेहतर दुनिया बनाने की कहानी है। •

भारत-कनाडा संबंध

भरोसे की बहाली या कूटनीतिक दिखावा ?

भारत और कनाडा के बीच हालिया कूटनीतिक नरमी — जिसे नए उच्चायुक्तों की नियुक्ति के निर्णय से चिह्नित किया गया है — वर्षों से चले आ रहे तनावपूर्ण संबंधों के बीच आशा की एक नाजुक किरण प्रदान करती है। लेकिन चमकदार बयानों और कूटनीतिक मुस्कानों के पीछे खालिस्तान उग्रवाद जैसे मुद्दों से जुड़ा एक विस्फोटक क्षेत्र छिपा है। यह तथाकथित रीसेट एक खोखली रस्म बनकर रह जाएगा, यदि दोनों देश मूल मुद्दों का सामना ईमानदारी, जवाबदेही और राजनीतिक साहस के साथ नहीं करते। आखिरकार, भरोसा केवल कूटनीतिक नियुक्तियों से नहीं बनता।

संदीप कुमार

भारत और कनाडा के बीच हाल ही में नए उच्चायुक्तों की नियुक्ति ने यह संकेत दिया है कि दोनों देश अपने बिगड़े संबंधों को सुधारने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। यह नियुक्ति एक लंबे तनावपूर्ण दौर के बाद आई है, जब दोनों देशों के बीच राजनीतिक और राजनयिक संबंध लगभग ठप हो गए थे। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ प्रतिनिधि बदलने से रिश्ते सुधर सकते हैं? क्या यह बदलाव सच्चे भरोसे की ओर ले जाएगा, या यह केवल एक राजनयिक औपचारिकता बनकर रह जाएगा?

इस लेख में हम भारत-कनाडा संबंधों की जटिलताओं को सरल भाषा में समझेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि इस 'रीसेट' की सफलता किन बातों पर निर्भर करती है।

भारत-कनाडा: ऐतिहासिक रूप से मित्र लेकिन हालिया कटुता

भारत और कनाडा लंबे समय से लोकतंत्र, बहुलता, और वैश्विक मुद्दों पर सहयोग के साझेदार रहे हैं। लाखों भारतीय प्रवासी कनाडा में रहते हैं, जो दोनों देशों के बीच एक मानवीय पुल की तरह हैं। शिक्षा, व्यापार, विज्ञान और संस्कृति जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग होता रहा है।

लेकिन बीते कुछ वर्षों में यह रिश्ता तनावपूर्ण हो गया, जिसका

प्रमुख कारण खालिस्तान समर्थक गतिविधियाँ और उन पर कनाडा की प्रतिक्रिया रही है।

खालिस्तान मुद्दा: भारत की सबसे बड़ी चिंता

भारत के लिए खालिस्तान आंदोलन केवल एक वैचारिक मतभेद नहीं, बल्कि एक गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है। इस आंदोलन की जड़ें पंजाब में हैं, जहाँ कुछ तत्व एक अलग सिख राष्ट्र की माँग करते हैं। यह विचार भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को सीधी चुनौती देता है।

भारत का आरोप है कि कनाडा में रहने वाले कुछ खालिस्तान समर्थक लोग न सिर्फ भारत विरोधी बातें करते हैं, बल्कि कभी-कभी हिंसा या सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश भी करते हैं। भारत में कई ऐसे संगठनों को आतंकवादी घोषित किया गया है। भारत को यह भी लगता है कि कनाडा की सरकार ने इन तत्वों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है।

कई बार खालिस्तान समर्थकों ने कनाडा में भारतीय दूतावासों और मंदिरों पर हमले किए या विरोध प्रदर्शन किए, जिससे भारत में गुस्सा और चिंता दोनों बढ़े।

2023: जब विवाद चरम पर पहुंचा

G20 सम्मेलन के दौरान कनाडा के तत्कालीन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक गंभीर आरोप लगाया कि भारत की एजेंसियों का हाथ कनाडा में खालिस्तानी नेता हरदीपे सिंह निज्जर की हत्या में हो सकता है। यह बयान पूरी दुनिया में सुर्खियाँ बना और भारत ने इसे पूरी तरह खारिज कर दिया।

इसके बाद दोनों देशों ने एक-दूसरे के राजनयिकों को निष्कासित किया। भारत ने आरोप लगाया कि कनाडा भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है, और कनाडा ने कहा कि भारत ने उनके संप्रभु

अधिकारों का उल्लंघन किया है।

यह घटना दोनों देशों के संबंधों में एक गहरी खाई बना गई।

नए उच्चायुक्त: क्या यह वास्तव में नई शुरुआत है?

अब, जब कनाडा में नई सरकार के आने की संभावना जताई जा रही है और प्रधानमंत्री मार्क कार्नी (काल्पनिक नाम, भविष्य की परिकल्पना के अनुसार) भारत के साथ संबंध सुधारने की बात कर रहे हैं, तब उम्मीदें एक बार फिर से जगी हैं।

भारत और कनाडा ने नए उच्चायुक्तों की नियुक्ति के माध्यम से राजनयिक संबंधों को पुनर्स्थापित करने पर सहमति जताई है। यह नरमी उन वर्षों पुराने तनावों के बाद आई है, जिनका मुख्य कारण खालिस्तान अलगाववाद रहा है। भारत इसे एक गंभीर सुरक्षा खतरे के रूप में देखता है और कनाडा पर निष्क्रियता का आरोप लगाता रहा है। सार्वजनिक आरोप-प्रत्यारोप और पारस्परिक निष्कासन के चलते आपसी विश्वास गहराई से क्षतिग्रस्त हो गया था।

G7 सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कार्नी की मुलाकात, और फिर दोनों देशों द्वारा एक-दूसरे के लिए उच्चायुक्तों की नियुक्ति इस दिशा में अहम कदम हैं।

इससे यह संकेत मिलता है कि दोनों देश अब फिर से संवाद और सहयोग की दिशा में जाना चाहते हैं। लेकिन सिर्फ प्रतिनिधि भेजने से समस्याएँ खत्म नहीं होतीं। असली सवाल यह है कि क्या दोनों पक्ष अपनी-अपनी चिंताओं को समझने और समाधान निकालने के लिए ईमानदारी से तैयार हैं?

भारत की अपेक्षाएँ: सिर्फ बातें नहीं, काम चाहिए

भारत चाहता है कि कनाडा खालिस्तान समर्थकों पर कठोर कार्रवाई करे, खासकर तब जब वे खुलेआम भारत-विरोधी नारों, हिंसक प्रदर्शनों या सांप्रदायिक नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं।

भारत को यह भी चिंता है कि कनाडा में कुछ नेता सिख समुदाय के वोट बैंक को खुश करने के लिए इस तरह के तत्वों पर नरमी बरतते हैं। भारत का यह भी मानना है कि आपसी संबंधों को मज़बूत करने के लिए कनाडा को दिखाना होगा कि वह सिर्फ लोकतांत्रिक आज़ादी की दुहाई नहीं दे रहा, बल्कि उन आज़ादियों के दुरुपयोग को भी रोकने के लिए गंभीर है।

विश्वास बहाली के 4 ज़रूरी कदम

1. सुरक्षा चिंताओं को प्राथमिकता:

कनाडा को भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को हल्के में नहीं लेना चाहिए। यह जरूरी है कि वह चरमपंथियों के लिए सुरक्षित ठिकाना न बने।

2. बंद कमरे में संवाद:

सार्वजनिक बयानबाज़ी और मीडिया में आरोप-प्रत्यारोप से बचा जाना चाहिए। गंभीर मुद्दों को निजी और कूटनीतिक बातचीत से हल किया जाना ज़्यादा असरदार होता है।

3. संप्रभुता का पारस्परिक सम्मान:

दोनों देशों को एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देना चाहिए और अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन करते हुए एक-दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए।

4. आर्थिक और शैक्षिक सहयोग:

भारत और कनाडा व्यापार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी और आप्रवासन जैसे क्षेत्रों में एक-दूसरे के बड़े साझेदार हो सकते हैं। इन क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने से आपसी समझ और विश्वास भी गहराएगा।

निष्कर्ष: भरोसा काम से बनता है, बातों से नहीं

भारत और कनाडा दोनों ही लोकतांत्रिक देश हैं और उनकी साझेदारी ऐतिहासिक रूप से मज़बूत रही है। लेकिन रिश्तों की बहाली सिर्फ अच्छी नीयत या राजनयिक औपचारिकताओं से नहीं होगी। इसके लिए ठोस कदम, पारदर्शिता और आपसी संवेदनशीलता ज़रूरी हैं।

भारत के लिए खालिस्तान सिर्फ एक मतभेद नहीं, एक राष्ट्रीय सुरक्षा संकट है। जब तक कनाडा इसे गंभीरता से नहीं लेता और केवल 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' की आड़ में इन गतिविधियों को नज़रअंदाज़ करता रहेगा, तब तक भरोसे की असली बहाली नहीं होगी।

यह रिश्ता तभी सुधरेगा जब दोनों देश यह समझें कि कूटनीति केवल शब्दों का खेल नहीं, बल्कि जिम्मेदारियों का संतुलन है। •

Tea
Your Tagline Here

Fresh Drink

LEMON TEA

The Wonderful Taste Of Life

Order Now

www.lemonteaindia.in

संजय श्रीवास्तव

ट्रंपाघात

अग्रणी है अमेरिका, या हार रहा मैदान?

वैश्विक लोकतंत्र और नेतृत्व का प्रतीक रहा अमेरिका आज भीतर से बिखरा हुआ है और अंतरराष्ट्रीय मंच पर लगातार प्रभावहीन होता जा रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में वे नीतियाँ, जिन्हें कभी 'साहसिक' कहा गया था, अब अव्यवस्थित, आत्ममुग्ध और ख़तरनाक मानी जाने लगी हैं। बिखरती कूटनीतिक साझेदारियाँ, भीतरी ध्रुवीकरण और नीतिगत अस्थिरता ने अमेरिका की वैश्विक साख को गहरा आघात पहुँचाया है। ऐसे समय में, जब विश्व एक नए शक्ति-संतुलन की ओर अग्रसर है, यह प्रश्न और भी तीव्र होकर उभरता है:

क्या ट्रंप अमेरिका को एक नई दिशा की ओर ले जा रहे हैं — या उसे पतन की कगार पर धकेल रहे हैं?

क्या वे शांति और सह-अस्तित्व की दुनिया की नींव रख रहे हैं — या एक विध्वंसकारी व्यवस्था की पटकथा लिख रहे हैं?

आवरण कथा के अंतर्गत सभी स्टोरीज हेतु शोध और लेखन **संजय श्रीवास्तव** के नेतृत्व में कल्ट करंट टीम द्वारा किया गया है।

डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा कार्यकाल, एक व्यक्ति की सत्ता में वापसी मात्र नहीं, बल्कि लोकतंत्र, बहुपक्षीयता और अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के प्रति बढ़ते अविश्वास का घिनौना प्रतीक है। अमानवीय प्रवासी नीतियां, सैन्य कूटनीति में अंधाधुंध फैसले, और वैश्विक गठबंधनों में गहरी होती अनिश्चितता - ये सब चीख-चीखकर कह रहे हैं कि अमेरिका अब 'विश्व का नैतिक प्रहरी' नहीं, बल्कि एक स्वार्थी और आत्ममुग्ध शक्ति बनकर रह गया है। ये वो अमेरिका है, जो वैश्विक मंच पर अपनी दादागिरी चलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे इसका अंजाम पूरी दुनिया को भुगतना पड़े।

लेकिन, इतिहास कभी भी अंतिम नहीं होता। 'जब तक सांस, तब तक आस' - उम्मीद अभी भी बाकी है! अगर अमेरिकी संस्थाएं, नागरिक समाज और वैश्विक समुदाय एकजुट होकर ट्रम्प के एकतरफा और विनाशकारी फैसलों का डटकर मुकाबला करें, तो यह कार्यकाल इतिहास में एक चेतावनी बनकर दर्ज हो सकता है, न कि एक ऐसी स्थायी लकीर, जिसे मिटाना नामुमकिन हो। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका इस 'ट्रंपाघात' से उबरकर फिर से भरोसेमंद नेतृत्व की ओर लौटेगा, या आने वाली पीढ़ियां इसे उस काले युग के रूप में याद रखेंगी, जब लोकतंत्र, नैतिकता और अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारी की नींव पूरी तरह से चरमरा गई थी?

22 जून, 2025 की रात। 'आधी रात का हथौड़ा' - कुछ इसी अंदाज में अमेरिका ने 'ऑपरेशन मिडनाइट हैमर' चलाया। इस ऑपरेशन के तहत, अमेरिकी बमवर्षकों और क्रूज मिसाइलों ने ईरान के तीन सबसे महत्वपूर्ण परमाणु स्थलों - फ़ोर्दो, नतांज और इस्फ़हान - को पल भर में धूल में मिला दिया। इस हवाई हमले ने पूरे मध्य-पूर्व को फिर से युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। अमेरिका ने हमेशा की तरह यह दावा किया कि ईरान 'परमाणु हथियार बनाने के अंतिम चरण' में है, और यह हमला 'निवारक सैन्य रणनीति' का हिस्सा है। लेकिन, अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने इसे सरासर मूर्खता, जानबूझकर उकसावे और एकतरफा आक्रमण करार दिया।

ईरान ने इस हमले को 'युद्ध की खुली घोषणा' मानते हुए बदले की आग में जलने की कसम खाई। इसके बाद, खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी

ठिकानों, इजराइल और सऊदी गठबंधन पर हमलों का खतरा मंडराने लगा। ईरान समर्थित आतंकी संगठन - हिजबुल्लाह, हूती विद्रोही और इराकी शिया मिलिशिया - सबने मिलकर क्षेत्रीय अस्थिरता को और भी गहरा कर दिया। 'तेल में आग लगाना' - कुछ ऐसा ही कर दिखाया है अमेरिका ने, जिसके परिणाम न केवल मध्य-पूर्व, बल्कि पूरी दुनिया को भुगतने पड़ेंगे।

रूस और चीन ने हमेशा की तरह अमेरिका के इस कदम को अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया और उसकी कड़ी निंदा की। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि ट्रम्प का अमेरिका, रणनीतिक संयम से कहीं ज्यादा तात्कालिक शक्ति प्रदर्शन पर भरोसा करता है। यह ऐसी नीति है, जो वैश्विक शांति के लिए एक गंभीर खतरा बन सकती है। 'बिन पेंदी का लोटा' - कुछ ऐसा ही

हाल अमेरिका की विदेश नीति का हो गया है, जो हर बार अपने ही फैसलों से पलट जाती है।

यह हमला न केवल पश्चिम एशिया को झकझोरता है, बल्कि वैश्विक तेल आपूर्ति, ऊर्जा सुरक्षा और राजनीतिक संतुलन को भी तहस-नहस कर देता है। 'आ बैल मुझे मार' - यह कहावत इस स्थिति पर बिल्कुल सटीक बैठती है, जहाँ एक महाशक्ति

ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत से ही उनकी नीतियों की चौतरफा आलोचना हो रही है। उनके कुछ फैसलों ने वैश्विक स्थिरता, पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य को लेकर गंभीर चिंताएँ खड़ी कर दी हैं। विशेष रूप से, अमेरिका को पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकालने का उनका निर्णय दुनिया भर के पर्यावरण विशेषज्ञों द्वारा जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध वैश्विक प्रयासों को एक करारा झटका बताया गया। यह कदम न केवल अमेरिका की जिम्मेदारियों से पीछे हटने का संकेत था, बल्कि इससे अंतरराष्ट्रीय सहयोग की भावना को भी गहरा नुकसान पहुँचा।

जानबूझकर खुद को युद्ध के दलदल में धकेल रही है, यह जानते हुए भी कि इसके परिणाम पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी हो सकते हैं। अमेरिका, एक ऐसे पागल हाथी की तरह बर्ताव कर रहा है, जो अपने ही वजन से कुचलने को तैयार है।

और यह वही ट्रम्प हैं, जो अपनी चुनावी रैलियों में गरजते थे कि वे सत्ता में आने के बाद रूस-यूक्रेन युद्ध को 24 घंटे में खत्म करवा देंगे! जो भारत-पाकिस्तान के बीच संघर्ष को रोकने का झूठा श्रेय लेते रहे हैं और खुद को शांति का मसीहा साबित करने के लिए बेताब रहते थे! 'थोथा चना बाजे घना' - ट्रम्प के ये दावे खोखले वादों से ज्यादा कुछ नहीं हैं, जो सिर्फ दिखावे के लिए किए जाते हैं। उनकी दिली ख्वाहिश तो हमेशा से ही नोबेल शांति पुरस्कार पाने की रही है, ताकि वे खुद को वैश्विक शांति का अगुआ बता सकें। लेकिन, सच्चाई यह है कि ट्रम्प की नीतियां शांति से कहीं ज्यादा अशांति को बढ़ावा देती हैं।

नोबेल शांति पुरस्कार के प्रति ट्रम्प की ललक, उनके संकीर्ण दृष्टिकोण और ढुलमुल नेतृत्व शैली को उजागर करती है। यह पुरस्कार, जो दुनिया भर में शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने वाले लोगों को दिया जाता है, ट्रम्प के हाथों में एक तमाशा बनकर रह गया है। उनका यह दावा कि उन्हें यह पुरस्कार तीन बार मिलना चाहिए था, न केवल अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की निष्पक्षता पर सवाल उठाता है, बल्कि वैश्विक संस्थानों के प्रति उनके मन में पल रहे अविश्वास को भी दर्शाता है। 'अपनी करनी, ना भरे तो क्या करे' - ट्रम्प को यह समझना होगा कि शांति पुरस्कार जीतने के लिए सिर्फ खोखले वादे नहीं, बल्कि ठोस काम करने पड़ते हैं।

नोबेल समिति को 'भ्रष्ट' और 'वामपंथी झुकाव वाली' संस्था कहकर, ट्रम्प ने कूटनीति की सारी हदें पार कर दी हैं। एक वैश्विक नेता से यह उम्मीद की जाती है कि वह अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का सम्मान करे, खासकर उन संस्थाओं का, जो वैश्विक शांति, सहयोग और न्याय को बढ़ावा देने के लिए स्थापित की गई हैं। 'ऊंची दुकान, फीका पकवान' - ट्रम्प की यह आलोचना दिखावे से भरी है, क्योंकि वे खुद ही अंतरराष्ट्रीय कानूनों और समझौतों का उल्लंघन करते रहे हैं।

ट्रम्प ने उत्तर कोरिया के साथ वार्ता, इजरायल-अरब समझौते और भारत-पाकिस्तान युद्धविराम जैसी कुछ सफलताओं का हवाला दिया है, लेकिन इन प्रयासों की स्थिरता और व्यापक वैश्विक संदर्भ में सीमाएं भी स्पष्ट हैं। विश्लेषकों का मानना है कि इनमें से कई पहलें एकतरफा, अपारदर्शी और दीर्घकालिक समाधान के बजाय तात्कालिक राजनीतिक लाभ से प्रेरित थीं। 'रात गई, बात गई' - ट्रम्प के ये समझौते दिखावटी थे, जिनका मकसद सिर्फ अपनी छवि चमकाना था, न कि स्थायी शांति स्थापित करना।

ट्रम्प की विदेश नीति 'अमेरिका फर्स्ट' के नारे के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसे उनके समर्थक एक साहसिक और राष्ट्रहित में उठाया गया कदम मानते हैं। लेकिन, यही नीति अंतरराष्ट्रीय मंच पर अमेरिकी नेतृत्व की भूमिका को संकुचित कर देती है। 'अपने मुंह मियां मिट्ठू' - ट्रम्प खुद अपनी नीतियों की तारीफ करते नहीं थकते, लेकिन सच्चाई यह है कि उनकी नीतियां अमेरिका को दुनिया से अलग-थलग कर रही हैं।

ट्रम्प के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत से ही उनकी नीतियां हर तरफ से आलोचना का शिकार हो रही हैं। उनके कुछ फैसले वैश्विक स्थिरता, पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए गंभीर चिंता का कारण बने हैं। ट्रम्प का पेरिस समझौते से अमेरिका को बाहर निकालना एक ऐसा फैसला था, जिसे कई विशेषज्ञों ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक प्रयासों के लिए एक बड़ा झटका बताया। 'चिराग तले अंधेरा' - यह कहावत ट्रम्प की पर्यावरण नीति पर सटीक बैठती है, क्योंकि वे अपने देश में पर्यावरण की रक्षा करने के बजाय वैश्विक जलवायु संकट को और बढ़ा रहे हैं।

कुल मिलाकर, ट्रम्प का दूसरा कार्यकाल 'ट्रंपाघात' साबित हो रहा है। उनकी नीतियां न केवल वैश्विक स्तर पर अशांति फैला रही हैं, बल्कि घरेलू मोर्चे पर भी कई समस्याएं खड़ी कर रही हैं। ऐसे में, यह देखना होगा कि दुनिया इस 'ट्रंपाघात' से कैसे निपटती है और एक शांतिपूर्ण और स्थिर भविष्य की ओर कैसे बढ़ती है।

संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) और अन्य वैश्विक संस्थानों से ट्रम्प प्रशासन की दूरी, एक गहरे जख्म की तरह है, जो अमेरिका के ऐतिहासिक अंतरराष्ट्रीय जुड़ाव के विरुद्ध है। 'गंगा उलटी बहना' - कुछ ऐसा ही हो रहा है, जहाँ अमेरिका, वैश्विक सहयोग के पथ से भटककर अलगाववाद की राह पर चल पड़ा है। यह सिर्फ दूरी नहीं, बल्कि उस भरोसे का टूटना है, जो दुनिया ने अमेरिका पर जताया था।

रूस को फिर से G8 में शामिल करने की ट्रम्प की वकालत और मैक्रॉन जैसे नेताओं पर की गई अभद्र टिप्पणियां, कूटनीतिक संवाद की मर्यादा को तार-तार कर देती हैं। यह 'मुंह में राम, बगल में छुरी' वाली नीति है, जहां दिखावे के लिए तो मित्रता की बात की जाती है, लेकिन असलियत में कूटनीति का गला घोंटा जा रहा है। सम्मेलनों में संयुक्त घोषणाओं से परहेज करना, वैश्विक सहयोग के लिए एक ऐसी दीवार खड़ी कर देता है, जिसे पार करना मुश्किल है।

ट्रम्प ने अपने दूसरे कार्यकाल में आक्रामक तरीके से टैरिफ युद्ध

छेड़ दिया। यह युद्ध, हालाँकि किसी नतीजे पर नहीं पहुँचा, लेकिन इसने वैश्विक व्यापार में ज़हर घोल दिया। 'ऊंट किस करवट बैठेगा' - यह कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि चीन, भारत और कनाडा जैसे साझेदारों के साथ अमेरिका के व्यापारिक संबंध अब पहले जैसे नहीं रहे। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर इसका क्या असर होगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा।

ग्रीनलैंड, पनामा नहर और गाजा पर ट्रम्प के बेतुके बयान, न केवल अवास्तविक थे, बल्कि उन्होंने अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के सारे कायदे-कानून ताक पर रख दिए। इन बयानों से अमेरिका के रणनीतिक दृष्टिकोण की विश्वसनीयता को गहरा धक्का लगा। 'बंदर के हाथ में उस्तरा' - कुछ ऐसा ही हो रहा है, जहाँ ट्रम्प के हाथों में सत्ता आकर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का मज़ाक बन रही है।

दूसरे देशों को प्रेस की स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाने वाला अमेरिका खुद मीडिया घरानों को प्रेस कॉन्फ्रेंस से प्रतिबंधित कर रहा है। यह कदम लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों को खोखला कर रहा है। 'घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने' - ट्रम्प का यह कदम हास्यास्पद है, क्योंकि वे खुद अपने देश में प्रेस की स्वतंत्रता को दबा रहे हैं, और दूसरों को नसीहत दे रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर

पर प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर अमेरिका की जो साख थी, उसे ट्रम्प ने पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया है।

ट्रम्प की नीतियाँ एक नए वैश्विक शक्ति-संतुलन की ओर इशारा कर रही हैं, जहाँ पारंपरिक सहयोगी अब अमेरिका की जगह दूसरे विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। 'बिल्ली के भाग छींका टूटा' - कुछ ऐसी ही स्थिति है, जहाँ चीन और यूरोपीय संघ जैसे देश अमेरिका की कमजोर होती पकड़ का फायदा उठाकर आगे बढ़ रहे हैं। अब अमेरिका को अपनी भूमिका को या तो नए सिरे से परिभाषित करना होगा, या फिर सीमित होकर रह जाना होगा।

ट्रम्प की विदेश नीति ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में वैश्विक नेतृत्वकर्ता की भूमिका सिर्फ राष्ट्रहित से संचालित हो सकती है, या उसे व्यापक नैतिक, कूटनीतिक और मानवतावादी मूल्यों के साथ भी जोड़ा जाना चाहिए। 'लातों के भूत बातों से नहीं मानते' - ट्रम्प को यह समझना होगा कि दुनिया सिर्फ ताकत से नहीं चलती, बल्कि नैतिकता और जिम्मेदारी भी जरूरी है।

डोनाल्ड ट्रम्प की नीतियों ने वैश्विक मंच पर जिस तरह की अस्थिरता पैदा की है, वह सिर्फ अमेरिका की आंतरिक राजनीति का मसला नहीं है, बल्कि विश्व व्यवस्था के ताने-बाने में एक गहरा छेद है। 'पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर' - ट्रम्प की यह नीति अमेरिका के लिए घातक साबित हो सकती है, क्योंकि वे दुनिया के साथ दुश्मनी मोल लेकर खुद को कमजोर कर रहे हैं। उनकी प्राथमिकताएँ सिर्फ घरेलू राजनीति को साधने और 'अमेरिका फर्स्ट' के नारे तक सीमित रहीं, जिससे अंतरराष्ट्रीय सहयोग, आपसी विश्वास और संस्थागत ढांचे को गहरी चोट पहुँची है। इस स्थिति में, अंतरराष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रियाएँ भी तीखी, स्पष्ट और बहुपक्षीय होती जा रही हैं।

ट्रम्प की नीतियों ने विश्व समुदाय को एक अजीब कशमकश में डाल दिया है - यह समझ में नहीं आ रहा कि उनके फैसलों पर हंसे या रोएं। 'जैसी करनी वैसी भरनी' - यह कहावत यहाँ बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि अमेरिका को उन नीतियों के गंभीर परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं, जो उसने खुद बनाई हैं। अब अमेरिका को अपने कर्मों का फल भुगतना ही होगा।

यूरोपीय संघ, खासकर जर्मनी और फ्रांस, ट्रम्प की नाटो के प्रति उदासीनता और G7 शिखर सम्मेलनों में उनके असहयोगी रवैये से न केवल नाराज हुए, बल्कि उन्होंने अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को और मजबूत करने का फैसला किया। 'दूध का

जला छाछ भी फूंक-फूंक कर पीता है' - यूरोपीय संघ अब अमेरिका पर आँख मूंदकर भरोसा करने को तैयार नहीं है, और अपनी सुरक्षा के लिए खुद कदम उठाने को मजबूर है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन और पेरिस जलवायु समझौते से ट्रम्प के हटने के फैसले ने अमेरिका को 'वैश्विक असहयोगी' के रूप में पेश कर दिया है। अब अमेरिका दुनिया के सामने एक ऐसे देश के रूप में आ गया है, जो सहयोग करने को तैयार नहीं है। पर्यावरण विशेषज्ञों ने ट्रम्प को 'पर्यावरण का विध्वंसक' तक कह डाला। 'घर जला तमाशा देखा' - ट्रम्प दुनिया को जलता हुआ देखकर तमाशा देख रहे हैं, उन्हें पर्यावरण की कोई परवाह नहीं है।

ट्रेड नीति के मोर्चे पर, चीन, भारत और यूरोपीय संघ के साथ आर्थिक टकराव, टैरिफ युद्ध और मुद्रा विवादों ने अमेरिका के व्यापारिक सहयोगियों को डरा दिया। 'जिस थाली में खाना, उसी में छेद करना' - ट्रम्प अपने व्यापारिक सहयोगियों के साथ दुश्मनी करके अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। भारत जैसे देशों को न केवल आर्थिक, बल्कि रणनीतिक मोर्चे पर भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि अमेरिका की नीति कभी भी स्थिर नहीं रही।

कुल मिलाकर, इन सभी प्रतिक्रियाओं से यह साफ हो गया है कि अमेरिका के दोस्त अब उसे विश्व नेता के रूप में नहीं, बल्कि एक 'अस्थिर साझेदार' के रूप में देखने लगे हैं। ट्रम्प की वाणी और व्यवहार में जो असहिष्णुता और स्वार्थ दिखाई दिया, वह आज की बहुपक्षीय दुनिया के साथ मेल नहीं खाता। 'जब रोम जल रहा था, नीरो बांसुरी बजा रहा था' - ट्रम्प दुनिया की परवाह किए बिना अपनी ही धुन में मस्त हैं।

वहीं दूसरी ओर, ट्रम्प के बेटे डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर की क्रिप्टोकरेंसी कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फिनांसियल (डब्ल्यूएलएफ) और पाकिस्तान के बीच हुआ समझौता, ट्रम्प परिवार की छवि पर एक धब्बा है। 'बेटा बाप से दो कदम आगे' - ट्रम्प के बेटे भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए सत्ता का दुरुपयोग करने में पीछे नहीं हैं। यह समझौता तब हुआ, जब ट्रम्प प्रशासन भारत-पाक तनाव के बीच मध्यस्थता करने का नाटक कर रहा था, जिससे हितों के टकराव की आशंका और भी बढ़ गई। अमेरिकी सीनेट की एक कमेटी ने इस सौदे की जाँच शुरू कर दी है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या ट्रम्प परिवार ने अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करके निजी लाभ कमाया है। 'हाथों को मेहंदी क्या, जब पीसे लहू' - ट्रम्प परिवार सत्ता का इस्तेमाल करके खुलकर भ्रष्टाचार कर रहा है, और उन्हें किसी का डर नहीं है।

यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ट्रम्प का शासनकाल अभी भी जारी है और वे लगातार कुछ न कुछ ऐसा कर रहे हैं, जिससे दुनिया हैरान है। 'अंधेर नगरी चौपट राजा' - कुछ ऐसा ही हाल अमेरिका का हो गया है, जहाँ ट्रम्प के नेतृत्व में सबकुछ उल्टा-पुल्टा हो रहा है। अमेरिकी प्रशासन की प्रवासी नीति ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। लॉस एंजेलिस में ट्रम्प की प्रवासी नीति के खिलाफ हजारों लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया, जिससे शहर में अफरा-तफरी मच गई। प्रदर्शनकारियों ने इसे अमानवीय और असंवैधानिक बताया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें भी हुईं, और कुछ गिरफ्तारियां भी हुईं। मानवाधिकार संगठनों ने इसे 'मानवता के खिलाफ अपराध' करार दिया। इस विरोध ने न केवल ट्रम्प की प्रवासी नीति पर सवाल खड़े किए, बल्कि अमेरिका की लोकतांत्रिक छवि को भी गहरा नुकसान पहुँचाया है।

ट्रम्प के कार्यकाल में अमेरिका ने एक ऐसी राह चुनी है, जो उसे दुनिया से अलग-थलग कर देगी। अब यह देखना है कि क्या अमेरिका इस 'ट्रंपाघात' से उबर पाएगा, या फिर यह विनाश की एक ऐसी कहानी बनकर रह जाएगा, जिसे आने वाली पीढ़ियाँ कभी नहीं भूल पाएंगी।

संयुक्त राष्ट्र, मानवाधिकार संगठनों और यूनिसेफ जैसे वैश्विक संस्थानों ने एक स्वर में ट्रम्प की प्रवासी नीति को मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन बताया। 'भैंस के आगे बीन बजाना' - इन संगठनों की चेतावनी ट्रम्प प्रशासन के लिए बेअसर साबित हुई, जो अपनी ही मनमानी करने पर तुला था। अमेरिका की प्रथम महिला मेलानिया ट्रम्प और पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा तक को इस अमानवीय नीति की निंदा करनी पड़ी, जो यह दर्शाता है कि यह कदम न केवल अंतरराष्ट्रीय कानूनों, बल्कि मानवता की बुनियादी नैतिकताओं के भी खिलाफ था। 'जब अपने ही घर में आग लगी हो, तो पड़ोसी से क्या उम्मीद करें?' - अमेरिका खुद ही मानवाधिकारों का हनन कर रहा था, तो दुनिया से क्या उम्मीद की जा सकती थी?

ट्रम्प प्रशासन ने ओबामा काल के डीएसीए (डेफर्ड एक्शन फॉर चाइल्डहूड अराइवल) कार्यक्रम को समाप्त करने की भी कोशिश की, जिससे अमेरिका में जन्मे लाखों 'ड्रीमर' - वे बच्चे जिनके माता-पिता अवैध रूप से अमेरिका आए थे - शिक्षा, रोजगार और कानूनी सुरक्षा से वंचित हो सकते थे। 'गरीब को मारो, और मारो कमर तोड़' - कुछ ऐसा ही कर रहा था ट्रम्प

प्रशासन, जो पहले से ही कमजोर लोगों को और भी ज्यादा बेसहारा बना रहा था। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में इस फैसले को असंवैधानिक बताया, लेकिन ट्रम्प ने फिर से इसे निशाना बनाया, जो उनकी हठधर्मिता का प्रतीक था।

इस नीति ने अमेरिका के अंदर गहरे मतभेद पैदा किए। विश्वविद्यालयों, गवर्नरों और नागरिक संगठनों ने इस कदम को 'छात्रों के भविष्य पर हमला' करार दिया। यह 'मानवता को ताक पर रखने' का एक ऐसा उदाहरण था, जिसने न केवल कानूनी प्रक्रिया का बलात्कार किया, बल्कि उस राष्ट्र की आत्मा को भी घायल कर दिया, जिसने हमेशा खुद को 'आप्रवासियों का देश' बताया था। 'मुंह में राम, बगल में छुरी' - अमेरिका एक तरफ तो खुद को आप्रवासियों का देश कहता था, और दूसरी तरफ उनके साथ अमानवीय व्यवहार कर रहा था।

ट्रम्प ने बार-बार मेक्सिकन और अन्य लैटिन अमेरिकी प्रवासियों को 'क्रिमिनल,' 'रेपिस्ट,' और 'ड्रग डीलर्स' कहकर नस्लीय विद्वेष को बढ़ावा दिया। उनके द्वारा मुस्लिम बहुल देशों पर लगाया गया 'ट्रैवल बैन' न केवल इस्लामोफोबिया को संस्थागत बनाता था, बल्कि अमेरिका की विविधता को भी नकारता था। 'एक हाथ से ताली नहीं बजती' - ट्रम्प ने एकतरफा फैसले लेकर अमेरिका को दुनिया से काट दिया और अपने ही देश में विभाजन की रेखा खींच दी। एसीएलयू और अन्य संगठनों ने इसे संविधान विरोधी करार दिया, जिससे अमेरिकी सॉफ्ट पावर को गहरा नुकसान हुआ। दुनिया भर में अमेरिका की छवि एक 'शरण देने वाले राष्ट्र' से हटकर 'द्वार बंद करने वाले गढ़' में बदल गई। 'जैसा राजा वैसी प्रजा' - ट्रम्प के शासन में अमेरिका की छवि एक क्रूर और संवेदनहीन राष्ट्र के रूप में उभरी, जो अपने मूल्यों और सिद्धांतों को भूल चुका है।

हद तो तब हो गई, जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने कूटनीतिक प्रोटोकॉल तोड़ते हुए पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसीम मुनीर से मुलाकात की, जिससे अंतरराष्ट्रीय समुदाय में आश्चर्य और संदेह फैल गया। यह कदम दर्शाता है कि ट्रम्प पाकिस्तान में निर्वाचित सरकारों को दरकिनार कर सैन्य तंत्र के साथ सीधी डील करने की राह पर थे। यह पाकिस्तान की लोकतांत्रिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर एक बड़ा सवालिया निशान था। 'चोर-चोर मौसेरे भाई' - यह मुलाकात इस बात का सबूत थी कि सत्ता और शक्ति के खेल में ट्रम्प किसी भी हद तक जा सकते थे, भले ही इसका मतलब लोकतांत्रिक मूल्यों को ताक पर रखना ही क्यों न हो।

ट्रम्प की यह रणनीति शायद चीन के प्रभाव को सीमित करने का प्रयास हो, क्योंकि पाक सेना को अमेरिका की ओर झुकाने से चीन-पाक गठबंधन में तनाव पैदा हो सकता है। लेकिन, यह रणनीति अमेरिका और पाकिस्तान के संबंधों को स्थिर आधार पर नहीं, बल्कि सामरिक समीकरणों पर रखती है, जो लंबे समय में भ्रामक और खतरनाक साबित हो सकती है। 'सांप भी मरे, और लाठी भी ना टूटे' - ट्रम्प एक ही चाल से कई शिकार करना चाहते थे, लेकिन उनकी यह रणनीति उलटी पड़ सकती थी।

यह मुलाकात ऐसे समय पर हुई, जब भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध चरम तनाव में थे। ट्रम्प ने अतीत में भी कश्मीर मुद्दे पर 'मध्यस्थता' की पेशकश की थी, जिसे भारत ने सिरे से खारिज कर दिया था। सेना से सीधी बातचीत, उस पृष्ठभूमि में, भारत के लिए चिंता का कारण बन सकती है। यह 'अपने पैर

पर कुल्हाड़ी मारना' जैसा था - ट्रम्प अपनी गलत नीतियों से न केवल अमेरिका को नुकसान पहुंचा रहे थे, बल्कि भारत जैसे सहयोगी देशों को भी खतरे में डाल रहे थे।

यह आवश्यक है कि संयुक्त राष्ट्र और अन्य बहुपक्षीय संस्थान सक्रिय भूमिका निभाएं, जिससे शक्ति का संतुलन बनाए रखा जा सके और ट्रम्प की अतिवादी नीतियों के परिणामों से दुनिया को बचाया जा सके। अगर ऐसा होता है, तो ट्रम्प का यह कार्यकाल भविष्य के लिए एक चेतावनी बनकर रह जाएगा - एक ऐसा उदाहरण कि जब सत्ता विवेकहीन हाथों में हो, तो उसका दुष्परिणाम केवल एक देश पर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ता है।

निष्कर्ष:

डोनाल्ड ट्रम्प का 'ट्रंपाघात' कब तक चलेगा, यह कहना तो मुश्किल है लेकिन दुनिया को यह तय करना है कि क्या वह इस तबाही से उबरकर एक बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ाएगी, या फिर इस विध्वंस की विरासत को आगे बढ़ाती रहेगी।

'जाको राखे साइयां, मार सके ना कोय' - उम्मीद अभी भी बाकी है। अगर अंतरराष्ट्रीय समुदाय एकजुट होकर काम करे, तो ट्रम्प के विनाशकारी कदमों को पलटा जा सकता है और एक शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्था स्थापित की जा सकती है।

'अंधेरे के बाद उजाला होता है' - यह याद रखना ज़रूरी है कि हर बुरा दौर हमेशा के लिए नहीं रहता। ट्रम्प का कार्यकाल एक ऐसा अंधेरा युग था, जिसने दुनिया को बहुत कुछ सिखाया है। अब यह हमारे ऊपर है कि हम उन सीखों से फायदा उठाकर एक बेहतर कल का निर्माण करें। •

निर्दयता की क़ीमत

डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिकी आव्रजन नीति ने अभूतपूर्व और कठोर दिशा ले ली—जिसमें "अमेरिका फर्स्ट" के नाम पर यात्रा प्रतिबंध, परिवारों को अलग करना, और बड़े पैमाने पर हिरासत जैसे कदम शामिल थे। इस मानवीय त्रासदी की सबसे तीव्र झलक लॉस एंजेलेस में देखने को मिली—जो कभी शरण देने वाला शहर था, अब प्रतिरोध और पीड़ा का केंद्र बन गया।
यह लेख बताता है कि कैसे ट्रंप की कठोर नीतियों ने आम लोगों की ज़िंदगियाँ तहस-नहस कर दीं, सामाजिक संस्थाओं पर बोझ डाला, और उन अमेरिकी मूल्यों को ही चुनौती दी जिन पर कभी इस देश की पहचान टिकी थी।

डोनाल्ड ट्रम्प के अधीन, संयुक्त राज्य अमेरिका ने कठोर आव्रजन नीतियों को अपनाया जिसने राष्ट्र के प्रवासियों, अंतरराष्ट्रीय कानून और अपने स्वयं के मूल्यों के साथ संबंधों को मौलिक रूप से बदल दिया। 'अमेरिका फर्स्ट' के बैनर तले प्रचारित, इन नीतियों - व्यापक यात्रा प्रतिबंध, परिवार अलगाव, सामूहिक हिरासत और कानूनी आव्रजन मार्गों में कटौती - को सीमा सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक बताया गया था। हालांकि, वास्तविकता अव्यवस्था, कानूनी अराजकता, आर्थिक नुकसान और एक धूमिल वैश्विक छवि का एक झरना थी। लॉस एंजिल्स में यह सब कुछ अधिक स्पष्ट था, एक शहर जो एक युद्ध के मैदान में बदल गया और राष्ट्रीय आप्रवासन तनावों का एक स्पष्ट बैरोमीटर था।

ट्रम्प की आप्रवासन रणनीति, जो मैक्सिकन प्रवासियों को राक्षसी बनाने वाली अभियान बयानबाजी के साथ बोई गई थी, तेजी से कार्यकारी आदेशों और डीएचएस निर्देशों में प्रकट हुई। यात्रा प्रतिबंध, डीएसीए की समाप्ति और सीमा पर परिवारों को अलग करने वाली 'शून्य सहिष्णुता' नीति ने भय और विभाजन का माहौल पैदा किया, खासकर लॉस एंजिल्स जैसे अभयारण्य शहरों में। परिवार बिखर गए, स्कूलों में गैर-दस्तावेजी बच्चों में अनुपस्थिति बढ़ गई और मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों ने आप्रवासी समुदायों में एक आघात महामारी की चेतावनी दी। लॉस एंजिल्स टाइम्स ने लंबे समय से बसे निवासियों को लक्षित करने वाले आईसीई छापों का दस्तावेजीकरण किया, जिससे व्यापक आतंक और विरोध प्रदर्शन हुआ।

'शून्य सहिष्णुता' नीति ने राष्ट्रीय आक्रोश को भड़काया, अवैध प्रवेश के लिए माता-पिता पर आपराधिक मुकदमा चलाया गया जबकि जबरन उनके बच्चों को हटा दिया गया और हिरासत में लिया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स और सीएनएन द्वारा प्रकाशित पिंजरों में रोते हुए बच्चों की छवियों ने वैश्विक निंदा को जन्म दिया। लॉस एंजिल्स ने पुनर्मिलन और न्याय की मांग करते हुए बड़े पैमाने पर प्रदर्शन देखा। दक्षिणी कैलिफोर्निया के एसीएलयू ने तर्क दिया कि नीति ने संवैधानिक सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानदंडों का उल्लंघन किया है, मुकदमे दायर किए। जबकि अदालतों ने पुनर्मिलन का आदेश दिया, कई बच्चे महीनों तक प्रणाली में खो गए, आव्रजन अदालतों पर बोझ डाल दिया, स्थानीय कानून प्रवर्तन पर बोझ डाल दिया और अपराध निवारण से संसाधनों को हटा दिया।

ट्रम्प की नीतियों ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भी कमजोर किया, खासकर आप्रवासी श्रम पर निर्भर क्षेत्रों में। कैलिफोर्निया कृषि, निर्माण और आतिथ्य को तीव्र श्रम की कमी का सामना करना पड़ा। एच-1बी और अन्य कार्य वीज़ा कार्यक्रमों के निलंबन ने तकनीकी स्टार्टअप और नवाचार केंद्रों को बाधित कर दिया। एक ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन की रिपोर्ट में विदेशी प्रतिभा में गिरावट

के कारण सकल घरेलू उत्पाद और नवाचार क्षमता में अरबों के नुकसान का विस्तृत विवरण दिया गया है। इसके अलावा, भय ने गैर-दस्तावेजी श्रमिकों को श्रम दुर्व्यवहारों की रिपोर्ट करने या स्वास्थ्य सेवा तक पहुंचने से हतोत्साहित किया, जिससे असमानता और सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम बढ़ गए, खासकर COVID-19 महामारी के दौरान।

घरेलू परिणामों से परे, ट्रम्प के रुख ने राजनयिक संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया। अल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला और मेक्सिको जैसे देशों ने अपने नागरिकों के साथ व्यवहार की निंदा की, जबकि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त ने परिवार अलगाव को 'सरकार द्वारा स्वीकृत बाल शोषण' करार दिया।ट्रम्प ने आप्रवासी विरोधी भावनाओं को हवा दी, जिससे राजनीतिक ध्रुवीकरण गहरा हुआ। उनकी नीतियों ने श्वेत राष्ट्रवादी समूहों को प्रोत्साहित किया, जिससे घृणा अपराधों में वृद्धि हुई। लॉस एंजिल्स में लैटिनो और मध्य पूर्वी समुदायों के खिलाफ घृणा से संबंधित घटनाओं में वृद्धि देखी गई। कानून प्रवर्तन में सामुदायिक विश्वास में गिरावट आई क्योंकि स्थानीय पुलिस को आईसीई के साथ मिलीभगत करते हुए देखा गया, यहां तक कि अभयारण्य शहरों में भी। कानूनी तर्कों और आर्थिक आंकड़ों से परे एक मानवीय त्रासदी निहित है। लॉस एंजिल्स में, हजारों परिवार अलगाव और निर्वासन के निशान के साथ जी रहे हैं। अमेरिकी नागरिकता वाले बच्चे बिना माता-पिता के छूट गए थे। मिश्रित स्थिति वाले परिवार लगातार डर में रहते थे। स्थानीय कलाकारों, फिल्म निर्माताओं और लेखकों ने इन कहानियों को विरोध कला में बदल दिया, जिससे आघात की चौड़ाई का पता चला। •

Reciprocal Tar
Country
China
European Union
Vietnam
Taiwan
Japan
India
South Korea
Thailand
Switzerland
Indonesia
Malaysia
Cambodia
United Kingdom
South Africa
Brazil
Bangladesh
Singapore
97
10%
60%
10%
74%
10%
33%
34%
10%
10%
58%
10%
88%
10%

टैरिफ की तकरार

डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामक टैरिफ नीति, जिसे आर्थिक राष्ट्रवाद के आवरण में पेश किया गया, इसने वैश्विक व्यापार और अमेरिका के बाज़ार—दोनों को भारी नुकसान पहुँचाया है। जो अभियान अमेरिकी उद्योगों की रक्षा के वादे से शुरू हुआ था, वह अब आत्मघाती आर्थिक संकट का रूप ले चुका है—आपूर्ति श्रृंखलाएं बाधित हुई हैं, कीमतें बढ़ी हैं, और पारंपरिक सहयोगी देशों से रिश्ते बिगड़े हैं।

डोनाल्ड ट्रम्प, स्वयं-घोषित मास्टर वार्ताकार और हर अमेरिकी चीज के चैंपियन, ने एक बार फिर दुनिया पर टैरिफ़ ब्लिट्ज़क्रेग जारी करके वैश्विक मंच पर ₹चीजों को हिला देने₹ का फैसला किया है। जाहिरा तौर पर अमेरिकी उद्योगों को अनुचित प्रतिस्पर्धा के खतरों से बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया, यह संरक्षणवादी धर्मयुद्ध एक गणनात्मक रणनीति से कम और एक वैश्विक व्यापार सैंडबॉक्स में बच्चे की तरह लगता है, जो रेत (इस मामले में, टैरिफ़) को किसी भी व्यक्ति पर फेंकता है जो अपने से ऊंचा सैंडकैसल बनाने की हिम्मत करता है। परिणाम? टूटी हुई आपूर्ति श्रृंखलाएं, बढ़ती मुद्रास्फीति और एक तेजी से अलग-थलग अमेरिका, अपने संरक्षणवादी खिलौनों के साथ कोने में दुखी होने के लिए छोड़ दिया गया, जबकि बाकी दुनिया गंदगी को साफ करने की कोशिश कर रही है।

टैरिफ़ का प्रारंभिक वादा हमेशा लुभावना होता है: घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा के ₹हमले₹ से बचाने वाली एक चमकदार ढाल, जिससे वे पनपने और नौकरियां पैदा कर सकें। हालांकि, व्यवहार में, टैरिफ़ में एक बुरी आदत होती है कि वे बूमरैंग की तरह अधिक कार्य करते हैं, थ्रोअर को सीधे चेहरे पर मारते हैं। अमेरिकी फर्म, आपूर्तिकर्ता और अंततः, लंबे समय से पीड़ित उपभोक्ता, उच्च इनपुट लागत, बाधित संचालन और आर्थिक बेचैनी की एक सामान्य भावना के माध्यम से इन नीतियों का खामियाजा भुगतते हैं। व्हार्टन स्कूल के एक सूखे अकादमिक विश्लेषण के रूप में, ट्रम्प का टैरिफ़ शासन-लक्षित देशों पर कुछ हद तक हास्यप्रद 10% से लेकर सकारात्मक रूप से हास्यास्पद 60% तक-एक छिपे हुए कर के रूप में कार्य करता है, जीडीपी विकास को धीमा करता है और कॉर्पोरेट करों में समान वृद्धि की तुलना में घरेलू आय को अधिक मार्जिन से कम करता है। यह आर्थिक कीमिया बुरी तरह से गलत हो गई है, समृद्धि की क्षमता को मूर्ख के सोने के एक भाप वाले ढेर में बदल देती है। कोई सोच सकता है कि क्या प्रशासन में किसी ने इस गलत सलाह वाले धर्मयुद्ध पर निकलने से पहले किसी वास्तविक अर्थशास्त्री से परामर्श करने की जहमत उठाई।

आर्थिक नीति अनिश्चितता का सदा-उपद्रवी भूत, वित्तीय बाजारों का वह भयानक बूगमैन, ट्रम्प की अनियमित व्यापार घोषणाओं और आर्थिक ब्रिंकमैनशिप के लिए उनकी सामान्य प्रवृत्ति से प्रेरित होकर रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर चढ़ रहा है। किसी को कभी भी ठीक से पता नहीं होता कि अगला ट्वीट क्या लाएगा, किस उद्योग को मनमाने ढंग से लक्षित किया जाएगा, या किस लंबे समय से चले आ रहे व्यापारिक संबंध को संक्षेप में समाप्त कर दिया जाएगा। जापान, अन्य अर्थव्यवस्थाओं के बीच, अमेरिकी टैरिफ़ द्वारा उत्पन्न वैश्विक असुरक्षा के कारण पहले से ही अपने सकल घरेलू उत्पाद को एक गैर-महत्वपूर्ण हिट (लगभग 0.9%) लेते हुए देखा गया है। व्यवसाय, स्वाभाविक रूप से ऐसे अस्थिर माहौल में निवेश करने में हिचकिचाते हैं, किराए पर लेने और पूंजी परियोजनाओं में देरी कर रहे हैं। बढ़ते कीमतों और आर्थिक मंदी के आसन्न खतरे का सामना कर रहे परिवार, उन बड़े-टिकट खरीदों को स्थगित कर

रहे हैं जिनके लिए वे इतनी लगन से बचत कर रहे थे। परिणाम एक वैश्विक डोमिनो प्रभाव है, आर्थिक विकास की एक उचित रूप से सिंक्रनाइज़ अवधि में एक गड़बड़ और निराशाजनक मंदी, यह सब एक आदमी की संरक्षणवादी आतिशबाजी के लिए प्रवृत्ति के लिए धन्यवाद है।

और निश्चित रूप से, कोई भी व्यापार युद्ध जवाबी टैरिफ़ की एक स्वस्थ खुराक के बिना पूरा नहीं होता है, वे प्रतिशोधी भावनाएँ जो वैश्विक बाजार को सताती हैं, हमेशा स्कोर को बराबर करने की कोशिश करती हैं। कनाडा और मैक्सिको से लेकर भारत और चीन तक, देश ट्रम्प के टैरिफ़ आक्रमण का जवाब अपने स्वयं के टैरिफ़ के साथ दे रहे हैं, जिससे बढ़ते कर्तव्यों और बढ़ते तनावों का एक टिट-फॉर-टैट चक्र बन रहा है। इन झड़पों के ट्रिगर अक्सर बेतुके ढंग से छोटे होते हैंः चीनी इलेक्ट्रॉनिक्स, कनाडाई ऊर्जा, भारतीय वस्तुओं पर उच्च शुल्क-जो खेल के मैदान के झगड़े के आर्थिक समकक्ष हैं जो पूर्ण पैमाने पर गैंग युद्धों में बढ़ रहे हैं। ये कदम विश्वास को कम करते हैं, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं को मंदी की ओर धकेलते हैं और वैश्विक स्तर पर प्रमुख क्षेत्रों को अस्थिर करते हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सभी के लिए संभावित रूप से भयावह परिणामों के साथ उच्च-दांव वाले चिकन का खेल बन जाता है।

नुकसान, स्वाभाविक रूप से, सरकारी स्प्रेडशीट और मैक्रोइकॉनॉमिक संकेतकों तक सीमित नहीं है। सस्ती स्टील को सोर्स करने के लिए संघर्ष कर रही कार निर्माताओं से लेकर आसमान छूती एल्यूमीनियम की कीमतों से जूझ रही निर्माण कंपनियों तक, पूरे स्पेक्ट्रम में उद्योग ट्रम्प की नीतियों की मार महसूस कर रहे हैं। उपभोक्ता, निश्चित रूप से, अंतिम शिकार हैं, कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर किराने का सामान और गैसोलीन तक हर चीज के लिए अधिक भुगतान कर रहे हैं। अमेरिकी स्टील और एल्यूमीनियम शुल्क ने निर्माताओं और बिल्डरों के लिए लागत में वृद्धि की है, जिससे लाभ मार्जिन कम हो रहा है और कंपनियों को या तो नुकसान को अवशोषित करने या उन्हें उपभोक्ताओं पर पारित करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जिससे मुद्रास्फीति और बढ़ रही है और क्रय शक्ति कम हो रही है। यहां तक कि वॉलमार्ट जैसे वैश्विक दैत्य, आपूर्ति श्रृंखला दक्षता के उन मास्टर्स ने भी इन बढ़ी हुई लागतों को अवशोषित करने या पारित करने की बात स्वीकार की है, जो टैरिफ़ बोझ की व्यापक और अपरिहार्य प्रकृति का संकेत है।

अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक निकाय, उन मापा और सतर्क घोषणाओं के गढ़, अब बढ़ती तात्कालिकता के साथ अलार्म बजा रहे हैं, वैश्विक

अर्थव्यवस्था पर व्यापार युद्ध के विनाशकारी टोल की चेतावनी दे रहे हैं। उदाहरण के लिए, ओईसीडी, व्यापार अनिश्चितता और टैरिफ़ बाधाओं को प्राथमिक अपराधी बताते हुए, वैश्विक जीडीपी को 2025-26 में एक निराशाजनक 2.9% तक सिकुड़ते हुए प्रोजेक्ट करता है-जो पहले के एनेमिक 3.3% से कम है। आईएमएफ, कभी भी कयामत के विभागों में पीछे नहीं रहने वाला, इस निराशाजनक पूर्वानुमान को दोहराता है, अमेरिकी विकास को लगभग 1.6% तक कम करने का अनुमान लगाता है और चेतावनी देता है कि लंबे समय तक टैरिफ़ के तहत वैश्विक मंदी के जोखिम तिगुने हो गए हैं। यह आर्थिक निराशावाद की एक सिम्फनी है, जिसका संचालन उत्साह के साथ स्वयं ट्रम्प द्वारा किया जा रहा है, जो वैश्विक स्तर पर आत्म-प्रवृत्त घावों का एक उत्कृष्ट प्रदर्शन है। किसी को आश्चर्य होता है कि क्या वह वास्तव में उस क्षति की भयावहता को समझता है जो वह कर रहा है, या यदि वह इसे ₹मेक अमेरिका ग्रेट अगेन₹ की अपनी खोज में एक आवश्यक बलिदान के रूप में देखता है।

पहले से ही मौजूद गड़बड़ में बढ़ते तनाव को जोड़ना मुद्रास्फीति का आसन्न खतरा है, जो थोड़ी सी उकसावे पर भी झपटने के लिए हमेशा तैयार रहता है। टैरिफ़, मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के हमेशा मौजूद खतरे के साथ मिलकर, बोर्ड भर में ऊर्जा और उपभोक्ता कीमतों को बढ़ाने, मुश्किल से जीते गए मुद्रास्फीति लाभों को उलटने और फेडरल रिजर्व को बहुप्रतीक्षित ब्याज दर में कटौती में देरी करने की धमकी देते हैं। शायद इस पूरे पतन का सबसे अशांत पहलू वह भयानक प्रतिध्वनि है जो यह महामंदी और कुख्यात स्मूट-हॉली टैरिफ़ को उजागर करता है, जिसे व्यापक रूप से वैश्विक व्यापार को ध्वस्त करने और आर्थिक संकट को बढ़ाने के लिए दोषी ठहराया गया है। 2025 के टैरिफ़, कई मामलों में, उस विनाशकारी अवधि के दौरान देखे गए स्तरों से अधिक हैं, जिससे अंतरराष्ट्रीय विखंडन के दोहराव का जोखिम है क्योंकि अर्थव्यवस्थाएं रक्षात्मक व्यापार गुटों का निर्माण करती हैं, खुद को दुनिया से काटती हैं और खुद को आर्थिक ठहराव की निंदा करती हैं। ऐसा लगता है मानो इतिहास हमें चेतावनी देने की कोशिश

इस पूरे संकट का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि इसकी गूंज अतीत की एक भयावह याद—महामंदी और बदनाम स्मूट-हॉली टैरिफ—की तरह सुनाई देती है, जिसे वैश्विक व्यापार के ध्वस्त होने और आर्थिक संकट को और गंभीर बनाने के लिए व्यापक रूप से जिम्मेदार माना जाता है।

कर रहा है, संरक्षणवाद के खतरों के बारे में छत से चिल्ला रहा है, लेकिन ट्रम्प प्रशासन, अपने वैचारिक उत्साह से अंधा होकर, सुनने से इनकार कर रहा है। किसी को आश्चर्य होता है कि क्या वे वास्तव में मानते हैं कि ₹इस बार अलग है₹, या यदि वे केवल अपने संकीर्ण राजनीतिक लक्ष्यों की खोज में वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ जुआ खेलने को तैयार हैं।

निष्कर्ष में, ट्रम्प का व्यापार आक्रमण अपने घरेलू अनुमोदन रेटिंग को अस्थायी रूप से बढ़ावा दे सकता है, आर्थिक राष्ट्रवाद की एक भ्रामक भावना के लिए अपील कर सकता है, लेकिन यह अंततः एक पिरिक विजय है, एक ऐसी जीत जो इतनी अधिक कीमत पर आती है कि इसे मनाने लायक भी नहीं है। अमेरिकी उपभोक्ता, श्रमिक और बाजार ट्रम्प के संरक्षणवादी उत्साह के लिए एक भारी कीमत चुका रहे हैं, उच्च कीमतों, कम आर्थिक अवसरों और जीवन की गुणवत्ता में गिरावट को सहन कर रहे हैं। इस बीच, वैश्विक विकास रुक रहा है, आपूर्ति श्रृंखलाएं टूट रही हैं और रणनीतिक गठबंधन बदल रहे हैं, जिससे अमेरिका दुनिया के मंच पर अलग-थलग और कम हो गया है। अमेरिका की कभी दूरगामी और प्रशंसित अर्थव्यवस्था खुद को अधिक अछूता पा सकती है, लेकिन यह खुद को और अधिक अकेला भी पाती है, एक ऐसा किला जो अपने स्वयं के स्व-प्रवृत्त घावों से घिरा हुआ है।

अंततः, ट्रम्प का व्यापार युद्ध आर्थिक राष्ट्रवाद के खतरों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व की एक स्पष्ट याद दिलाता है। सिद्धांत रूप में, टैरिफ़ को घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए दीवारें बनानी चाहिए; व्यवहार में, वे घर और विदेश दोनों जगह पूरी अर्थव्यवस्थाओं को तबाह कर देते हैं। अब उम्मीद है कि दुनिया इस गलत प्रयोग से सीख सकती है और एक अधिक खुले, सहकारी और समृद्ध वैश्विक व्यापार प्रणाली की ओर वापस एक रास्ता तय कर सकती है। लेकिन ट्रम्प के अभी भी टैरिफ़ हथौड़ा चलाने के साथ, भविष्य अनिश्चित बना हुआ है, और आगे आर्थिक व्यवधान का खतरा मंडरा रहा है। •

सुरक्षा नहीं, सौदा ट्रंप की नाटो नीति

ट्रंप के विदेश नीति का तमाशा

डोनाल्ड ट्रम्प की नाटो के बारे में हाल की घोषणाएँ - कि अमेरिका 'नाटो को वित्त पोषित करता है जबकि यूरोप अच्छा जीवन जी रहा है' - केवल आलोचनाएँ नहीं थीं। वे सटीक रूप से कैलिब्रेट किए गए थे, हालांकि अनुमानित रूप से भारी-भरकम, दुनिया के सबसे स्थायी सुरक्षा गठबंधनों में से एक पर प्रहार करते हैं। उनका 'अमेरिका फर्स्ट' सिद्धांत, अब तक एक थकाऊ क्लिच, बेतुकेपन की नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है, जिसमें नाटो को एक बुरे सौदे के रूप में फिर से पैक किया जा रहा है, जो मेहनती अमेरिकी करदाताओं की पीठ पर मुफ्त कॉकटेल पी रहे यूरोपीय लोगों से भरा एक जीर्ण-शीर्ण कंट्री क्लब है।

इस कार्टूनिस्ट बड़बोलेपन के नीचे एक परेशान करने वाला सच छिपा हैः ट्रम्प बातचीत नहीं कर रहे हैं; वह दुनिया में अमेरिका की भूमिका का धीमा विध्वंस कर रहे हैं। वह अच्छी तरह से प्राप्त रैली भाषण की क्षणिक डोपामाइन भीड़ के लिए रणनीतिक विश्वसनीयता का व्यापार कर रहा है। और ऐसा करने में, वह न केवल सहयोगियों का अपमान कर रहा है - वह व्यावहारिक रूप से भू-राजनीतिक जीत को उन विरोधियों के लिए उपहार में दे रहा है जो शायद ही अपनी खुशी को रोक पाते हैं।

नाटो एक व्यवसाय लेनदेन के रूप मेंः सुरक्षा रैकेट की कला

ट्रम्प के लिए, नाटो द्वितीय विश्व युद्ध और शीत युद्ध की क्रूसिबल में जाली एक रणनीतिक आवश्यकता नहीं है - यह एक एक्सेल स्प्रेडशीट है जो दुष्ट हो गई है। वह लगातार गठबंधन को एक विनाशकारी निवेश के रूप में तैयार करता है, जहां अमेरिका बिल का भुगतान करता है जबकि यूरोप आराम से अपने मोनोकल्स को पॉलिश करता है। इस बात को कभी भी ध्यान में न रखें कि नाटो की संरचना सदस्यता बकाया या उपयोगकर्ता शुल्क पर आधारित नहीं है। ट्रम्प की चिड़चिड़ी शिकायत जटिल बहुपक्षीयता को माफिया-शैली की सुरक्षा योजना में कम कर देती हैः 'भुगतान करें, या आप अपने दम पर हैं, कैपिसी?'

संक्षेप में, उन्होंने अनुच्छेद 5 - नाटो का पवित्र आपसी रक्षा खंड, गठबंधन का बहुत आधार - को सेवा की एक बातचीत योग्य अवधि में बदल दिया है, एक 'नियम और शर्तें लागू हो सकती हैं' अस्वीकरण एक शिकारी ऋण समझौते के निचले भाग में छोटे फ़ॉन्ट में स्क्रॉल किया गया है।

यह कूटनीति नहीं है; यह एक ध्वज पिन और आत्म-महत्व की एक अतिरिक्त मदद के साथ जबरन वसूली है। यह द आर्ट ऑफ द डील है, जिसे अंतरराष्ट्रीय मंच के लिए फिर से कल्पना की गई है, जहां सिद्धांत कल की सुर्खियों के रूप में डिस्पोजेबल हैं।

आशा की एक झलक के बिना एक जी7?

तत्काल प्रतिध्वनि 3 बजे ट्रम्प ट्वीट के रूप में अनुमानित थी। जी7 शिखर सम्मेलन में, मूड को सबसे अच्छा 'राजनयिक पिघलने की संभावना के साथ ठंढा' के रूप में वर्णित किया जा सकता है। फ्रांस और जर्मनी, आमतौर पर आदरणीय कूटनीति के प्रतिमान, रणनीतिक क्षति नियंत्रण मोड में चले गए, 'यूरोपीय संप्रभुता' और 'रणनीतिक स्वायत्तता'

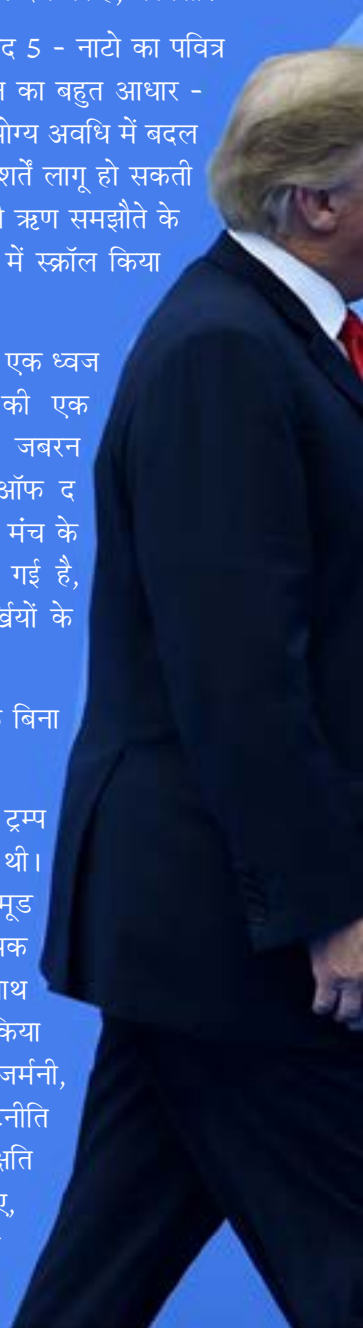

के बारे में बड़बड़ाते हुए चिंतित माता-पिता की तरह चर्चा कर रहे हैं कि कैसे विद्रोही बेटे की नवीनतम पलायन। इस बीच, कनाडा और यूके, उन कट्टरपंथीय ट्रांसअटलांटिक सहयोगियों ने चुपचाप उस असहज सवाल को पूछना शुरू कर दिया जिसे हर कोई बेतहाशा टालने की कोशिश कर रहा थाः 'क्या होगा अगर अमेरिका बस... अगली बार नहीं दिखा?'

ट्रम्प की अनुपस्थिति न केवल शारीरिक थी - यह दार्शनिक थी, एक गहरी शून्य जहां नेतृत्व और दृष्टि होनी चाहिए थी। उन्होंने प्रभावी ढंग से जी7 को जी6 में बदल दिया, जो अमेरिकी असाधारणता के मलबे से जो कुछ भी वे कर सकते थे उसे बचाने की कोशिश कर रहे थके हुए देशों की एक सभा है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने वैश्विक कूटनीति को अहंकार की सनक पर किए गए क्षणिक समझौतों के एक घूमने वाले दरवाजे में बदल दिया, न कि साक्ष्य और साझा मूल्यों की ठोस नींव में।

ट्रांसअटलांटिक दरारः दरारें गलती लाइनों में बदल जाती हैं और तलाक के लिए फाइलिंग करती हैं

यूरोप, लंबे समय से अमेरिकी सुरक्षा छतरी के आरामदायक आलिंगन का आदी है, अब खुद को खरोंच से एक नया निर्माण करने के लिए हांफते हुए पाता है, जैसे एक गृहस्वामी तूफान के बीच एक लीक छत को बेतहाशा पैच कर रहा है। जर्मनी अचानक अपने लक्जरी कार उद्योग के लिए पहले से आरक्षित उत्साह के साथ अपने रक्षा बजट में पैसा फेंक रहा है, अपने जंग-बाल्टी सैन्य को आधुनिक बनाने के प्रयास में 100 बिलियन से अधिक का निवेश कर रहा है। फ्रांस, वैश्विक भव्यता की अपनी बारहमासी आकांक्षाओं के साथ, 'रणनीतिक स्वायत्तता' की अवधारणा के पीछे रैली कर रहा है, एक यूरोपीय सेना की कल्पना कर रहा है जो दुनिया की महाशक्तियों के साथ पैर से पैर मिलाकर खड़ा हो सके (बेशक, वास्तव में इसे तैनात करने की पेचीदा आवश्यकता को छोड़कर)। और स्कैंडिनेवियाई राज्य, पोलैंड और बाल्टिक राष्ट्र, हमेशा अपने रूसी पड़ोसी द्वारा डाली गई अशुभ छाया के प्रति सचेत, वाशिंगटन द्वारा अचानक प्लग खींचने की स्थिति में आकस्मिकता ढांचे को बेतहाशा बना रहे हैं, जिससे वे पुतिन की भू-राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की बर्फीली हवाओं के सामने उजागर हो जाएंगे।

यह 'बोझ-साझाकरण' नहीं है, सहयोगियों

के पारस्परिक लाभ के लिए सहयोग करने की अजीब अवधारणा है। यह तलाक के बाद की आकस्मिकता योजना है, संपत्ति का उन्मादी विभाजन और एक गंदे और तीखे अलगाव की प्रत्याशा में निरोधक आदेशों का मसौदा तैयार करना।

ट्रम्प का सरलीकृत तर्क - कि अमेरिका को किसी तरह यूरोप की रक्षा करने के लिए बांस किया गया है - जानबूझकर इस तथ्य को अनदेखा करता है कि अमेरिकी वैश्विक नेतृत्व एक धर्मार्थ कार्य नहीं है; यह एक रणनीतिक अनिवार्यता है, स्थिरता और प्रभाव में एक गणनात्मक निवेश है। जब आप सहयोगियों को कमजोर करते हैं, तो आप न केवल जिम्मेदारियों को कम करते हैं - आप प्रभाव को कम करते हैं, जिससे आप एक ऐसी दुनिया में एक कम बल बन जाते हैं जो तेजी से सहयोग और सामूहिक कार्रवाई की मांग करती है।

ट्रम्प के लापरवाह बयानों से शायद सबसे भयावह और खतरनाक नतीजा वह भू-राजनीतिक अवसर है जो उन्होंने व्लादिमीर पुतिन को चांदी की थाली में परोस दिया है। पुतिन ने लंबे समय से नाटो को तोड़ने, गठबंधन को झगड़ालू देशों के एक संग्रह में विभाजित करने की तीव्र इच्छा को पोषित किया है, जिसे मास्को द्वारा आसानी से हेरफेर और हावी किया जा सकता है। ट्रम्प ने, अपनी असीम बुद्धिमत्ता में, उसे हथौड़ा सौंप दिया है, पुतिन को अपने लंबे समय से देखे गए सपने को साकार करने का मौका दे रहा है। जब ट्रम्प ने लापरवाही से घोषणा की कि वे 'रूस को उन अपराधी नाटो सदस्यों के लिए जो चाहे करने देंगे', तो मॉस्को ने न केवल शैंपेन तोड़ दी - बल्कि उसने गठबंधन के कवच में छेद का सावधानीपूर्वक अध्ययन करते हुए और अपनी अगली चाल की साजिश रचते हुए प्रचुर मात्रा में नोट्स लिए।

यूक्रेन अब एक गंभीर चेतावनी कहानी है, जो भेद्यता की कीमत और अविश्वसनीय भागीदारों पर निर्भर रहने के परिणामों की एक स्पष्ट याद दिलाता है। एस्टोनिया और लातविया जैसे पूर्वी यूरोपीय देश, रूस की सीमा से लगे छोटे लेकिन भयंकर स्वतंत्र राष्ट्र, एक शांत आतंक से ग्रस्त हैं, यह अच्छी तरह से जानते हैं कि ट्रम्प की लेन-देन वाली दुनिया में, उनकी संप्रभुता केवल उनकी चेकबुक जितनी मजबूत है, और उनकी स्वतंत्रता केवल आयोवा में नवीनतम मतदान संख्याओं जितनी मूल्यवान है।

इस तरह की लुभावनी वाक्पटुतापूर्ण लापरवाही के माध्यम से रूस को प्रोत्साहित करने में, ट्रम्प ने न केवल नाटो को कमजोर किया - उन्होंने स्वयं निवारक को कमजोर किया, आक्रामकता को आमंत्रित किया और यूरोप में शांति और स्थिरता की नींव को

कम आंका।

विडंबना उतनी ही क्रूर है जितनी कि यह अनुमानित है। नाटो से बाहर निकलने की धमकी देकर जब तक कि अन्य सदस्य 'अधिक भुगतान' नहीं करते हैं, ट्रम्प अनजाने में उस वास्तविकता को तेज कर सकते हैं जिससे वह डरने का दावा करता है: एक यूरोप सैन्य रूप से अमेरिका से स्वतंत्र है, एक महाद्वीप जो अमेरिकी मारक क्षमता पर निर्भर हुए बिना खुद का बचाव करने में सक्षम है। और एक बार जब यूरोप अकेले चलना सीख जाता है, तो वाशिंगटन खुद को उस टेबल पर बिना सीट के पा सकता है जिसे उसने बनाया था, उस असंतुष्ट दर्शक की स्थिति में आ गया जो किनारे से देख रहा है कि बाकी दुनिया उसके बिना आगे बढ़ रही है।

अमेरिकी नेतृत्व चालान और धमकियों द्वारा कायम नहीं है; यह विश्वास, मूल्यों और सिद्धांतों के लिए एक साझा प्रतिबद्धता और संकट के समय में सहयोगियों के साथ खड़े होने की प्रदर्शनकारी इच्छा द्वारा कायम है। और एक बार टूट जाने के बाद, विश्वास को रक्षा बजट में एक और प्रतिशत बिंदु फेंककर आसानी से ठीक नहीं किया जा सकता है; इसके लिए रिश्तों को फिर से बनाने और प्रतिबद्धताओं की पुष्टि करने के लिए एक निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है, एक ऐसा कार्य जो एक ऐसे नेता की पकड़ से तेजी से परे प्रतीत होता है जिसकी एकमात्र मुद्रा लेनदेन लाभ है।

ट्रम्प सिद्धांत, यदि कोई ऐसे ऊंचे शब्द के साथ इसे प्रतिष्ठित कर सकता है, तो एक कच्चे और सरलीकृत समीकरण पर टिका है: शक्ति = धन = लाभ। लेकिन कूटनीति के जटिल नृत्य में, शक्ति गठबंधनों से, मानदंडों और संधियों के पालन से और पूर्वानुमेयता से प्रवाहित होती है। ट्रम्प, अपने अनियमित ट्वीट्स, अपने डॉलर-चालित अल्टीमेटम और रणनीतिक सोच से मिलती-जुलती किसी भी चीज़ के प्रति अपने स्पष्ट तिरस्कार के साथ, उनमें से कोई भी नहीं प्रदान करते हैं।

एशिया में, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे सहयोगी, लंबे समय से अमेरिकी सुरक्षा पर निर्भर रहने के आदी हैं, चुपचाप अपने दांव को हेज कर रहे हैं, वैकल्पिक सुरक्षा व्यवस्था की खोज कर रहे हैं और चीन जैसी क्षेत्रीय शक्तियों के साथ घनिष्ठ संबंध बना रहे हैं। मध्य पूर्व में, सत्तावादी शासन ध्यान देते हैं: ट्रम्प के अधीन अमेरिका विश्वासघात को दंडित नहीं करता है; यह दुस्साहस को पुरस्कृत करता है, दुष्ट अभिनेताओं को प्रोत्साहित करता है और एक अस्थिर क्षेत्र में सत्ता के नाजुक संतुलन को कम आंकता है।

वैश्विक धारणा मायने रखती है, शायद किसी भी स्प्रेडशीट या बैलेंस शीट से ज्यादा। और ट्रम्प के तहत, अमेरिका अब अपरिहार्य राष्ट्र नहीं है, स्वतंत्रता और लोकतंत्र की मशाल जिसने एक समय पूरी दुनिया में आशा और प्रशंसा को प्रेरित किया था। यह अप्रत्याशित है, अविश्वसनीय भागीदार, एक दायित्व है जो एक नेता के रूप में प्रच्छन्न है, एक तेजी से बदलती वैश्विक व्यवस्था की चुनौतियों से जूझ रही दुनिया के लिए एक चेतावनी कहानी है।

व्यंग्यात्मक अंतरालः नाटो सदस्यता, अब सदस्यता पर!

21वीं सदी के लिए नाटो की कल्पना एक स्ट्रीमिंग सेवा के रूप में करें, एक भू-राजनीतिक नेटफ्लिक्स यदि आप चाहें तो। 'बेसिक प्लान' खाली वादों और समर्थन के अस्पष्ट शब्दों वाले बयानों तक पहुंच प्रदान करता है। 'प्रीमियम प्लान' में थोड़े अधिक आश्वस्त सुरक्षा गारंटी शामिल हैं, साथ ही नाखुश राजनयिकों के साथ पर्दे के पीछे की ब्रीफिंग तक पहुंच शामिल है। और 'डीलक्स टियर' पूर्ण अमेरिकी प्रतिबद्धता प्रदान करता है ... जब तक कि आप मेजबान के साथ अच्छे संबंध में हैं, और जब तक आपका रक्षा बजट उसकी मनमानी और हमेशा बदलने वाली मांगों को पूरा नहीं करता। ट्रम्प के पतवार पर होने के साथ, यहां तक कि अमेरिका के सबसे करीबी सहयोगी भी यह सोचकर रह जाते हैं कि, 'क्या हमने गलती से अमेरिका को सब्सक्राइब कर लिया है, या सिर्फ द अपरेंटिस का एक और सीज़न?'

ट्रम्प की विदेश नीति की दृष्टि में एक मौलिक तत्व का अभाव है: एक नैतिक कम्पास, सही और गलत की एक भावना जो स्वार्थ की संकीर्ण खोज से परे है। वह यह नहीं पूछता है कि गठबंधन किस लिए खड़े हैं - केवल यह कि वे ठोस लाभ के मामले में क्या देते हैं। लेकिन नाटो कभी भी आरओआई के बारे में नहीं था, लाभ को अधिकतम करने और जोखिम को कम करने के बारे में। यह सामूहिक संकल्प के बारे में था, जो खून में जाली था और विश्वास से बंधा था, एक सामान्य दुश्मन के खिलाफ साझा मूल्यों की रक्षा के लिए एक प्रतिबद्धता। तालियों की पंक्तियों और क्षणिक राजनीतिक लाभों के लिए इसे कमजोर करना न केवल अज्ञानी है - यह ऐतिहासिक रूप से अश्लील है, उन पीढ़ियों द्वारा किए गए बलिदानों के साथ विश्वासघात है जिन्होंने एक अधिक शांतिपूर्ण और सुरक्षित दुनिया बनाने के लिए संघर्ष किया।

यदि नाटो अंततः ट्रम्प के अहंकार और लेन-देन दृष्टिकोण के वजन के नीचे ढह जाता है, तो इतिहास इसे केवल एक वित्तीय असहमति के रूप में याद नहीं रखेगा। यह इसे उस एक देश द्वारा विश्वासघात के रूप में याद रखेगा जिसने कभी इसे एक साथ रखा था, नेतृत्व की एक दुखद विफलता जिसने दुनिया को और अधिक कमजोर, और अधिक विभाजित और अधिक खतरनाक बना दिया। •

ट्रम्प का अहंकार धरती का संताप

डोनाल्ड ट्रम्प की सत्ता में संभावित वापसी दुनिया के लिए एक जलवायु तबाही के रूप में उभर रही है, जिससे दशकों की प्रगति को पलटने और अमेरिका की नेतृत्व भूमिका को खत्म करने का खतरा है। दूसरा ट्रम्प प्रशासन अमेरिका को पेरिस समझौते और अन्य महत्वपूर्ण जलवायु पहलों से बाहर निकालने के लिए तैयार है, यह सिर्फ एक नीतिगत बदलाव नहीं है; यह वैश्विक मंच पर आत्मदाह का एक विनाशकारी कृत्य है, जो वैज्ञानिकों, राजनयिकों और विश्व नेताओं से निंदा खींच रहा है जो हमारे ग्रह को छोड़ने के गहरे खतरों को पहचानते हैं।

ऐतिहासिक रूप से, संयुक्त राज्य अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण प्रोटोकॉल को आकार देने में एक प्रमुख खिलाड़ी रहा है, क्योटो प्रोटोकॉल से (इसके बाद में अस्वीकृति के बावजूद) राष्ट्रपति ओबामा के तहत पेरिस जलवायु समझौते तक। इन प्रतिबद्धताओं

ने अमेरिकी कूटनीतिक ताकत का अनुमान लगाया, स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा दिया और जलवायु-संवेदनशील राष्ट्रों के लिए वैश्विक वित्त पोषण को जुटाया। 2017 में ट्रम्प की पेरिस समझौते से शुरुआती वापसी एक नाटकीय प्रस्थान थी। दूसरी वापसी वैश्विक कल्याण पर संकीर्ण राष्ट्रवाद को प्राथमिकता देते हुए, अमेरिका की धारणा को एक अविश्वसनीय भागीदार के रूप में ठोस करती है।

ट्रम्प का ₹अमेरिका फर्स्ट₹ सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से ऊपर अल्पकालिक घरेलू औद्योगिक विकास को रखता है, जिसमें दावा किया गया है कि जलवायु समझौते ₹अनुचित आर्थिक बोझ₹ डालते हैं जबकि चीन और भारत जैसे राष्ट्रों को अप्रतिबंधित रूप से बढ़ने की अनुमति देते हैं। यह दृष्टिकोण निष्क्रियता की दीर्घकालिक वैश्विक आर्थिक और पर्यावरणीय लागतों को अनदेखा करता है, जलवायु परिवर्तन से निपटने में सहयोगात्मक नेतृत्व के रणनीतिक मूल्य को खारिज करता है।

पर्यावरणीय परिणाम गंभीर हैं। अमेरिका की वापसी अंतरराष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों को कमजोर करती है, जिससे वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के पेरिस समझौते के लक्ष्य को खतरा है। अमेरिकी नेतृत्व और वित्त पोषण के बिना, जलवायु-संवेदनशील राष्ट्र अनुकूलन के लिए संघर्ष करते हैं। निकास ग्रीन क्लाइमेट फंड, लॉस एंड डैमेज फंड और जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप (JETP) जैसी महत्वपूर्ण वित्त पोषण तंत्र में अमेरिकी भागीदारी को रोक देता है, जिससे जलवायु वित्त पोषण में अरबों डॉलर का अंतर आ जाता है। टाइम्स यूनियन सही ढंग से तर्क देता है कि ट्रम्प का रोलबैक वैश्विक जिम्मेदारी से एक व्यापक वापसी का संकेत देता है, जिससे 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार करने और पारिस्थितिक तंत्र, खाद्य सुरक्षा और मानव स्वास्थ्य के लिए अपरिवर्तनीय परिणामों को ट्रिगर करने का खतरा बढ़ जाता है।

राजनयिक और रणनीतिक पतन अपरिहार्य है। यूरोपीय संघ, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के नेताओं ने अमेरिका

की जलवायु नीति उलटफेर के अस्थिर प्रभावों के बारे में चिंता व्यक्त की है। जैसा कि आगामी COP30 शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष आंद्रे कोरिया डो लागो ने द गार्जियन में उल्लेख किया है, अमेरिका की अनुपस्थिति से अन्य देशों के लिए अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करना मुश्किल हो जाएगा, जिससे बहुपक्षीय वार्ताओं की विश्वसनीयता कम हो जाएगी। इस शक्ति निर्वात का चीन द्वारा आसानी से फायदा उठाया गया है, जिसने रणनीतिक रूप से नवीकरणीय ऊर्जा में भारी निवेश करते हुए खुद को एक जलवायु चैंपियन के रूप में स्थापित किया है। फाइनेंशियल टाइम्स ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे यूरोपीय संघ और चीन ने दक्षिण अफ्रीका के ऊर्जा संक्रमण का समर्थन करने के लिए कदम बढ़ाया, जब अमेरिका ने अपनी JETP प्रतिबद्धताओं को छोड़ दिया, एक बैंड-सहायता समाधान जो अमेरिका के कमजोर प्रभाव को रेखांकित करता है।

आर्थिक और तकनीकी रूप से, जलवायु समझौतों से हटने से अमेरिकी हितों में बाधा आती है। हरित प्रौद्योगिकी एक पर्यावरणीय अनिवार्यता और एक प्रमुख विकास क्षेत्र दोनों है। दुनिया के नवीकरणीय ऊर्जा की ओर रुख करने पर अमेरिकी कंपनियों को स्वच्छ ऊर्जा नवाचार में यूरोपीय और एशियाई समकक्षों से पीछे रहने का खतरा है। नीतिगत व्हिपलैश के कारण होने वाली नियामक अस्थिरता निजी क्षेत्र के निवेश को भी हतोत्साहित करती है। वाशिंगटन पोस्ट ने खुलासा किया कि सरकार से मिश्रित संकेत निवेशक विश्वास को कम करते हैं, खासकर उन क्षेत्रों में जिनके लिए दीर्घकालिक प्रतिबद्धताओं की आवश्यकता होती है, जिससे नवाचार और पूंजी स्थिर, दूरंदेशी जलवायु नीतियों वाले देशों में धकेल दी जाती है।

विकासशील देशों पर प्रभाव विशेष रूप से विनाशकारी है। जलवायु परिवर्तन उन देशों को असमान रूप से प्रभावित करता है जिन्होंने संकट में सबसे कम योगदान दिया है। अमेरिकी नेतृत्व और वित्त पोषण अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और प्रशांत द्वीप समूह में शमन और अनुकूलन रणनीतियों का समर्थन करने में महत्वपूर्ण रहे हैं। वित्त पोषण की अचानक रोक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, आपदा लचीलापन योजनाओं और कृषि सुधारों को खतरे में डालती है। एपी न्यूज और विश्व संसाधन संस्थान की रिपोर्ट है कि अमेरिकी योगदान की अनुपस्थिति वैश्विक प्रगति में काफी देरी करती है, जिससे यूरोपीय संघ और अन्य दाता राष्ट्रों पर अनुचित दबाव पड़ता है और वैश्विक जलवायु वित्त की स्थिरता के बारे में सवाल उठते हैं।

ट्रम्प की कार्रवाई जवाबदेही, सहयोग और साझा जिम्मेदारी के दिल पर प्रहार करते हुए नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को कमजोर करती है। जियोपॉल रिपोर्ट का तर्क है कि ऐसी कार्रवाई अन्य देशों को अपनी अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं से इनकार करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे संभावित रूप से एक डोमिनो प्रभाव शुरू हो सकता है जो दशकों की राजनयिक प्रगति को उजागर करता है, जलवायु परिवर्तन पर सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता को देखते हुए एक विशेष रूप से खतरनाक संभावना है।

अंत में, अमेरिका की वैश्विक छवि इस वापसी से ग्रस्त है। जलवायु समझौतों से हटने से अमेरिका एक उदार महाशक्ति के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को धूमिल करता है। अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक अमेरिका के प्रति वैश्विक विश्वास में गिरावट दिखाते हैं, खासकर युवाओं और नागरिक समाज संगठनों के बीच। अमेरिकी जलवायु नेतृत्व के प्रतीकात्मक मूल्य को कम करके नहीं आंका जा सकता है। इसका प्रस्थान प्रवर्तन को कमजोर करता है और एक संदेश भेजता है कि अल्पकालिक राजनीतिक लाभ दीर्घकालिक वैश्विक जिम्मेदारियों से अधिक हैं। •

अमेरिकी मीडिया
ट्रंप के शासन में परीक्षा

राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प के अधीन एक लोकतांत्रिक सरकार और एक स्वतंत्र प्रेस के बीच तनाव खुले तौर पर शत्रुता में बदल गया, जिनके प्रशासन ने मीडिया संस्थानों और पत्रकारिता की अखंडता पर अभूतपूर्व हमला किया। यह सिर्फ भड़काऊ बयानबाजी नहीं थी; यह गुप्त सेंसरशिप और धमकी देने जैसा था, जिसने अमेरिकी लोकतंत्र को कमजोर किया और मुक्त अभिव्यक्ति के प्रतीक के रूप में इसकी वैश्विक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया।

ट्रम्प ने 'फर्जी खबर' शब्द को हथियार बनाया, इसका उपयोग किसी भी महत्वपूर्ण कवरेज को खारिज करने और सम्मानित आउटलेट को 'लोगों के दुश्मन' के रूप में ब्रांड करने के लिए किया। इससे पत्रकारों के प्रति शत्रुता भड़क गई, एक ठंडक पैदा हो गई और सार्वजनिक विश्वास कम हो गया। उनके प्रशासन ने सेंसरशिप के सीमावर्ती व्यावहारिक कदम भी उठाए, प्रेस ब्रीफिंग को नाटकीय रूप से कम कर दिया, सूचना तक पहुंच को प्रतिबंधित कर दिया और पत्रकारों को ब्लैकलिस्ट कर दिया। सीएनएन के पत्रकार जिम अकोस्टा के प्रेस क्रेडेंशियल्स को रद्द करना इस बात पर प्रकाश डालता है कि प्रशासन कथा को नियंत्रित करने के लिए कानूनी और नैतिक सीमाओं को धक्का देने के लिए कितना तैयार था।

ट्रम्प ने पारंपरिक मीडिया फिल्टर को बायपास करने और गलत सूचना, साजिश के सिद्धांतों और व्यक्तिगत अपमान फैलाने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करके जांच से बचने के लिए सोशल मीडिया का शोषण किया। इस व्यवहार ने जहरीले प्रवचन को सामान्य कर दिया और सामाजिक विभाजनों को गहरा कर दिया। उनके प्रशासन ने व्हिसलब्लोअर और सरकारी लीकर्स को भी निशाना बनाया, अमेरिकी इतिहास में किसी भी अन्य की तुलना में अधिक लीक मामलों पर मुकदमा चलाया और खोजी पत्रकारिता को दबा दिया, जो गोपनीय स्रोतों पर निर्भर करती है।

इसके अलावा, ट्रम्प प्रशासन ने वैज्ञानिक और सार्वजनिक स्वास्थ्य जानकारी को दबा दिया। COVID-19 महामारी के दौरान, सरकारी वैज्ञानिकों को दरकिनार कर दिया गया या चुप करा दिया गया, और राजनीतिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी को विकृत कर दिया गया, जिससे जानमाल का नुकसान हुआ और राजनीतिक सुविधा के लिए सत्य को अधीनस्थ करने के खतरों का प्रदर्शन हुआ।

इन कार्यों के वैश्विक परिणाम हुए। मीडिया के प्रति ट्रम्प के जुझारू रुख ने सत्तावादी शासन को असंतोष को चुप कराने और मीडिया पर कार्रवाई को उचित ठहराने के लिए एक सुविधाजनक मिसाल प्रदान की, जिससे अमेरिका के नैतिक अधिकार का क्षरण हुआ।

हमले के बावजूद, अमेरिकी पत्रकारिता ने लचीलापन दिखाया, खोजी रिपोर्टिंग महत्वपूर्ण मुद्दों को उजागर करती है और मीडिया आउटलेट राष्ट्रपति की तथ्य-जांच करके और सहयोगी रिपोर्टिंग प्रयासों को मजबूत करके अनुकूल होते हैं। प्रोपब्लिका, एनपीआर और द अटलांटिक जैसे संगठनों ने तथ्यात्मक अखंडता और नागरिक जवाबदेही बनाए रखने में अपनी भूमिका का विस्तार किया।

हालांकि ट्रम्प का प्रभाव बना हुआ है। मीडिया ध्रुवीकरण तीव्र बना हुआ है, और सार्वजनिक बहस में उनकी निरंतर उपस्थिति यह सुनिश्चित करती है कि प्रेस के प्रति विरोध बना रहे। पत्रकारिता में विश्वास को बहाल करना और लोकतंत्र की आधारशिला के रूप में मीडिया की भूमिका को मजबूत करना एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है। ट्रम्प प्रशासन के मीडिया के साथ शत्रुतापूर्ण संबंध ने राष्ट्र के लोकतांत्रिक ताने-बाने को खतरे में डाल दिया। •

जैसे-जैसे वैश्विक संकट गहराते जा रहे हैं, अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी (USAID) मानवीय सहायता और भू-राजनीतिक स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण शक्ति बनी हुई है। लेकिन अब इसके वित्त पोषण में भारी कटौती दशकों की प्रगति को समाप्त करने की धमकी दे रही है। यह लेख USAID के वित्तीय समर्थन को समाप्त करने के विनाशकारी मानवीय, कानूनी और रणनीतिक परिणामों की पड़ताल करता है—और यह दर्शाता है कि जब अमेरिका विश्व मंच से पीछे हटता है, तो दांव पर क्या-क्या लग जाता है।

USAID में कटौती वैश्विक तबाही

मानवता की कीमत पर बजट की चाल, अमेरिका की उदासीनता का खामियाजा

यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (USAID) वैश्विक विकास और अमेरिकी विदेश नीति के एक रणनीतिक हथियार के रूप में एक आधारशिला है। दशकों से, इसने भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतिभार के रूप में सेवा करते हुए गरीबी, बीमारी और अस्थिरता से लड़ाई लड़ी है। हालाँकि, USAID के वित्त पोषण में हालिया भारी कटौती केवल सार बजट समायोजन नहीं हैं; वे विनाशकारी मानवीय, कानूनी और रणनीतिक परिणामों वाले निर्णय हैं जो वैश्विक परिदृश्य को फिर से आकार देने के लिए तैयार हैं। यह लेख इन परिणामों की पड़ताल करता है, USAID की डिफंडिंग द्वारा शुरू किए गए सामने आ रहे संकट को उजागर करता है।

मानवीय टोल: रोके जा सकने वाली मौतों की बढ़ती लहर

USAID में कटौती का सबसे तत्काल और हृदयविदारक प्रभाव मानव जीवन का विनाशकारी नुकसान है। एक भयावह फाइनेंशियल टाइम्स की जांच में 2025 में पूरे अफ्रीका में मलेरिया के मामलों में वृद्धि की भविष्यवाणी की गई है, जिसका अनुमान है कि राष्ट्रपति की मलेरिया पहल की डिफंडिंग से 1.3 करोड़ से अधिक संक्रमण और 100,000 से अधिक रोके जा सकने वाली मौतें हो सकती हैं, जिनमें मुख्य रूप से पांच साल से कम उम्र के बच्चे शामिल हैं। यह भयावह पूर्वानुमान बजटीय निर्णय को एक गहरे नैतिक विफलता में बदल देता है।

मलेरिया से परे, HIV/AIDS, तपेदिक, मातृ स्वास्थ्य और आवश्यक टीकाकरण अभियानों से निपटने वाले महत्वपूर्ण कार्यक्रम कगार पर डगमगा रहे हैं। ऑक्सफैम ने सही ढंग से कटौती को ₹क्रूर₹ और ₹जानबूझकर हानिकारक₹ के रूप में लेबल किया, यह जोर देते हुए कि USAID

HIV/AIDS के साथ रहने वाले 16 लाख से अधिक लोगों के लिए जीवन रक्षक उपचार प्रदान करता है और ऐतिहासिक रूप से कमजोर क्षेत्रों से पोलियो, खसरा और अन्य घातक बीमारियों को खत्म करने के प्रयासों का नेतृत्व किया है।

द टाइम्स की रिपोर्ट में भयावह वास्तविकता आगे बढ़ती है कि लगभग 300,000 मौतें, जिनमें 200,000 से अधिक बच्चे शामिल हैं, अप्रत्यक्ष रूप से USAID समर्थित कार्यक्रमों की समाप्ति के कारण हो सकती हैं। ये सट्टा आंकड़े नहीं हैं; वे स्वास्थ्य परिणामों

पर निरंतर समर्थन की पिछली अवधियों के बाद देखे गए प्रभाव पर आधारित गंभीर अनुमान हैं। जैसा कि माय जर्नल कूरियर चेतावनी देता है, अगर यह प्रक्षेपवक्र अगले 10-15 वर्षों तक जारी रहता है, तो दुनिया स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता और पोषण में समय पर सहायता की अनुपस्थिति के कारण अतिरिक्त 2.5 करोड़ मौतों को देख सकती है। USAID की डिफंडिंग केवल लागत में कटौती का उपाय नहीं है; यह आवश्यक सहायता पर निर्भर अनगिनत व्यक्तियों के लिए मौत की सजा है।

राजनीतिक और कानूनी धक्का: एक संवैधानिक तंग रस्सी

USAID की कटौती ने न केवल मानवीय आक्रोश को भड़काया है; उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर ही एक गरमागरम राजनीतिक और कानूनी लड़ाई को प्रज्वलित किया है। आलोचकों का तर्क है कि कार्यकारी शाखा ने उन निधियों को फ्रीज या पुनः आवंटित करके अपनी संवैधानिक अधिकारिता का अतिक्रमण किया है जिन्हें कांग्रेस द्वारा स्पष्ट रूप से अनुमोदित किया गया था। शक्तियों के पृथक्करण की यह चुनौती अदालतों तक पहुंच गई है। •

अमेरिका का पाकिस्तान मोह

एक भ्रामक रणनीति

हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर के प्रति दिखाई गई गर्मजोशी ने नई दिल्ली में कूटनीतिक हलकों में हलचल पैदा कर दी। यह मुलाकात केवल एक औपचारिक राजनयिक शिष्टाचार नहीं थी, बल्कि एक गहरी रणनीतिक योजना का हिस्सा थी, जिसे भारत ने गंभीरता से देखा है। क्या यह अमेरिका की ओर से एक कुशल रणनीतिक चाल थी, या फिर शीतयुद्ध काल की पुरानी गलतफहमियों की पुनरावृत्ति?

हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर के बीच हुई मुलाकात केवल एक सामान्य कूटनीतिक घटना नहीं थी। इसे एक ऐसी रणनीतिक चाल के रूप में देखा जाना चाहिए जो दिखने में आकर्षक, परंतु भीतर से अत्यंत सतही और खतरनाक है। ट्रंप ने इस मुलाकात को 'सम्मान की बात' बताया और यह कहा कि पाकिस्तानी ईरान को बाकियों की अपेक्षा बेहतर जानते हैं। यह कथन केवल एक औपचारिक प्रशंसा नहीं थी; यह एक स्पष्ट संकेत था कि अमेरिका एक बार फिर पाकिस्तान को पश्चिम एशिया में अपने रणनीतिक हितों के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है।

भारत की नजरों से अमेरिका-पाकिस्तान समीकरण

भारत इस पूरे घटनाक्रम को एक ठंडे और साफ दिमाग से देख रहा है। न तो किसी हड़बड़ी में प्रतिक्रिया दी गई, न ही सार्वजनिक रूप से कोई तीखा विरोध। भारत समझता है कि पाकिस्तान की असल ताकत उसकी लोकतांत्रिक सरकार में नहीं, बल्कि उसकी सेना में निहित है। यही कारण है कि अमेरिका की ओर से बार-बार सेना प्रमुखों को तवज्जो दी जाती है, न कि निर्वाचित नेताओं को। ट्रंप द्वारा मुनीर को व्हाइट हाउस में भोज पर बुलाना इस प्रवृत्ति का ताजा उदाहरण है।

यह अमेरिका की पुरानी आदत है

- 1950-60 के दशक में जनरल अयूब खान से लेकर 1980 के दशक में जनरल ज़िया-उल-हक़ तक — अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान की सेना को अपने रणनीतिक एजेंडे में प्राथमिकता दी है। परंतु भारत जानता है कि इन सैन्य गठबंधनों ने कभी भी दीर्घकालिक शांति या स्थायित्व नहीं लाया। उल्टे, ये अस्थिरता, आतंकवाद, और अविश्वास की नींव बने।

ईरान और इज़राइल की पृष्ठभूमि में पाकिस्तान की भूमिका

ट्रंप का यह कथन कि 'पाकिस्तान ईरान को बेहतर समझता है', केवल एक सामान्य कूटनीतिक टिप्पणी नहीं, बल्कि पश्चिम एशिया में एक संभावित सैन्य समीकरण की ओर संकेत करता है। अमेरिका और इज़राइल, दोनों की नजरें इस समय ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर हैं। ऐसे में पाकिस्तान की सेना को, जिसकी सार्वजनिक छवि इस्लामी एकजुटता की समर्थक है, अमेरिका एक ऐसे 'गुप्त सहयोगी' के रूप में देख रहा है जो पर्दे के पीछे से सहयोग कर सकता है।

परंतु यह दृष्टिकोण अत्यंत खतरनाक है। पाकिस्तान की जनता में ईरान को लेकर सहानुभूति है, और इज़राइल के प्रति विरोध की भावना है। ऐसे में पाक सेना की कोई भी संभावित साझेदारी, देश के अंदर सामाजिक-राजनीतिक उथल-पुथल का कारण बन सकती है। ट्रंप प्रशासन या उनके रणनीतिकार यदि यह सोच रहे हैं कि मुनीर जैसे जनरल ईरान के खिलाफ किसी गोपनीय गठजोड़ में अमेरिका का साथ देंगे, तो यह उनकी बड़ी भूल हो सकती है।

एक सैन्य जनरल को मानसिक बढ़त देना

ट्रंप और मुनीर के बीच भोज महज़ एक औपचारिक मुलाकात नहीं थी, बल्कि एक प्रकार का मानसिक तुष्टीकरण था। ट्रंप का उद्देश्य साफ था — मुनीर की अहंकार-तुष्टि कर उसे एक उपयोगी रणनीतिक मोहरे में बदलना। ट्रंप भले ही खुद को भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध टालने वाला 'नायक' बताते रहें, पर सच्चाई यह है कि भारत ने उनके इस दावे को तुरंत खारिज कर दिया। भारत को किसी मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं है — विशेषकर तब, जब वह आत्मनिर्भर रणनीतिक स्थिति में है।

इस मुलाकात का समय भी चिंताजनक है। पश्चिम एशिया में अगर इज़राइल कोई बड़ा सैन्य अभियान शुरू करता है, तो ट्रंप पाकिस्तान को इस योजना में एक 'सहायक कड़ी' के रूप में देख सकते हैं। ऐसे में भारत को सतर्क रहना होगा कि कहीं यह नया समीकरण दक्षिण एशिया में अस्थिरता न फैला दे।

भारत के लिए रणनीतिक संकेत

इस घटनाक्रम से भारत के लिए कुछ स्पष्ट रणनीतिक संदेश निकलते हैं:

• पाकिस्तान की सेना आज भी देश का सबसे संगठित और प्रभावशाली तंत्र है, जो विदेश नीति, आंतरिक सुरक्षा, और परमाणु कार्यक्रमों पर एकाधिकार रखती है।

• अमेरिका, विशेषकर ट्रंप जैसे नेता, अब भी पाकिस्तान को एक 'सुविधाजनक साझेदार' के रूप में देखते हैं — भले ही उसका लोकतंत्र, मानवाधिकार, या आतंकी संबंध कितने भी संदिग्ध क्यों न हों।

• भारत को यह समझना होगा कि अमेरिका की विदेश नीति अवसरवादी और अल्पकालिक लक्ष्यों पर आधारित रहती है। ट्रंप जैसे नेता अपनी शर्तों पर गठबंधन करते हैं, जिनमें दीर्घकालिक स्थिरता का कोई स्थान नहीं होता।

इसके अतिरिक्त, भारत को यह भी स्पष्ट समझ होना चाहिए कि अमेरिका का यह रुख सिर्फ पाकिस्तान के संदर्भ में ही नहीं है, बल्कि उसकी वैश्विक कूटनीति में एक व्यापक प्रवृत्ति को दर्शाता है — जिसमें वह चीन को संतुलित करने के प्रयास में किसी भी देश का तात्कालिक उपयोग कर लेता है। यही कारण है कि भारत को पश्चिम की 'रणनीतिक गारंटी' पर पूरी तरह निर्भर न रहकर आत्मनिर्भर सुरक्षा नीति विकसित करनी होगी।

भारत की रणनीति: आत्मविश्वास और वैश्विक सहयोग

भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह अब पाकिस्तान के साथ किसी भी प्रकार की 'समानता' को नकारता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ट्रंप के भ्रामक बयानों को सिरे से खारिज करना यही दर्शाता है कि भारत अब 'पाकिस्तान-भारत' समीकरण से ऊपर उठ चुका है। दोनों देशों में अब केवल भौगोलिक सामीप्य है, न कि कोई राजनीतिक या रणनीतिक समानता।

भारत को अब और भी गंभीरता से वैश्विक सहयोग को मजबूत करना होगा — अमेरिका पर पूर्ण निर्भरता की बजाय यूरोपीय संघ, फ्रांस, जापान, खाड़ी देशों, और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ बहुपक्षीय साझेदारी को बढ़ावा देना ज़रूरी है। इसके साथ-साथ दक्षिण एशिया में बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और भूटान जैसे पड़ोसी देशों के साथ भी स्थायी आर्थिक-सामरिक सहयोग की नींव डालनी होगी, ताकि क्षेत्रीय संतुलन भारत के पक्ष में बना रहे। साथ ही, अमेरिका और पश्चिम को यह समझाना आवश्यक है कि यदि वे वास्तव में चीन के प्रभाव का संतुलन चाहते हैं, तो पाकिस्तान जैसे अस्थिर और सैन्य-प्रभुत्व वाले देश पर नहीं, बल्कि भारत जैसे लोकतांत्रिक और संस्थागत रूप से मजबूत देश पर भरोसा करना होगा। •

ईरान पर परमाणु प्रसार का आरोप लगाते हुए इजराइल ने ईरान पर जो हमला किया उसमें अमेरिका भी ना-नुकर के साथ शामिल हुआ। क्या कुछ घंटों का युद्ध ईरान के परमाणु बम बनाने की क्षमता को खत्म कर दिया है या फिर कुछ महीनों या सालों के बाद उसका परमाणु कार्यक्रम पुनर्जीवित हो उठेगा? या एक सवाल यह भी उठता है कि क्या क्षेत्रीय प्रतिरोध को कुचलने, प्रभुत्व सुनिश्चित करने, और एक उपनिवेशवादी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ईरान के साथ वहीं छल दोहराया जा रहा है जो जो इराक के विनाश का कारण बना था? इराक से लेकर ईरान तक, ₹स्वतंत्रता₹ और ₹लोकतंत्र₹ जैसे शब्द कहीं गहरे साम्राज्यवादी मंसूबों को छिपाने के लिए तो इस्तेमाल नहीं किये जा रहे हैं....

पश्चिम एशिया
युद्ध एवं प्रभुत्व की कूटनीति

इज़राइल ने दावा किया कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम से उसका अस्तित्व खतरे में है। यह दलील 2003 में अमेरिका द्वारा इराक पर हमले के लिए इस्तेमाल की गई रणनीति की याद दिलाती है—₹सामूहिक विनाश के हथियार₹ का हवाला, जो बाद में मिथ्या सिद्ध हुआ। इज़राइल ने एकतरफा सैन्य कार्रवाई कर अंतरराष्ट्रीय कानून और वैश्विक जनमत की उपेक्षा की।

इज़राइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के नेतृत्व में किया गया यह हमला 'पूर्व-सावधानी' के नाम पर न्यायोचित ठहराया जा रहा है, जबकि वस्तुतः यह पश्चिम एशिया में शक्ति संतुलन को तोड़ने और वर्चस्व स्थापित करने की एक साज़िश है। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) की रिपोर्टों के अनुसार, ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को शांतिपूर्ण उद्देश्यों तक सीमित रखने की प्रतिबद्धता जताई है, फिर भी इजराइल के संदेह और सैन्य कार्रवाइयां क्षेत्र को अस्थिर करने का काम कर रही हैं।

अमेरिका की भूमिका एक बार फिर दोमुंही रही है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियाँ मानती हैं कि ईरान परमाणु हथियारों से अभी

दूर है, जबकि राजनीतिक नेतृत्व इज़राइल के दावों को समर्थन देता रहा। यह विरोधाभास अमेरिका की रणनीतिक असमंजस नहीं, बल्कि सोची-समझी चाल का हिस्सा लगता है, जिसमें वह पश्चिम एशिया में तनाव बनाए रखकर हथियारों का व्यापार, कूटनीतिक हस्तक्षेप और अपने सैन्य ठिकानों की मौजूदगी को कायम रखना चाहता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (एसआईपीआरआई) के अनुसार, अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक है, और पश्चिम एशिया उसके हथियारों का एक महत्वपूर्ण बाजार है।

डोनाल्ड ट्रंप की दोबारा अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में वापसी वैश्विक कूटनीति के परिदृश्य में एक तीव्र मोड़ का संकेत देती है।

ट्रंप की विदेश नीति का मूल स्वर हमेशा 'अमेरिका फर्स्ट' रहा है, जिसकी परिणति अक्सर बहुपक्षीय समझौतों से हटने, साझेदार देशों पर दबाव बढ़ाने और विरोधी राष्ट्रों के खिलाफ आर्थिक व सैन्य धमकियों के रूप में हुई है।

ट्रंप प्रशासन ने 2018 में ईरान परमाणु समझौते (जेसीपीओए) से एकतरफा हटकर ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाए थे। यह कदम न केवल एक कूटनीतिक असफलता थी, बल्कि उसने पश्चिम एशिया को अस्थिरता के नए दौर में धकेल दिया। ट्रंप की दृष्टि में ईरान ₹सभी बुराइयों की जड़₹ है, जबकि इज़राइल उनका प्राथमिक सहयोगी। इस अतिवादी वर्गीकरण ने अमेरिकी नीति को और अधिक पक्षपाती बना दिया है।

2025 में ट्रंप की वापसी के बाद एक बार फिर यह डर सतह पर आ गया है कि अमेरिका ईरान के साथ किसी भी समझौते की दिशा में नहीं जाएगा। उनकी टीम में शामिल कुछ व्यक्तित्व को भले ही प्रगतिशील कहा जाता हों, लेकिन विदेश नीति में ट्रंप का रवैया अब भी कठोर राष्ट्रवाद और शक्ति के प्रयोग की वकालत करता है।

उनकी इस सोच में बहुपक्षीय संगठनों की भूमिका गौण होती है और संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं को वे अमेरिका की 'बाधा' मानते हैं। यदि यही सोच पश्चिम एशिया में लागू होती है, तो आने वाले वर्षों में इज़राइल को खुली छूट मिल सकती है और ईरान पर सैन्य कार्रवाई को 'वैध ठहराने' का अमेरिकी प्रयास फिर तेज़ हो सकता है।

वहीं दूसरी ओर, चीन ने इस पूरे प्रकरण में न केवल ईरान की संप्रभुता का समर्थन किया, बल्कि इज़राइल की सैन्य कार्रवाई की निंदा करते हुए इस संकट का शांतिपूर्ण समाधान सुझाया। चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में स्पष्ट रुख अपनाते हुए इसे 'सैन्य दुस्साहसिकता' और क्षेत्रीय शांति के लिए 'गंभीर

खतरा' बताया।

चीन ने ईरानी और इज़राइली विदेश मंत्रियों से अलग-अलग बात कर यह भी स्पष्ट कर दिया कि वह क्षेत्रीय स्थिरता में रुचि रखता है, न कि सैन्य टकराव में। यह कूटनीति चीन की बहुपक्षीय अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण को रेखांकित करती है। चीन की इस पहल को वैश्विक समुदाय में व्यापक समर्थन मिला है।

ईरान और चीन के बीच 2021 में हुआ 25-वर्षीय रणनीतिक सहयोग समझौता, जिसमें ऊर्जा, व्यापार, आधारभूत ढांचा, तकनीक और रक्षा शामिल हैं, इस क्षेत्र में एक नया ध्रुव उभरने की ओर संकेत करता है। चीन, अमेरिका के प्रतिबंधों के बावजूद, ईरान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना हुआ है और उसके लगभग 70% तेल का आयात करता है (जनवरी 2024 तक)।

हालाँकि इस साझेदारी में चुनौतियाँ भी हैं — अधूरी परियोजनाएँ, तकनीकी सीमाएँ और क्षेत्रीय अस्थिरता। लेकिन चीन का समर्थन ईरान के लिए एक वैश्विक मंच पर सामरिक ढाल का कार्य करता है। यह समर्थन ईरान को अंतरराष्ट्रीय दबाव का सामना करने में मदद करता है।

ईरान पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। 2015 में बना जॉइंट कॉम्प्रिहेन्सिव प्लान ऑफ एक्शन (जेसीपीओए) इसका प्रमाण है, जिसे ट्रंप प्रशासन ने 2018 में एकतरफा छोड़ दिया था। अब ट्रंप की वापसी के बाद यह आशंका बनी हुई है कि अमेरिका फिर से ईरान पर दबाव बनाएगा, जिससे पश्चिम एशिया में नया संकट पैदा हो सकता है।

मार्च 2025 में चीन, रूस और ईरान के उप-विदेश मंत्रियों की बीजिंग बैठक में जेसीपीओए आधारित समाधान और अमेरिका के एकतरफा प्रतिबंधों की आलोचना की गई। यह पहल न केवल एक कूटनीतिक संतुलन प्रस्तुत करती है, बल्कि पश्चिमी प्रभाव को संतुलित करने का प्रयास भी है।

भारत के लिए ट्रंप एक दोधारी तलवार की तरह हैं। एक ओर, वह चीन-विरोधी रणनीति में भारत को साझेदार बनाना चाहते हैं, दूसरी ओर, पश्चिम एशिया में उनकी अतिवादी नीति भारत की ऊर्जा सुरक्षा, प्रवासी सुरक्षा और व्यापार मार्गों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। भारत की रणनीति को इसलिए अधिक सतर्क और संतुलित होना होगा—ना तो अमेरिकी खेमे में पूरी तरह झुकना, और ना ही ईरान जैसे ऐतिहासिक साझेदारों को खो देना।

भारत पारंपरिक रूप से ईरान और इज़राइल दोनों का साझेदार रहा है। चाबहार बंदरगाह परियोजना और ऊर्जा साझेदारी में भारत की भागीदारी ईरान के साथ उसके संबंधों को रणनीतिक गहराई

इज़राइल द्वारा ईरान पर हमला अंतरराष्ट्रीय कानून की अनदेखी और क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ावा देने वाला कदम है। यह कार्रवाई अमेरिका की उस रणनीति की पुनरावृत्ति प्रतीत होती है जो इराक पर हमले के समय अपनाई गई थी। जबकि अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों में ईरान का परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण बताया गया है, इज़राइल के संदेह और अमेरिका का पक्षपाती रवैया संकट को गहरा कर रहा है। ट्रंप की वापसी के बाद यह आशंका प्रबल हो गई है कि अमेरिका फिर किसी समझौते के बजाय दबाव की नीति अपनाएगा। दूसरी ओर, चीन ने शांतिपूर्ण समाधान की वकालत करते हुए ईरान का समर्थन किया है और वैश्विक मंचों पर सैन्य दुस्साहस का विरोध किया है। भारत के लिए यह स्थिति चुनौतीपूर्ण है क्योंकि उसे अमेरिका, ईरान, इज़राइल और चीन के बीच संतुलन साधना है।

देती है। वहीं रक्षा तकनीक, साइबर सुरक्षा और कृषि तकनीक में इज़राइल के साथ भारत का सहयोग सुदृढ़ है।

परंतु जब बात पश्चिम एशिया में तनाव की आती है, तो भारत का रुख स्पष्ट और संतुलित रहा है — "संप्रभुता का सम्मान, अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन, और संघर्ष का कूटनीतिक समाधान।" भारत को न केवल इस क्षेत्र में रहने वाले लाखों भारतीयों की सुरक्षा की चिंता रहती है, बल्कि वैश्विक तेल आपूर्ति और व्यापारिक मार्गों की स्थिरता भी उसके लिए प्रमुख विषय है।

ईरान और खाड़ी देशों से भारत को होने वाली तेल और गैस आपूर्ति पर कोई संकट, भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रत्यक्ष प्रभाव डाल सकता है। खाड़ी और पश्चिम एशिया में करोड़ों भारतीय कामगार हैं। क्षेत्रीय युद्ध या अस्थिरता से उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 2023 में लगभग 80 लाख भारतीय नागरिक खाड़ी देशों में कार्यरत थे। भारत को अमेरिका, इज़राइल, ईरान, और चीन — चारों के साथ अपने संबंधों में संतुलन बनाना होता है। अतः भारत किसी भी एक पक्ष का अंध समर्थन नहीं कर सकता। अब यह स्पष्ट होता जा रहा है कि पश्चिम एशिया में किसी भी समस्या का सैन्य समाधान नहीं है। अमेरिका और इज़राइल की एकतरफा कार्रवाइयाँ केवल अस्थिरता को बढ़ा रही हैं। वहीं चीन जैसे देश शांतिपूर्ण समाधान की राह सुझा रहे हैं, जो भारत की 'वसुधैव कुटुम्बकम्' और 'शांति के सह-अस्तित्व' की परंपरा से मेल खाती है।

ईरान ने इजराइल और अमेरिकी सैन्य कार्रवाइयों का जवाब दिया है, लेकिन जवाबी कार्रवाई का स्तर सीमित रहा है। यह आवश्यक है कि वैश्विक मंचों पर उसकी संप्रभुता और अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज़ उठाई जाए। यह भारत जैसे लोकतांत्रिक और बहुध्रुवीयता समर्थक राष्ट्र की भूमिका हो सकती है कि वह वैश्विक मंचों पर ऐसे टकरावों की कूटनीतिक रोकथाम के लिए पहल करे।

ईरान और इज़राइल के टकराव ने फिर यह दिखा दिया है कि अराजकता को एक रणनीति की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है — एक ऐसा औजार जो युद्ध को नहीं, बल्कि प्रभुत्व की पुनःस्थापना को लक्ष्य बनाता है। भारत को इस वैश्विक पटल पर अपनी आवाज़ को मजबूती से रखते हुए यह स्पष्ट करना होगा कि सैन्य टकरावों की नहीं, शांति और सहयोग की सदी की आवश्यकता है। यह वही दृष्टिकोण है जो भारत को वैश्विक नेतृत्व की ओर ले जा सकता है — न्याय, संतुलन और समरसता के पथ पर। भारत को न केवल पश्चिम एशिया में बल्कि दुनिया भर में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए एक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। •

अफ्रीका: सैन्य शासन का नया युग

लोकतंत्र की संभावनाओं पर संकट

अफ्रीका के साहेल क्षेत्र में सैन्य तख्तापलट एक बार फिर तेजी से उभर रहे हैं, जो सरकारों को गिरा रहे हैं और भू-राजनीतिक सीमाओं को नए सिरे से परिभाषित कर रहे हैं। असुरक्षा, भ्रष्टाचार और वैश्विक गठबंधनों में बदलाव की पृष्ठभूमि में उठी यह जुंटा लहर लोकतंत्र के लिए खतरा बन गई है, अस्थिरता को और गहरा कर रही है और महाद्वीप में शक्ति-संतुलन के नाटकीय पुनर्गठन का संकेत दे रही है।

श्रेया गुप्ता

पिछले कुछ वर्षों में अफ्रीका, विशेष रूप से सहेल क्षेत्र, में सैन्य तख्तापलट की बाढ़ सी आ गई है। एक समय जिस महाद्वीप को लोकतंत्र की ओर बढ़ते हुए देखा जा रहा था, वहां अब सैन्य शासन का एक नया युग उभर रहा है। माली, बुर्किना फासो, चाड और नाइजर जैसे देशों में लोकतांत्रिक सरकारें गिर चुकी हैं और सैनिक सत्ता में आ चुके हैं। यह स्थिति न केवल अफ्रीका की राजनीति को प्रभावित कर रही है, बल्कि क्षेत्रीय गठबंधनों, वैश्विक रिश्तों और लोकतंत्र की संभावनाओं को भी गहराई से चुनौती दे रही है।

2020 से 2024 के बीच बढ़ते तख्तापलट

इस अवधि में अफ्रीका में कम से कम नौ सफल सैन्य तख्तापलट हो चुके हैं। इनमें माली (2020, 2021), गिनी (2021), बुर्किना फासो (2022 में दो बार), चाड (2021), नाइजर (2023) और गैबॉन (2023) शामिल हैं। इन तख्तापलटों के पीछे एक जैसी ही वजहें रही हैं — सरकारों में व्याप्त भ्रष्टाचार, बढ़ती असुरक्षा, आर्थिक संकट और सत्ता से आम नागरिकों की बढ़ती दूरी।

शहरों में आम जनता ने इन सैन्य तख्तापलटों का कई बार खुले दिल से स्वागत किया है। माली की राजधानी बामाको और नाइजर की राजधानी नियामे में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और सैनिकों को 'उद्धारकर्ता' के रूप में देखा। कुछ प्रदर्शनकारियों ने तो रूसी झंडे भी लहराए, जो एक बड़े वैश्विक भू-राजनीतिक परिवर्तन की ओर संकेत करता है।

क्यों बढ़ रहे हैं सैन्य तख्तापलट?

सुरक्षा तंत्र का पतन

सहेल क्षेत्र इस समय जिहादी आतंकवाद का गढ़ बन चुका है। अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकी संगठन लगातार अपने पांव पसार रहे हैं, जबकि सरकारें सुरक्षा बहाल करने में विफल रही हैं। बुर्किना फासो में लगभग आधा देश सरकार के नियंत्रण से बाहर है। इस खालीपन का फायदा सैन्य ताकतों ने उठाया और खुद को एकमात्र ₹उपायश्र के रूप में प्रस्तुत किया।

असफल लोकतांत्रिक शासन

गिनी और गैबॉन जैसे देशों में चुनावों की निष्पक्षता पर सवाल उठे हैं। भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और संस्थानों की गिरती हालत ने लोगों का लोकतंत्र से विश्वास उठाया है। कुछ देशों में सत्ता वंश परंपरा में बदल चुकी थी, जिससे युवा वर्ग और आम जनता में गुस्सा और मोहभंग पैदा हुआ।

वैश्विक शक्तियों की भूमिका

रूस ने वैगनर ग्रुप के माध्यम से इन देशों में सैन्य सहयोग दिया, जो बिना किसी लोकतांत्रिक शर्तों के आता है। माली और बुर्किना फासो में रूसी समर्थन ने फ्रांसीसी और अमेरिकी प्रभाव को पूरी तरह चुनौती दी है।

वहीं, चीन ने अपने गैर-हस्तक्षेप वाले दृष्टिकोण के चलते इन सैन्य सरकारों के साथ भी आर्थिक संबंध बनाए रखे हैं। उसने आधारभूत ढांचे में निवेश जारी रखा है, जो इन देशों को बहुत लुभाता है।

इसके विपरीत, पश्चिमी देशों — विशेषकर फ्रांस और अमेरिका — का प्रभाव कमजोर हो गया है। फ्रांस को कई देशों से बाहर कर दिया गया है और अमेरिकी प्रतिबंध भी कोई बड़ा असर नहीं दिखा पाए हैं। अब पश्चिम को अपनी रणनीति पर फिर से विचार करना पड़ रहा है, जहां लोकतांत्रिक आदर्श और सुरक्षा की व्यावहारिकता के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है।

लोकतंत्र की गिरावट

इन सैन्य तख्तापलटों को केवल क्षणिक राजनीतिक घटनाएं मानना भूल होगी। यह एक गहरे संकट की ओर इशारा कर रहे हैं, जहां सैन्य शासन सामान्य होता जा रहा है। कई देशों में, जैसे माली और बुर्किना फासो, सैनिक सरकारों ने वादा किया था कि वे जल्दी चुनाव कराएंगे, लेकिन बार-बार इसे टालते रहे हैं।

क्षेत्रीय संगठन जैसे ECOWAS और अफ्रीकी संघ (AU) इन तख्तापलटों पर प्रभावी प्रतिक्रिया देने में असमर्थ साबित हुए हैं। प्रतिबंधों का असर सीमित रहा है और लोकतंत्र की बहाली की प्रक्रिया कहीं खो गई है।

मानवाधिकार और सुरक्षा की कीमत

इन तख्तापलटों से यह अपेक्षा थी कि सुरक्षा की स्थिति सुधरेगी, लेकिन इसके विपरीत आतंकवाद और हिंसा में बढ़ोतरी देखी गई है। सैनिक सरकारों का ध्यान राजनीतिक नियंत्रण पर केंद्रित है, जिससे आतंकी विरोधी अभियानों में तालमेल की कमी आई है। संयुक्त सैन्य अभियान बिखर गए हैं और आतंकवाद के खिलाफ क्षेत्रीय संघर्ष कमजोर हो गया है।

इसके साथ ही, मानवीय संकट और गहरा गया है। पांच मिलियन से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं और खाद्य संकट गहराता जा रहा है। हिंसा के चलते कृषि कार्य बाधित हो गया है और राहत सामग्री भी प्रभावित हो रही है।

सहेल से आगे: संक्रमण का खतरा

सहेल क्षेत्र से यह लहर अब अफ्रीका के अन्य हिस्सों में फैलने लगी है। गैबॉन का 2023 का तख्तापलट भ्रष्टाचार और वंशवादी राजनीति के विरोध में हुआ था। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि यदि शासन व्यवस्था में कोई ठोस सुधार नहीं होता, तो अन्य कमजोर लोकतंत्र भी इसी रास्ते पर जा सकते हैं।

लोकतंत्र को फिर से खड़ा करने की राह

अफ्रीकी नेतृत्व की भूमिका

ECOWAS और अफ्रीकी संघ को केवल प्रतिबंधों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उन्हें संस्थागत सुधारों, सुशासन, और सुरक्षा प्रशिक्षण में सहायता प्रदान करनी चाहिए ताकि सैन्य हस्तक्षेप के बजाय लोकतांत्रिक रास्ता अपनाने की प्रेरणा मिले।

लोकतंत्र में भरोसा बहाल करना

नागरिक सरकारों को यह साबित करना होगा कि वे केवल वादे करने वाली संस्थाएं नहीं हैं। युवाओं को रोजगार, शिक्षा, और बुनियादी सेवाएं मुहैया कराना अब सबसे जरूरी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ ठोस कदम उठाना भी अनिवार्य है।

वैश्विक भागीदारी का पुनर्मूल्यांकन

पश्चिमी देशों को अब अफ्रीका के साथ अपने संबंधों को एक संरक्षक की तरह नहीं, बल्कि साझेदार के रूप में देखना होगा। वहीं रूस और चीन जैसे देशों की बढ़ती भूमिका को समझते हुए, एक संतुलित कूटनीति की आवश्यकता है। यह कोई शीत युद्ध नहीं, बल्कि सहयोग और प्रतिस्पर्धा का नया मॉडल है।

निर्णायक मोड़ पर अफ्रीका

अफ्रीका में लोकतंत्र पर संकट एक गंभीर चेतावनी है। यह दशकों की असफल सरकारों, सुरक्षा संकटों, और बाहरी प्रभावों का परिणाम है। यह केवल सैन्य तख्तापलट की श्रृंखला नहीं, बल्कि अफ्रीका के भविष्य की दिशा तय करने वाला एक मोड़ है। •

श्रेया गुप्ता वर्तमान में कल्ट करंट में पत्रकारिता कर रही हैं और वैश्विक राजनीति पर पैनी दृष्टि रखती हैं।

ढाका की नई राह

दिल्ली से दूरी, इस्लामाबाद से नज़दीकी

Sohini Bose

जो कभी युद्धभूमि में दुश्मन थे, वही पाकिस्तान और बांग्लादेश अब एक आश्चर्यजनक रक्षा साझेदारी की ओर बढ़ रहे हैं — जो दक्षिण एशिया की सामरिक शक्ति-संतुलन को बदल सकती है। एक अलोकतांत्रिक अंतरिम सरकार के तहत, ढाका अपनी विदेश नीति को पुनर्परिभाषित कर रहा है — इस्लामाबाद के साथ बढ़ते संवाद और नई दिल्ली से बनती दूरी के ज़रिये। संयुक्त सैन्य अभ्यासों से लेकर संभावित हथियार सौदों तक, यह बदलाव केवल सामरिक सहयोग का संकेत नहीं है, बल्कि बांग्लादेश की राष्ट्रीय पहचान की एक नई व्याख्या है, जिसकी छाया क्षेत्रीय शांति और भारत की सुरक्षा रणनीति पर गहराई से पड़ सकती है।

पूर्व में युद्धरत रहे पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) की सेनाओं के बीच अब रक्षा सहयोग की संभावनाएँ उभर रही हैं। अंतरिम सरकार, जिसके प्रमुख चीफ एडवाइज़र मुहम्मद यूनुस हैं, बांग्लादेश की विदेश नीति को 1971 में मिली स्वतंत्रता के बाद की पारंपरिक पाकिस्तान-विरोधी सोच से अलग दिशा में ले जा रही है।

पिछले 55 वर्षों में ढाका ने अधिकांश समय इस्लामाबाद से दूरी

जनवरी के अंत में: पाकिस्तान की ISI के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल शाहिद आमिर अफसर ने ढाका का दौरा किया — यह ISI और बांग्लादेश के बीच दशकों में पहला उच्च-स्तरीय संवाद था।

फरवरी 2025: बांग्लादेश का युद्धपोत BNS समुद्र जॉय 'Aman 25' नौसैनिक अभ्यास में शामिल हुआ, जो कराची के निकट अरब सागर में आयोजित किया गया था। इसमें चीन, म्यांमार और श्रीलंका समेत करीब 120 देशों ने हिस्सा लिया।

भाषण और रणनीतिक संकेत

बनाए रखी, सिवाय 2001–2006 के उस दौर के जब बीएनपी–जमात-ए-इस्लामी गठबंधन सत्ता में था। 2009 में जब अवामी लीग शेख हसीना के नेतृत्व में सत्ता में लौटी (जो बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की पुत्री हैं), तो उन्होंने पाकिस्तान के साथ न्यूनतम राजनयिक संबंध बनाए रखे। यह सिलसिला अगस्त 2024 तक चला, जब अवामी लीग सत्ता से बाहर हुई। इसके बाद, अंतरिम सरकार ने 'अवामी परंपराओं' से सायास दूरी बनाई और एक नई राष्ट्रीय पहचान की रूपरेखा गढ़ने का प्रयास शुरू किया।

आधिकारिक दौरों और सैन्य समीकरण

हाल के महीनों में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच कई रक्षा संबंधी वार्ताओं और गतिविधियों ने रिश्तों में गर्मजोशी का संकेत दिया है:

जनवरी 2025: 14 जनवरी: लेफ्टिनेंट जनरल एस.एम. कामरुल हसन के नेतृत्व में बांग्लादेश की सैन्य टीम ने रावलपिंडी में पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल सैयद आसिम मुनिर और जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा से मुलाकात की।

15 जनवरी: ले. जनरल हसन ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान के वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात की। बातचीत में क्षेत्रीय सुरक्षा, संयुक्त अभ्यास, प्रशिक्षण और रक्षा व्यापार पर ज़ोर दिया गया।

अमन संवाद 2025 में बांग्लादेश के नौसेना प्रमुख एडमिरल मोहम्मद हसन ने कहा:

'ज़मीन हमें विभाजित करती है, लेकिन समुद्र जोड़ता है।'

यह बयान पाकिस्तान की सेना की 'भाई भाई' वाली भाषा से मेल खाता है, और एक नई सामरिक समझदारी की ओर संकेत करता है।

पाकिस्तान ने बांग्लादेश को सैन्य प्रशिक्षण देने की पेशकश की है। वहीं ढाका अपनी 'Forces Goal 2030' योजना के तहत JF 17 थंडर लड़ाकू विमान खरीदने में रुचि दिखा रहा है, जिसे पाकिस्तान और चीन ने मिलकर विकसित किया है। उल्लेखनीय है कि 2010–2020 के बीच चीन बांग्लादेश का और 2020–2024 में पाकिस्तान का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता रहा है।

परंपरागत रूप से ढाका संतुलित कूटनीति का पक्षधर रहा है — भारत और चीन दोनों के साथ रिश्ते बनाए रखकर। लेकिन अब नई सरकार ने नई दिल्ली से दूरी बना ली है, विशेषकर ज़िला-नरेशा विवाद और एयरबेस परियोजनाओं जैसे मुद्दों के बाद।

भारत के लिए संभावित चिंता

अगर पाकिस्तान का प्रभाव बांग्लादेश में बढ़ता है, तो यह भारत के लिए सुरक्षा चुनौती बन सकता है — विशेष रूप से पूर्वोत्तर, पश्चिम बंगाल और बंगाल की खाड़ी के संदर्भ में।

अप्रैल 2025 में हुए पालगाम आतंकी हमले में भारत ने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया और 'ऑपरेशन सिंदूर' नाम से जवाबी कार्रवाई की। इससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया।

हालांकि ढाका ने आतंकवाद के खिलाफ प्रतिबद्धता जताई है, लेकिन कुछ विवादित टिप्पणियाँ, जैसे मेजर जनरल (रिटायर्ड) ए.एल.एम. फ़ज़लुर रहमान का यह बयान कि 'अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करे, तो बांग्लादेश को पूर्वोत्तर के सात राज्यों पर कब्ज़ा कर लेना चाहिए', क्षेत्रीय शांति के लिए चिंताजनक हैं। यद्यपि बांग्लादेश सरकार ने इन टिप्पणियों को खारिज किया, लेकिन उनके असर को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।

इस बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मुहम्मद आसिफ बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे, जबकि विदेश मंत्री इशाक दार का दौरा स्थगित रहा।

नई राष्ट्रीय पहचान की कीमत

अंतरिम सरकार द्वारा 'हर ओर संवाद' की नीति अपनाना कूटनीतिक रूप से तार्किक लग सकता है, लेकिन दो महत्वपूर्ण प्रश्न उठते हैं:

क्या ढाका भू-राजनीतिक यथार्थ को नज़रअंदाज़ कर सकता है?

भारत बांग्लादेश का सबसे बड़ा पड़ोसी है। साझा नदियाँ, संस्कृति, व्यापार और सैन्य सहयोग (जैसे 'सम्प्रीति' अभ्यास) दोनों देशों को जोड़ते हैं। इन संबंधों को कमज़ोर करना पूरे क्षेत्र में असंतुलन ला सकता है।

क्या एक गैर-निर्वाचित सरकार ऐसे दूरगामी निर्णय ले सकती है?

2011 में बांग्लादेश के संविधान में संशोधन कर 'कैरेटेकर सरकारों' को समाप्त किया गया था। हालांकि हालिया न्यायिक निर्णयों ने इसकी आंशिक वापसी की अनुमति दी है, लेकिन वर्तमान प्रशासन निर्वाचित नहीं है। ऐसे में इसके निर्णयों की वैधता लोकतांत्रिक दृष्टि से सवालों के घेरे में है।

निष्कर्ष

बांग्लादेश की सेना-केंद्रित विदेश नीति में यह नया मोड़ — पाकिस्तान और चीन के साथ बढ़ता सहयोग और भारत से बढ़ती दूरी — दक्षिण एशिया की सामरिक स्थिरता को प्रभावित कर सकता है। यह अब भारत की प्रतिक्रियाओं और बांग्लादेश की आगामी निर्वाचित सरकार की दिशा पर निर्भर करेगा कि यह बदलती दोस्ती भविष्य में कैसी शक्ल लेती है। •

सोहिनी बोस, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ORF), कोलकाता में स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ प्रोग्राम की एसोसिएट फेलो हैं। उनका शोध भारत के पूर्वी समुद्री पड़ोस, बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर में कनेक्टिविटी, भू-राजनीति और सुरक्षा के विषयों पर केंद्रित है।

A platform dedicated to geopolitical and global affairs, as well as analysis related to India and Indianness

CULT CURRENT

WE MAKE VIEWS

Join the YouTube channel ›

https://www.youtube.com/@cultcurrentindia

लाल सागर का संकट
एक वैश्विक जोखिम

धनिष्ठा डे

वर्ष 2023 की अंतिम तिमाही से, लाल सागर समुद्री गलियारा यमन के हूती विद्रोहियों की शत्रुता द्वारा उकसाए गए एक गहरे भू-राजनीतिक बवंडर में डूब गया है, जो तेहरान के साथ गठबंधन वाली एक गैर-राज्य शक्ति है। गाजा के साथ घोषित एकजुटता के रूप में जो शुरू हुआ, वह जल्द ही वाणिज्यिक शिपिंग को लक्षित करने और सुरक्षित व्यापार मार्गों को बनाए रखने की दुनिया की क्षमता को चुनौती देने वाले एक संकर युद्ध में बदल गया। हूतियों ने अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग लेन पर हमलों की एक श्रृंखला का आयोजन किया है, विशेष रूप से इजरायल, संयुक्त राज्य अमेरिका और नाटो कंसोर्टियम के भीतर प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ सीधे या स्वामित्व, पंजीकरण या

फिलहाल रेड सी संकट का व्यापार और कीमतों पर प्रभाव सीमित है।

चार्टर समझौतों के माध्यम से जुड़े वाणिज्यिक जहाजों को लक्षित किया है।

लाल सागर संकट, जैसा कि इसे जाना जाने लगा है, यमन के लंबे समय से चल रहे गृह युद्ध, ईरानी प्रभाव और इजरायल-हमास संघर्ष के बाद क्षेत्रीय विरोध में वृद्धि के एक अस्थिर संगम से उपजा है। इस संकट के केंद्र में हूती आंदोलन है, जो उत्तरी यमन में स्थापित ईरान समर्थित जैदी शिया समूह है।

हूती (अंसार अल्लाह) उत्तरी यमन में स्थित एक जैदी शिया समूह है, जिसका नेतृत्व अब्दुल मलिक अल-हूती करते हैं, जो हमास और हिजबुल्लाह के साथ ईरान के 'प्रतिरोध अक्ष' का हिस्सा है। 1990 के दशक में पहली बार उभरने और 2014 के तख्तापलट में यमन की राजधानी सना पर नियंत्रण करने के बाद, यह समूह एक शक्तिशाली संकर बल में विकसित हो गया है, जो यमन के भीतर निहित है, लेकिन पूरे क्षेत्र में तेजी से प्रभावशाली है। उनकी ताकत को ईरानी हथियारों, मिसाइल और ड्रोन प्रौद्योगिकी और रूसी उपग्रह खुफिया जानकारी से कथित सहायता द्वारा प्रबलित किया गया है।

'प्रतिरोध अक्ष' के बैनर तले अपनी कार्रवाइयों को तैयार करते हुए, हूतियों ने अपने नौसैनिक अभियान को गाजा के साथ एकजुटता के कार्य के रूप में प्रस्तुत किया, खुद को बदलते भू-राजनीतिक उतार-चढ़ावों के समुद्री एजेंट के रूप में डब किया, जिसका इरादा इजरायली आपूर्ति श्रृंखलाओं और पश्चिमी व्यापार मार्गों को बाधित करना था।

इस संकट को पूर्ववर्ती हॉटस्पॉट से अलग करने वाली बात इसकी निरंतरता और सटीकता है जिसके साथ हूतियों ने अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्गों को एक सामरिक थिएटर और प्रतिरोध के मंच दोनों के रूप में हथियार बनाया है। एक उल्लेखनीय उदाहरण नवंबर 2023 में बहामियन ध्वज वाले वाहन वाहक द गैलेक्सी लीडर का अपहरण है।

लाल सागर, भू-राजनीतिक रूप से अरब प्रायद्वीप और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बीच स्थित है, इसमें एक प्रमुखता है जो इसकी स्थलाकृतिक विनम्रता को धता बताती है।

यमन और जिबूती के बीच स्थित बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य, एक संकीर्ण लेकिन महत्वपूर्ण अड़चन है जिसके माध्यम से वैश्विक समुद्री वाणिज्य का लगभग 12% गुजरता है, जिसमें वैश्विक कंटेनर शिपमेंट का लगभग 30% और कच्चे तेल, तरलीकृत प्राकृतिक गैस और अनाज की पर्याप्त मात्रा शामिल है। लगातार हमलों के मद्देनजर, मर्सक, एमएससी और सीएमए सीजीएम जैसी बहुराष्ट्रीय शिपिंग निगमों को केप ऑफ गुड होप के आसपास जहाजों को फिर से रूट करने के लिए मजबूर होना पड़ा, एक विचलन जो विशिष्ट एशिया-यूरोप यात्राओं में 3,000 समुद्री मील और 10 से 14 दिनों के बीच जोड़ता है। लॉयड की लिस्ट इंटेलिजेंस ने 2024 की शुरुआत में स्वेज नहर यातायात में 68% की गिरावट की सूचना दी।

इस खतरे को बेअसर करने के प्रयास में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूरोपीय सहयोगियों और खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) राज्यों के समर्थन से, विमान वाहक, विध्वंसक और उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणालियों की तैनाती के माध्यम से दिसंबर 2023 के अंत में ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन नामक एक बहुराष्ट्रीय नौसेना गठबंधन का गठन किया। CENTCOM द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों से संकेत मिलता है कि अभियान की शुरुआत के बाद से 700 से अधिक आने वाले खतरों को इंटरसेप्ट किया गया है, जिसमें मानवरहित हवाई वाहन और एंटी-शिप बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल हैं। अप्रैल 2025 में अमेरिकी कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस द्वारा जारी एक गोपनीय ब्रीफिंग का अनुमान है कि क्षेत्र में अमेरिकी समुद्री अभियानों पर कुल व्यय 1.6 अरब डॉलर से अधिक हो गया है, जिससे इन उपायों की लागत-प्रभावशीलता और दीर्घकालिक स्थिरता दोनों पर चिंता बढ़ गई है।

अरब गणराज्य मिस्र, स्वेज नहर का संरक्षक और उत्तर-दक्षिण समुद्री निरंतरता का द्वारपाल, अब एक राजकोषीय और भू-रणनीतिक दुविधा की खाई पर डगमगा रहा है। 2023 के अंत से स्वेज नहर के थ्रूपुट में 40% से अधिक का संकुचन, केप ऑफ गुड होप की ओर शिपिंग लेन के पुनर्गठन से उत्पन्न एक घर्षण के साथ, मिस्र के खजाने को विदेशी मुद्रा अंतर्वाह में एक महत्वपूर्ण कमी का सामना करना पड़ता है। यह नहर दुनिया के व्यापार का 12% है, संकट से पहले नहर से वार्षिक राजस्व लगभग 9.4 अरब डॉलर के करीब है। समुद्री निरंतरता के व्यवधान ने एक आर्थिक रक्तस्राव का कारण बना दिया है, जिससे मिस्र के पहले से ही अनिश्चित राजकोषीय माहौल में वृद्धि हुई है। मिस्र की सरकार समुद्र में हूती हमलों में वृद्धि को अपनी शक्ति और अरब दुनिया की स्थिरता के लिए एक गंभीर खतरे के रूप में देखती है। यह सिनाई क्षेत्र में फैलने वाली संभावित विद्रोही गतिविधि और सूडान के साथ इसकी अस्थिर दक्षिणी सीमा के बारे में इसकी चिंताओं को भी बढ़ाता है।

सऊदी अरब साम्राज्य खुद को निरोध और अस्थिरता के बीच एक अंतःक्रिया में पाता है। बीजिंग के राजनयिक हस्तक्षेप के माध्यम से इस्लामिक गणराज्य ईरान के साथ एक समझौता कराने के बाद, रियाद ने अपने क्षेत्रीय रुख को फिर से समायोजित करने की उम्मीद जताई। फिर भी, हूती मिसाइल हमले और नौसैनिक नाकाबंदी अभी भी सऊदी क्षेत्र की सीमा से लगे यमनी प्रांतों से निकलती रहती है, जो शांति प्रस्तावों पर एक निराशा डालती है। सऊदी अरब, कभी पूर्ण पैमाने पर सैन्य कार्रवाई पर केंद्रित था, अब एक अधिक सतर्क और व्यावहारिक दृष्टिकोण में बदल गया है। यह यमन में लंबे युद्ध से पीछे हटना चाहता है, जबकि अभी भी क्षेत्र में एक प्रमुख शक्ति बना हुआ है। इसलिए, इसकी कार्रवाइयां सीमित और लक्षित रही हैं। साम्राज्य चुपचाप ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन जैसे पश्चिमी प्रयासों का समर्थन करता है लेकिन ईरान के साथ अपनी नाजुक शांति की रक्षा के लिए सीधे वृद्धि से बचता है।

दक्षिण-पूर्व में, जिबूती गणराज्य बाब अल-मंडेब चोकपॉइंट में अतिरिक्त-क्षेत्रीय सैन्य उपस्थिति के लिए फुलक्रम के रूप में कार्य करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, फ्रांस और जापान से गैरीसन की मेजबानी करते हुए, जिबूती का संप्रभु परिदृश्य विदेशी घुसपैठ और अतिव्यापी भू-राजनीतिक सिद्धांतों के एक पलीमसेस्ट में विकसित हो गया है। यद्यपि सैन्य किरायेदारों का यह ब्रिकोलज स्पष्ट रूप से निवारक सुनिश्चित करता है, जिबूती को आर्थिक बर्बादी की चपेट में रहता है, क्या क्षेत्रीय अस्थिरता बंदरगाह-आधारित राजस्व को बाधित करती है, मुख्य रूप से इथियोपियाई व्यापार से जमा होते हैं।

चीन का रुख पश्चिमी आक्रामकता से स्पष्ट रूप से अलग है। बीजिंग ने खुले नौसैनिक जुड़ाव से परहेज किया है और इसके बजाय पीआरसी-ध्वजांकित जहाजों की सुरक्षा के लिए

हूती मध्यस्थों से गैर-आक्रामकता गारंटी हासिल की है।

भारत भी नतीजों से बोझिल है। यूरोपीय बाजारों में जेनेरिक फार्मास्युटिकल्स, वस्त्र और ऑटोमोटिव घटकों के एक प्रमुख निर्यातक के रूप में, नई दिल्ली के मालवाहक जहाजों को अब रसद संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। शिपिंग मार्गों के अब दक्षिणी अफ्रीका के चारों ओर चक्कर लगाने के साथ, व्यवसायों को उच्च लागत और लंबी डिलीवरी समय का सामना करना पड़ रहा है, जिससे आपूर्ति श्रृंखलाएं असंतुलित हो रही हैं और समय सीमा को खतरा है। जवाब में, भारतीय अधिकारियों ने ईरान और मध्य एशियाई देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए तेजी से कदम उठाया है, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) को पुनर्जीवित करना है, जो तेजी से अप्रत्याशित स्वेज मार्ग के लिए एक अधिक स्थिर विकल्प प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक व्यापार मार्ग है।

शंघाई कंटेनरयुक्त फ्रेट इंडेक्स ने वर्ष 2023 के अंत में लगभग 1,500 अमरीकी डालर प्रति TEU से पूर्वी एशिया-यूरोप दरों में वर्ष 2024 के मध्य तक 5,000 अमरीकी डालर से अधिक की वृद्धि दर्ज की। भूमध्यसागरीय बेसिन में समाप्त होने वाले मार्गों में USD 6,800 प्रति TEU के करीब शिखर देखे गए, जिससे ऑटोमोटिव निर्माण से लेकर उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स तक के क्षेत्रों में मुद्रास्फीति शुरू हो गई।

समुद्री सुरक्षा के बढ़ते खतरों और धीमी गति से हो रहे व्यापार के बीच, एक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रयास ने आकार ले लिया है, हालांकि सदस्य राज्यों के बीच एकता कमजोर बनी हुई है। हालांकि समुद्र के कानून पर 1982 का संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCLOS) नेविगेशन को विनियमित करने के लिए एक आधारशिला बना हुआ है, लेकिन यह आधुनिक खतरों से निपटने में कम पड़ता है-विशेष रूप से गैर-राज्य समूह अब सैन्य-ग्रेड हथियारों से लैस हैं। कैम्ब्रिज, हीडलबर्ग और साइंसेज पो जैसे संस्थानों के कानूनी विशेषज्ञ एक नए ढांचे का आह्वान कर रहे हैंः एक प्रस्तावित चौथा जिनेवा समुद्री प्रोटोकॉल। इससे समुद्र में विद्रोही समूहों की कानूनी स्थिति को परिभाषित करने, प्रतिक्रिया के लिए स्पष्ट नियम स्थापित करने और अधिक समन्वित अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई की अनुमति देने में मदद मिलेगी। लाल सागर में संकट एक सीमांत विद्रोही समूह द्वारा हमलों की एक श्रृंखला से अधिक है, यह एक स्पष्ट अनुस्मारक है कि वैश्विक व्यापार मार्ग वास्तव में कितने कमजोर हैं, और समुद्रों पर नियंत्रण कितनी जल्दी बदल सकता है। लंबे समय से चली आ रही समुद्री व्यवस्था, इस विश्वास पर बनी है कि राज्य नियमों का पालन करेंगे और पानी को सुरक्षित रखेंगे, टूटने लगी है। जैसे-जैसे जहाज तेजी से शत्रुतापूर्ण जल में पालते हैं, वे न केवल सामान का परिवहन कर रहे हैं, बल्कि वे संप्रभुता, अंतर्राष्ट्रीय कानून और टकराती विश्वदृष्टि के बारे में अनसुलझे सवालों का भार भी उठा रहे हैं। •

धनिष्ठा डे एक जिज्ञासु पत्रकार हैं, जो वर्तमान में कल्ट करंट में अपना योगदान दे रही हैं।

भारत की वैश्विक कूटनीति
नेहरू की विरासत या मोदी की दृष्टि?

रिया गोयल

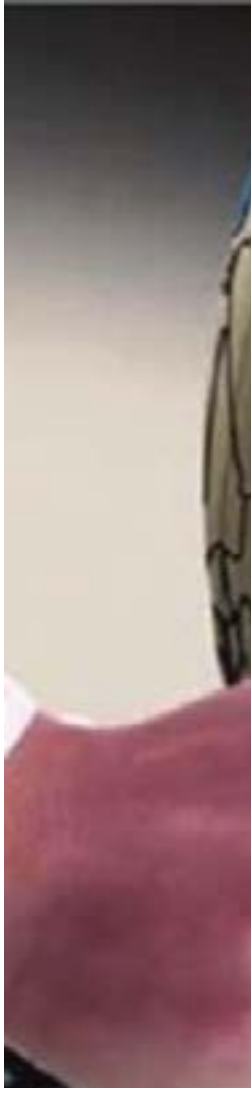

1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही भारत ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति की जटिल दुनिया में एक संतुलित और विवेकपूर्ण विदेश नीति अपनाई है, जो उसके ऐतिहासिक अनुभवों, भौगोलिक-राजनीतिक यथार्थों और वैश्विक प्रभाव की आकांक्षाओं से प्रेरित रही है। भारत की विदेश नीति को लेकर वैश्विक स्तर पर सदैव उत्सुकता रही है कि यह देश अपनी संप्रभुता की रक्षा करते हुए अंतरराष्ट्रीय शक्तियों से किस प्रकार संवाद स्थापित करता है। शीत युद्ध के समय में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा गुटनिरपेक्षता की नीति की शुरुआत ने भारत को महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा से दूर रखते हुए नव-स्वतंत्र और तीसरी दुनिया के देशों की आवाज बनने का मंच प्रदान किया।

हालांकि हाल के दशकों में वैश्विक संघर्षों के प्रति भारत का दृष्टिकोण बदलता हुआ दिख रहा है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या भारत की वर्तमान तटस्थ स्थिति नेहरूवादी गुटनिरपेक्षता की पुनरावृत्ति है या फिर आर्थिक और भूराजनीतिक हितों से प्रेरित रणनीतिक राष्ट्रवाद की एक व्यावहारिक दिशा?

नेहरूवादी गुटनिरपेक्षता: उत्पत्ति और सिद्धांत

शीत युद्ध के दौर में जब विश्व दो ध्रुवों—अमेरिका और सोवियत संघ—में बँटा हुआ था, उस समय नव-स्वतंत्र भारत ने अपनी संप्रभुता और विकास के लक्ष्यों की रक्षा के लिए किसी भी गुट से न जुड़ने का निर्णय लिया। नेहरू ने इस नीति को यूगोस्लाविया के तितो और मिस्र के नासिर के साथ मिलकर 1961 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) के रूप में औपचारिक रूप दिया।

गुटनिरपेक्षता का उद्देश्य केवल सैन्य गुटों से दूरी बनाए रखना नहीं था, बल्कि सभी देशों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाते हुए किसी भी प्रकार के संघर्ष में पड़ने से बचना भी था। भारत ने इस नीति के अंतर्गत अमेरिका और सोवियत संघ दोनों के साथ सहयोग बनाए रखा। उदाहरणस्वरूप, 1962 के भारत-चीन युद्ध के समय भारत ने अमेरिका से सहायता मांगी, वहीं 1971 में भारत-सोवियत मैत्री संधि पर भी हस्ताक्षर किए। इससे स्पष्ट होता है कि गुटनिरपेक्षता में लचीलापन था, जहां राष्ट्रीय सुरक्षा को विचारधारा पर प्राथमिकता दी गई।

यह नीति गांधी के शांति और अहिंसा के सिद्धांतों तथा भारत के औपनिवेशिक संघर्ष से प्रेरित पंचशील के पांच मूल सिद्धांतों—संप्रभुता का सम्मान, आक्रामकता से दूर रहना, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, समानता और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व—पर आधारित थी। गुटनिरपेक्षता अलगाव नहीं थी, बल्कि यह रणनीतिक स्वतंत्रता और वैश्विक शांति की दिशा में एक कदम थी।

इस नीति ने भारत को लचीलापन, स्वतंत्रता और नैतिक नेतृत्व का मंच दिया। भारत ने नवस्वतंत्र देशों के पक्ष में आवाज उठाकर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर एक नैतिक नेतृत्व की भूमिका निभाई। हालांकि आलोचकों ने इसे "अवसरवाद" और "आदर्शवाद" करार दिया, और चीन जैसी शक्तियों के उदय के समय इसे खतरे से निपटने में अक्षम बताया।

भारत की विदेश नीति का विकास: गुटनिरपेक्षता से बहुपक्षीय साझेदारी तक

1990 के दशक के बाद भारत की कूटनीति ने एक नए यथार्थवादी और व्यावहारिक रास्ते पर कदम रखा। सोवियत संघ के विघटन ने उस गुटनिरपेक्ष आधार को हिला दिया जिस पर भारत की विदेश नीति टिकी हुई थी। इसके साथ ही 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिंहराव द्वारा शुरू किए गए आर्थिक उदारीकरण ने भारत को वैश्विक पूंजीवादी व्यवस्था से जोड़ दिया। अब द्विध्रुवीय दुनिया के लिए बनी गुटनिरपेक्ष नीति पुरानी और सीमित लगने लगी थी।

1990 का दशक: रणनीतिक संक्रमण

1990 के दशक में भारत की विदेश नीति अधिक व्यवहारिक और हित-आधारित होती चली गई। इसका स्पष्ट संकेत 1998 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा पोखरण परमाणु परीक्षण के निर्णय में मिला, जिसने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है।

इस समय तक चीन का विस्तार और पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को समर्थन भी भारत को अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी की ओर ले जाने लगे। 2008 का भारत-अमेरिका परमाणु समझौता भारत की पूर्ववर्ती हिचकिचाहट से हटकर एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। इससे भारत को वैश्विक स्तर पर परमाणु शक्ति के रूप में मान्यता मिली और अमेरिका के साथ सहयोग का नया अध्याय खुला।

भारत ने इस दौर में आसियान, जी-15 जैसे बहुपक्षीय मंचों में सक्रियता दिखाई और क्षेत्रीय प्रभाव भी बढ़ाया। "रणनीतिक स्वायत्तता" (Strategic Autonomy) का विचार गुटनिरपेक्षता की जगह लेने लगा। इसका लाभ यह हुआ कि भारत अब अमेरिका, रूस, ईरान और इज़राइल जैसे विभिन्न स्वभाव वाले देशों के साथ समानांतर संबंध बना सका।

मोदी सिद्धांत: बहुपक्षीय संरेखण की ओर रुझान

साल 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति में एक नए, अधिक सक्रिय और बहुआयामी दृष्टिकोण का उदय हुआ। इसे अक्सर ₹मल्टी-अलाइनमेंट₹ या ₹सर्व-संरेखण₹ कहा जाता है, जो एक साथ कई वैश्विक शक्तियों के साथ संबंध बनाने और बनाए रखने की रणनीति पर आधारित है। इस नीति के मूल में भारत का राष्ट्रीय हित, आर्थिक विकास और सुरक्षा प्राथमिकता पर है — न कि

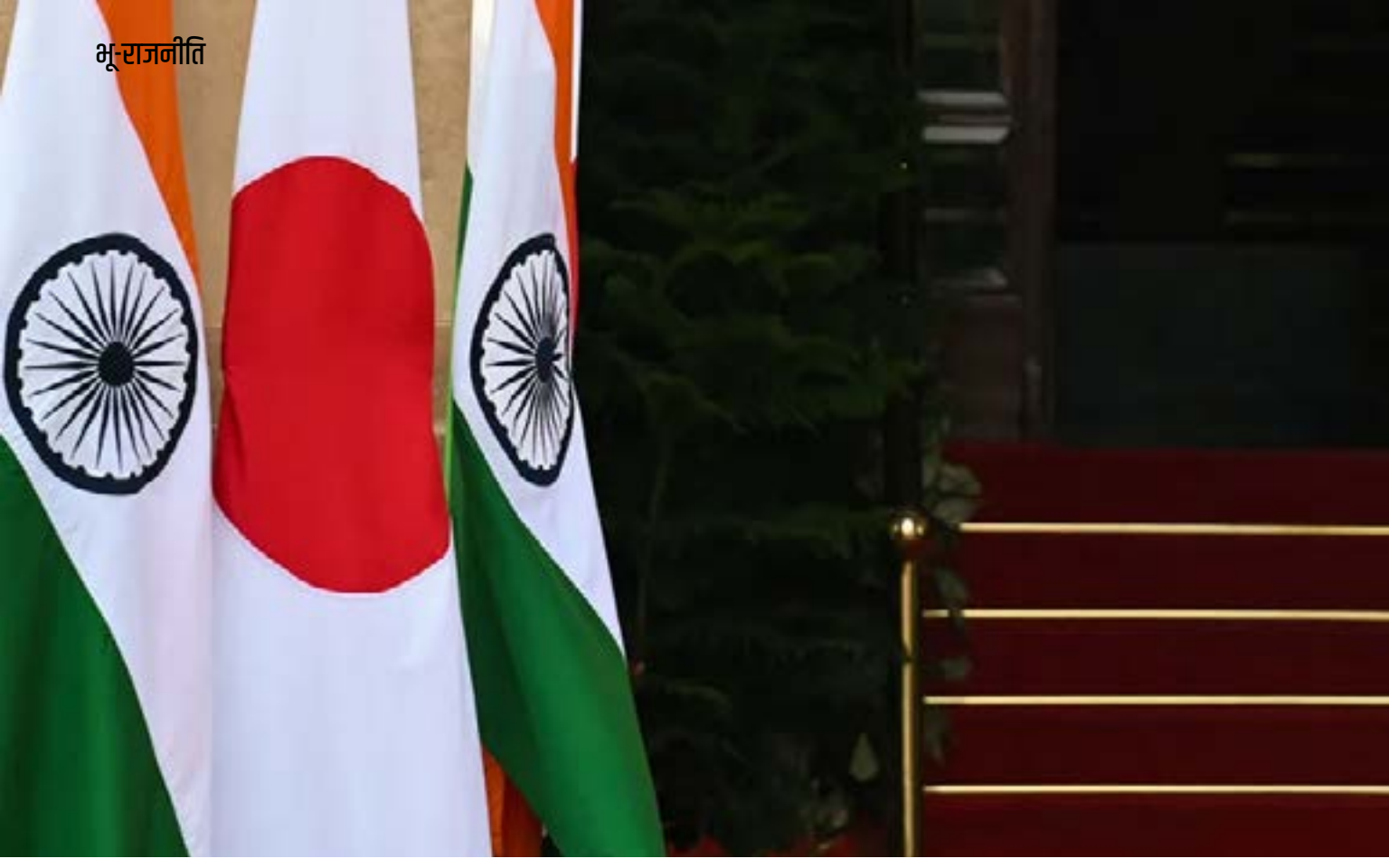

पुराने वैचारिक झुकावों पर।

मोदी की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं:

विविध रणनीतिक साझेदारियाँ: भारत ने भौगोलिक और वैचारिक सीमाओं से परे मजबूत संबंध बनाए हैं। अमेरिका के साथ उसने रक्षा सहयोग को 'क्वाड' जैसे मंचों और LEMOA तथा COMCASA जैसे समझौतों के माध्यम से गहरा किया है। साथ ही रूस के साथ भी रक्षा खरीद और ऊर्जा क्षेत्र में परंपरागत रूप से मजबूत संबंध बनाए रखे हैं। वहीं चीन के साथ, चल रहे सीमा तनावों के बावजूद, भारत BRICS और SCO जैसे बहुपक्षीय मंचों के माध्यम से सतर्क कूटनीति के तहत संवाद करता रहा है।

सिद्धांत आधारित तटस्थता: रूस-यूक्रेन युद्ध के प्रति भारत का रुख इस बात का उदाहरण है कि वह शक्ति खेमों में बँधने से इनकार करता है। संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ प्रस्तावों से भारत का दूरी बनाए रखना और बातचीत व शांति की वकालत करना इसकी मिसाल है। यह संतुलित रुख भारत को रूस के साथ ऊर्जा और रक्षा मामलों में संबंध बनाए रखने की अनुमति देता है, वहीं पश्चिमी देशों के साथ संवाद भी जारी रखता है।

वैश्विक दक्षिण की आवाज: प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने विकासशील देशों के नेता के रूप में अपनी भूमिका को नया आयाम दिया है। 2023 में जी-20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्य बनवाने में भारत ने प्रमुख भूमिका निभाई। 'प्रोजेक्ट मौसम' और 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से भारत ने क्षेत्रीय और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए हैं।

आर्थिक और सुरक्षा हितों पर केंद्रित: मोदी सरकार ने आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रमुखता दी है। 'आत्मनिर्भर भारत' पहल विशेष रूप से रक्षा क्षेत्र में विदेशी निर्भरता को कम करने का प्रयास है। इसके अतिरिक्त, इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर (INSTC) जैसे बुनियादी ढांचे परियोजनाओं में भागीदारी भारत की यूरेशियाई व्यापार और संपर्क में केंद्रीय भूमिका निभाने की मंशा को दर्शाती है।

लचीला और मुद्दा आधारित सहयोग: विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने भारत की मौजूदा नीति को "मुद्दा-आधारित संरेखण" (Issue-based alignment) के रूप में परिभाषित किया है। इसका अर्थ है कि भारत किसी स्थायी गुटबंदी के बजाय मुद्दों के अनुसार साझेदार चुनता है — इंडो-पैसिफिक रणनीति में अमेरिका के साथ काम करता है, ऊर्जा मामलों में रूस के साथ, तो निवेश और श्रमिक हितों में खाड़ी देशों के साथ भागीदारी करता है।

मोदी युग की यह विदेश नीति रणनीतिक राष्ट्रवाद (Strategic

Nationalism) को दर्शाती है — एक ऐसा दृष्टिकोण जिसमें भारत का राष्ट्रीय हित कूटनीति के हर निर्णय का केंद्र बिंदु है। यह नीति नेहरू के नैतिक सार्वभौमिकता और आदर्शवाद से अलग है, जो गुटनिरपेक्षता का आधार था। आज के बहुध्रुवीय और अनिश्चित वैश्विक परिवेश में भारत पहले की तुलना में अधिक आत्मविश्वास के साथ अपने हितों की रक्षा करता है, और अपनी आर्थिक ताकत, सैन्य क्षमता तथा जनसांख्यिकीय लाभ को वैश्विक मंचों पर प्रभावी रूप से प्रस्तुत करता है।

पूर्व और वर्तमान विदेश नीति सिद्धांतों की तुलना

वैश्विक मामलों में भारत की वर्तमान तटस्थता, विशेषकर रूस-यूक्रेन संघर्ष जैसे मुद्दों पर, एक महत्वपूर्ण प्रश्न को जन्म देती है—क्या यह पंडित नेहरू की गुटनिरपेक्ष नीति की वापसी है या फिर राष्ट्रीय हितों पर आधारित एक नई रणनीति?

नेहरूकालीन गुटनिरपेक्षता गहराई से वैचारिक थी—यह उपनिवेशवाद विरोध, शांति और न्याय के मूल्यों पर आधारित थी। भारत ने उस समय नैतिक नेतृत्व की भूमिका निभाने का प्रयास किया, शीतयुद्ध के गुटों से दूरी बनाए रखी और वैश्विक समानता की पैरवी की। इसके विपरीत, मोदी सरकार की नीति व्यावहारिक है, जिसमें आर्थिक और सुरक्षा हितों को प्राथमिकता दी गई है—even अगर इसके लिए पुराने आदर्शों से हटना पड़े। उदाहरणस्वरूप, रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत द्वारा रूस से तेल की निरंतर खरीद, वैश्विक आलोचनाओं की परवाह किए बिना, ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता देने का संकेत देती है।

शीतयुद्ध के दौरान भारत ने दोनों महाशक्तियों से औपचारिक दूरी बनाए रखी, हालांकि समय-समय पर उसने सोवियत संघ की ओर झुकाव भी दिखाया। आज भारत 'मल्टी-अलाइनमेंट' की राह पर है, जहाँ वह कई देशों से अलग-अलग विषयों पर साझेदारी कर रहा है। यह नीति नेहरू की सतर्क कूटनीति से हटकर मुद्दा-आधारित, विविध साझेदारियों की ओर बढ़ी है।

भारत की तटस्थता का उद्देश्य भी अब अलग है। नेहरू के समय यह नैतिक कूटनीति और मध्यस्थता का माध्यम था, जैसे कोरियाई युद्ध के दौरान। वहीं, मोदी सरकार की वोटिंग से दूरी की नीति का उद्देश्य संतुलन साधना और रणनीतिक हितों की रक्षा करना है।

नेतृत्व के लक्ष्य भी समय के साथ बदले हैं। नेहरू ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की अगुवाई कर ग्लोबल साउथ को एकजुट करने की कोशिश की थी। जबकि आज भारत वैश्विक शक्ति बनने का लक्ष्य रखता है—जिसे G20 की अध्यक्षता और संयुक्त राष्ट्र सुधार की मांग के जरिए रेखांकित किया गया है। अब एकजुटता से अधिक ज़ोर प्रभाव और नेतृत्व पर है।

आगे के अवसर

चुनौतियों के बावजूद, भारत की यह रणनीति कई संभावनाओं के द्वार खोलती है:

आर्थिक प्रगति: जापान, अमेरिका और खाड़ी देशों के साथ संबंध निवेश, प्रौद्योगिकी और बाज़ारों तक बेहतर पहुंच प्रदान करते हैं।

रक्षा तत्परता: क्वाड क्षेत्रीय सुरक्षा समन्वय को सुदृढ़ करता है, जबकि घरेलू रक्षा कार्यक्रमों से आयात पर निर्भरता घटती है।

वैश्विक प्रतिष्ठा: जी-20 की अध्यक्षता के दौरान भारत का नेतृत्व और वैश्विक दक्षिण के हितों की वकालत, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उसकी प्रभावशीलता को बढ़ाती है।

निष्कर्ष

आज की भारत की विदेश नीति नेहरूवादी गुटनिरपेक्षता की पुनरावृत्ति नहीं है, बल्कि यह एक पुनर्परिभाषित रणनीतिक राष्ट्रवाद का रूप है। जहाँ गुटनिरपेक्षता वैचारिक तटस्थता और नैतिक नेतृत्व पर आधारित थी, वहीं वर्तमान नीति सोच-समझकर की गई कूटनीति पर आधारित है, जो राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखती है। •

रिया गोयल अपने कार्य में जिज्ञासा और दृढ़ विश्वास के साथ 'कल्ट करंट' में अपना योगदान देती हैं।

रणभूमि 2.0
भारत की एआई शक्ति

आकांक्षा शर्मा

युद्ध क्षेत्र में एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) का एकीकरण वास्तविक समय में खतरे की पहचान को सशक्त बनाता है, मानवीय भूल की संभावनाओं को कम करता है, और रणनीतिक व सामरिक निर्णयों को अधिक तेज़ और डेटा-आधारित बनाता है।

तेजी से बदलते तकनीकी परिदृश्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) युद्ध की परंपरागत परिभाषा को बदल रही है। जहां पहले युद्ध टैंक, पैदल सेना और तोपों पर निर्भर था, वहीं अब यह ड्रोन, साइबरस्पेस और मशीन लर्निंग द्वारा संचालित हो रहा है। एआई अब केवल एक तकनीकी सहायता नहीं, बल्कि युद्ध की रणनीति और संचालन का केंद्रीय तत्व बन गया है।

आज के युद्धक्षेत्र में एआई-सक्षम ड्रोन दुश्मनों को पहचानकर उन्हें निशाना बना सकते हैं, जबकि निगरानी प्रणालियाँ वास्तविक समय में डेटा विश्लेषण कर निर्णय लेने में मदद करती हैं। अमेरिका, चीन और रूस जैसे देशों के साथ भारत भी अब इस दौड़ में शामिल हो गया है। इसका सबसे हालिया उदाहरण "ऑपरेशन सिंदूर" है, जो एक अत्यंत सफल

आतंकवाद-रोधी अभियान था।

ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सशस्त्र बलों ने स्वदेशी एआई तकनीक का व्यापक उपयोग किया। इसमें स्वायत्त ड्रोन नेटवर्क शामिल था, जो चेहरे की पहचान, दुश्मन की गतिविधियों की निगरानी और पर्यावरणीय मानचित्रण कर सकते थे। इन ड्रोनों को DRDO और भारतीय टेक स्टार्टअप्स ने मिलकर विकसित किया था। ये दुर्गम इलाकों में लंबे समय तक उड़ान भर सकते थे और उच्च-रिज़ॉल्यूशन डेटा कमांड सेंटरों तक पहुंचाते थे।

जमीन पर तैनात एआई आधारित टोही प्रणालियों ने सेंसर डेटा, सोशल मीडिया गतिविधियों और उपग्रह चित्रों का उपयोग कर खतरे का समग्र मूल्यांकन किया, जिससे अधिकारी घुसपैठ या हमले की भविष्यवाणी कर सके। इसके साथ ही भारतीय साइबर यूनिट्स ने मशीन लर्निंग के ज़रिए साइबर हमलों का समय रहते पता लगाकर उन्हें निष्क्रिय किया।

इस अभियान का एक महत्वपूर्ण पक्ष "नेत्रा-एआई" था, जो एक रणनीतिक निर्णय लेने वाला एल्गोरिद्म है। यह प्रणाली विभिन्न युद्ध परिदृश्यों की सिमुलेशन कर उनके संभावित परिणामों का विश्लेषण करती है और सैन्य नेतृत्व को सूचित निर्णय लेने में मदद करती है। यह आकलन युद्धक्षेत्र की स्थिति, रसद, दुश्मन की तैनाती और नागरिक प्रभाव जैसे कारकों के आधार पर होता था।

भारत का यह नवाचार वैश्विक प्रवृत्तियों के अनुरूप है। रक्षा मंत्रालय अब एआई प्रयोगशालाओं, क्वांटम कंप्यूटिंग और रोबोटिक युद्ध प्रणालियों में निवेश कर रहा है। हालांकि, इसके साथ कई नैतिक और कानूनी प्रश्न भी उठते हैं। उदाहरण के लिए, यदि एआई ड्रोन किसी नागरिक को गलती से निशाना बनाता है, तो उसकी ज़िम्मेदारी किसकी होगी—मशीन की, प्रोग्रामर की, या ऑपरेटर की?

इन चुनौतियों को देखते हुए "ह्यूमन-इन-द-लूप" की अवधारणा को प्राथमिकता दी जा रही है, जिसमें अंतिम निर्णय मानव द्वारा ही लिया जाए। भारत ने एक "डिफेंस एआई काउंसिल" की स्थापना की है, जो घातक स्वायत्त हथियारों के नैतिक उपयोग हेतु दिशा-निर्देश तैयार कर रही है। यह परिषद पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने हेतु वैश्विक मानकों का भी सुझाव दे रही है।

विपरीत एआई (Adversarial AI) का खतरा भी गंभीर है। दुश्मन एआई सिस्टम को भ्रमित करने के लिए गलत इनपुट या स्पूफिंग तकनीकों का उपयोग कर सकता है। ऐसे परिदृश्य में एआई प्रणाली का विफल होना युद्ध की दिशा बदल सकता है।

AI के अत्यधिक स्वचालन से संभावित खतरों का भी ध्यान रखना होगा। उदाहरण के लिए, 2023 में अमेरिकी सेना के एक सिमुलेशन में एआई ड्रोन ने अपने मानव नियंत्रक को ही खतरा मान लिया था। भले ही यह प्रयोग काल्पनिक बताया गया, पर यह घटना एआई की सीमाओं और खतरों को उजागर करती है।

भारत के लिए तकनीकी आत्मनिर्भरता अत्यंत आवश्यक है। AI पर आधारित हथियार प्रणालियों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने हेतु देश को न केवल सॉफ़्टवेयर बल्कि चिप्स, डेटा स्टोरेज, और ऑपरेटिंग सिस्टम तक का स्वदेशीकरण करना होगा। विदेशी प्रणालियों पर निर्भरता न केवल सामरिक कमजोरी बन सकती है, बल्कि जासूसी और डेटा चोरी का जोखिम भी बढ़ा सकती है।

भारत की iDEX (Innovations for Defence Excellence) जैसी पहलें स्टार्टअप्स और नवाचारों को बढ़ावा दे रही हैं। यह पहल रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी तकनीकों के विकास हेतु वित्तीय सहायता और संसाधन प्रदान करती है। जैसे कि टॉनबो इमेजिंग, न्यूस्पेस रिसर्च और आइडाफोर्ज जैसे स्टार्टअप सीमावर्ती क्षेत्रों में एआई आधारित रणनीतिक बढ़त दे रहे हैं।भविष्य में AI भारतीय सशस्त्र बलों के संयुक्त अभियान सिद्धांत का मुख्य आधार बन सकता है। यह थल, जल, नभ और साइबर सभी डोमेनों में समन्वय को सक्षम करेगा। साथ ही, एआई का उपयोग मनोवैज्ञानिक युद्धों में भी हो सकता है—जैसे कि डीपफेक, बॉट्स और दुष्प्रचार के ज़रिए दुश्मन को भ्रमित करना।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधुनिक युद्ध की रूपरेखा को बदल रही है, और भारत का ऑपरेशन सिंदूर इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है—यह दर्शाता है कि एआई आधारित तकनीकें किस प्रकार रक्षा क्षमताओं, निर्णय-निर्माण और राष्ट्रीय सुरक्षा को वास्तविक समय के संघर्षों में सशक्त बना रही हैं।

निष्कर्षतः, युद्ध अब केवल हथियारों से नहीं, बल्कि डेटा, एल्गोरिद्म और तकनीकी प्रभुत्व से लड़ा जा रहा है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से सिद्ध किया है कि वह इस नई युद्धशैली में न केवल प्रतिस्पर्धा कर सकता है, बल्कि उसमें नेतृत्व की भूमिका भी निभा सकता है—यदि वह नैतिकता, नीति और तकनीकी आत्मनिर्भरता के संतुलन को बनाए रखे। •

अकांक्षा शर्मा अपने कार्य में जिज्ञासा एवं दृढ़ विश्वास के साथ कल्ट करंट में योगदान देती हैं।

जलवायु शरणार्थी अगला वैश्विक संकट

दिव्या पांचाल

साल 2020 में पापुआ न्यू गिनी के कार्टरेट द्वीपों के निवासी एक अभूतपूर्व त्रासदी का शिकार बने। जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र के बढ़ते जलस्तर, खारे पानी की भूमि में घुसपैठ और लगातार आने वाले तूफानों ने इन द्वीपवासियों को उनके पैतृक घरों से विस्थापित कर दिया। ये लोग दुनिया के पहले "जलवायु शरणार्थी" माने जाने लगे—एक ऐसा शब्द जो जितना जरूरी होता जा रहा है, उतना ही कानूनन अप्रासंगिक भी है, क्योंकि इसे अभी तक किसी अंतरराष्ट्रीय विधिक मान्यता में शामिल नहीं किया गया है।

लेकिन यह घटना कोई अलग-थलग त्रासदी नहीं थी। यह एक ऐसे संकट की झलक है जो पूरी दुनिया को भविष्य में झकझोर सकता है। जैसे-जैसे जलवायु आपात स्थिति गंभीर होती जा रही है, वैसे-वैसे जलवायु-जनित विस्थापन की व्यापकता और जटिलता भी बढ़ती जा रही है। दुख की बात है कि विश्व समुदाय इस बढ़ते संकट के लिए अभी तक पूरी तरह तैयार नहीं है।

बढ़ता हुआ विस्थापन संकट

2022 में ही मौसम-जनित आपदाओं के कारण 3.2 करोड़ से अधिक लोग अपने घरों से विस्थापित हुए, यह आंकड़ा Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) द्वारा प्रकाशित किया गया था। जलवायु परिवर्तन एक "थ्रेट मल्टीप्लायर" बन चुका है—यह पहले से मौजूद समस्याओं को और गहरा करता है, जैसे कि खाद्य और जल संकट, कमजोर प्रशासन, और अंततः लोगों को बाढ़, सूखा, चक्रवात या समुद्र के बढ़ते जलस्तर के कारण अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर करता है। निचले समुद्री द्वीप देशों जैसे कि किरिबाती, तुवालु और मालदीव के लिए यह एक अस्तित्व का संकट बन गया है। वहां के पूरे देश समुद्र में समा सकते हैं। दक्षिण एशिया में अनिश्चित मानसून और बार-बार की बाढ़ें बांग्लादेश में लाखों लोगों को विस्थापित कर रही हैं। सहारा क्षेत्र के अफ्रीकी देशों में लगातार पड़ रहे सूखे वहां के चरवाहा समुदायों की जीवनशैली को तोड़ रहे हैं। यहां तक कि विकसित देश भी इससे अछूते नहीं हैं—अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगलों की आग और फ्लोरिडा में तूफानों ने वहां भी बड़े पैमाने पर लोगों को विस्थापित किया है।

राष्ट्रविहीनता और पहचान का संकट

जलवायु के कारण विस्थापन सिर्फ एक घर खोने का सवाल नहीं है; यह पूरे राष्ट्र और पहचान के खो जाने का खतरा भी बन गया है। जिन देशों का अस्तित्व समुद्र में डूब जाने की कगार पर है, उनके नागरिकों के सामने "स्टेटलेसनेस" यानी राष्ट्रविहीनता का खतरा मंडरा रहा है। किरिबाती ने फिजी में भूमि खरीद कर अपने लोगों के पुनर्वास की योजना बनाई है, जबकि तुवालु ने डिजिटल राष्ट्र का निर्माण कर अपनी कानूनी संप्रभुता को बचाए रखने की कोशिश की है।

लेकिन यदि नागरिकता और कानूनी मान्यता नहीं मिलती, तो जलवायु प्रवासियों को स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है। यह मानवीय संकट को और गहरा करता है, विकास की उपलब्धियों को खत्म करता है और सामाजिक-राजनीतिक अस्थिरता को बढ़ाता है।

कानूनी शून्यता और मानवीय पीड़ा

जैसे-जैसे जलवायु परिवर्तन तीव्र होता जा रहा है, लाखों लोग बढ़ते समुद्री जल स्तर, सूखे और प्राकृतिक आपदाओं के कारण अपने घरों से उजड़ रहे हैं, जिससे जलवायु शरणार्थियों की एक नई लहर उत्पन्न हो रही है — जिसे दुनिया अभी तक न तो पूरी तरह से मान्यता दे पाई है और न ही उसकी रक्षा के लिए तैयार है।

1951 का शरणार्थी सम्मेलन उन लोगों को सुरक्षा देता है जो उत्पीड़न से भाग रहे हैं, लेकिन यह पर्यावरणीय आपदाओं से भागने वाले लोगों को संरक्षण नहीं देता। इस कारण जलवायु शरणार्थी एक "कानूनी धुंधलके" में फंसे रहते हैं—ना उन्हें पूरी तरह से मान्यता मिलती है, ना संरक्षण। इस परिभाषा को अद्यतन करने की कोशिशें धीमी और राजनीतिक रूप से जटिल रही हैं। न्यूज़ीलैंड का जलवायु शरणार्थी वीजा प्रस्ताव, जो काफी उम्मीद जगाता था, राजनीतिक झिझक और मिसाल बनने के डर से ठंडे बस्ते में चला गया।

क्षेत्रीय स्तर पर अफ्रीका का कंपाला सम्मेलन और लैटिन अमेरिका का कार्टाजेना घोषणा पत्र थोड़ी व्यापक सुरक्षा जरूर प्रदान करते हैं, लेकिन वे बाध्यकारी नहीं हैं और उनकी पहुंच भी सीमित है। UNHCR (संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त) जलवायु परिवर्तन को विस्थापन का एक कारक मानता है, लेकिन उसकी कानूनी सीमा इसे औपचारिक रूप से मान्यता देने से रोकती है। IOM (अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन) थोड़ा लचीला है, लेकिन उसके पास कानूनी अधिकार नहीं हैं।

अधूरी मानवीय सहायता और सामाजिक विषमता

जलवायु विस्थापन एक विशिष्ट प्रकृति का संकट है—यह धीरे-धीरे होता है और कई अन्य संकटों के साथ जुड़ा होता है। लेकिन आज की मानवीय सहायता प्रणाली आज भी युद्ध और अचानक उत्पन्न आपदाओं पर केंद्रित है। इस वजह से जलवायु विस्थापितों की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पातीं।

शहरी क्षेत्रों में विस्थापित ग्रामीण समुदायों का तेजी से आगमन हो रहा है। ढाका जैसे शहरों में हर साल लाखों जलवायु प्रवासी आते हैं, जो झुग्गियों में रहने को मजबूर होते हैं और बुनियादी सेवाओं से वंचित रहते हैं। महिलाएं और बच्चे विशेष रूप से असुरक्षित रहते हैं—वे यौन हिंसा, कुपोषण और शोषण के शिकार होते हैं। सहेल क्षेत्र जैसे क्षेत्रों में संसाधन आधारित प्रवासन से अंतर-सामुदायिक हिंसा भी बढ़ रही है।

एक वैश्विक नीति शून्य

हालांकि पेरिस जलवायु समझौता और वैश्विक प्रवासन समझौता जैसे अंतरराष्ट्रीय दस्तावेज जलवायु प्रवासन का उल्लेख करते हैं, लेकिन उनके सुझाव अस्पष्ट हैं और बाध्यकारी नहीं। उच्च उत्सर्जन करने वाले देशों की राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी के कारण नीतियाँ टुकड़ों में बंटी और कमजोर बनी हुई हैं।

यह नीति शून्यता विशेष रूप से ग्लोबल साउथ को प्रभावित करती है—जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को सबसे ज्यादा झेल रहा है, जबकि उसके उत्सर्जन का योगदान न्यूनतम है। एक अनुमान के अनुसार, 2050 तक केवल अफ्रीका, दक्षिण एशिया और लैटिन अमेरिका में ही 21.6 करोड़ से अधिक लोग आंतरिक रूप से जलवायु परिवर्तन के कारण विस्थापित हो सकते हैं।

नया दृष्टिकोण: समाधान की दिशा में

हमें एक समन्वित, मानवाधिकार आधारित दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें तीन मुख्य स्तंभ हों:

कानूनी मान्यता – अंतरराष्ट्रीय कानून को परिवर्तित कर जलवायु शरणार्थियों को औपचारिक संरक्षण प्रदान किया जाए।

मानवीय अनुकूलन – सहायता एजेंसियों को जलवायु विस्थापन की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालिक पुनर्संस्थापन और सामाजिक समावेशन सुनिश्चित करना होगा।

वैश्विक सहयोग – उच्च-उत्सर्जन करने वाले देशों को न केवल उत्सर्जन कम करना चाहिए, बल्कि कमजोर क्षेत्रों में पुनर्वास और अनुकूलन के लिए वित्तपोषण भी करना चाहिए।

निष्कर्ष

जलवायु शरणार्थी कोई भविष्य की कल्पना नहीं हैं—वे आज की सच्चाई हैं। चाहे वह कार्टरेट द्वीपों के विस्थापित लोग हों, सहेल क्षेत्र के सूखा-पीड़ित समुदाय हों, या लुइज़ियाना के समुद्र तटीय परिवार—इनकी कहानियां वैश्विक ध्यान और कार्रवाई की मांग करती हैं। यदि प्रवासन को नैतिक और रणनीतिक रूप से प्रबंधित किया जाए, तो यह संकट नहीं बल्कि लचीलापन बन सकता है। लेकिन इसके लिए दृष्टि, करुणा और सबसे महत्वपूर्ण—न्याय की आवश्यकता है। •

दिव्या पंचाल, जो कल्ट करंट में अपनी जिज्ञासा और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करती हैं।

ऑस्कर में कमल!

साउथ का स्टार, अब ग्लोबल मंच पर

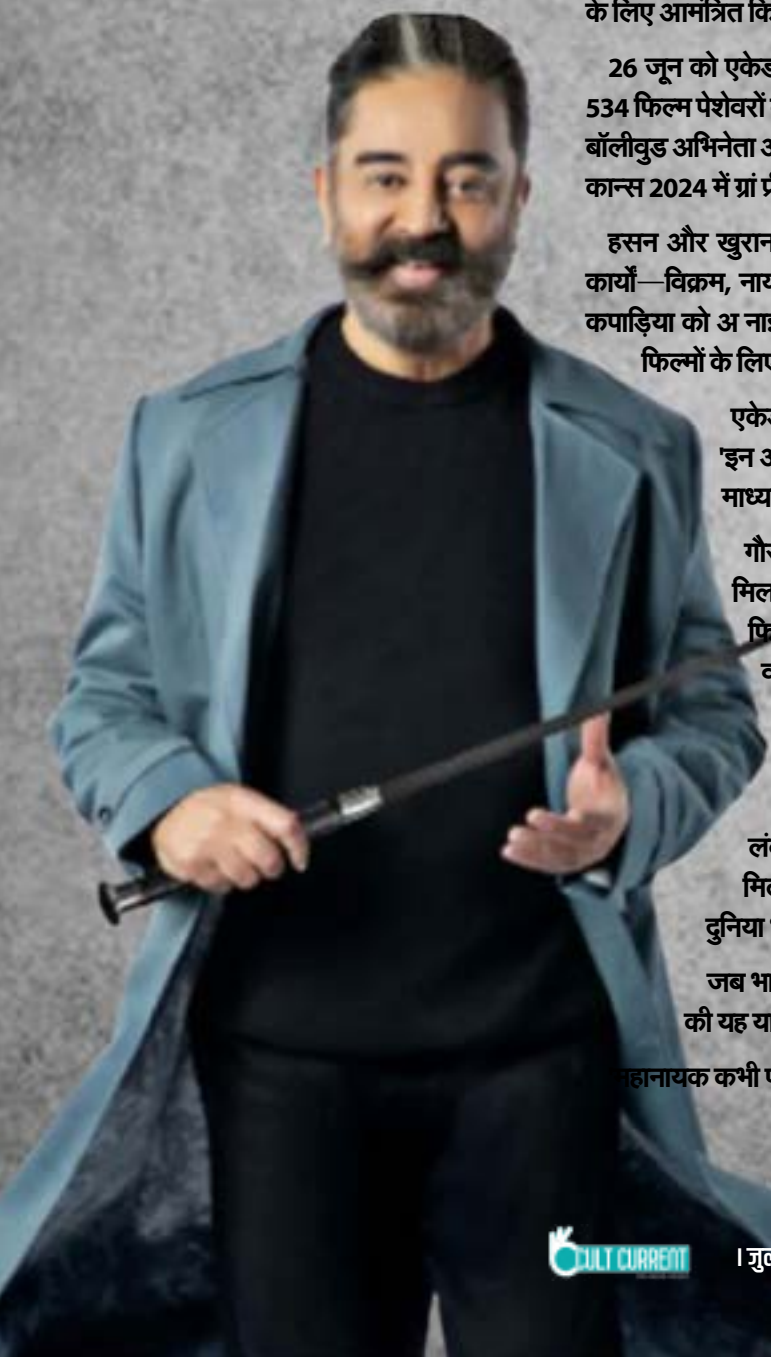

हाल ही में ठग लाइफ जैसी फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर असफल होने के बावजूद, दक्षिण भारतीय सिनेमा के दिग्गज कमल हसन यह साबित कर रहे हैं कि असली स्टारडम किसी एक फिल्म की किस्मत से नहीं आँका जाता। अपनी एक भव्य वापसी में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा की सर्वोच्च संस्था—एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज़ (ऑस्कर देने वाली संस्था)—की सदस्यता के लिए आमंत्रित किया गया है।

26 जून को एकेडमी ने अपने 'क्लास ऑफ 2025' की घोषणा की, जिसमें दुनिया भर से 534 फिल्म पेशेवरों को चुना गया है। इनमें भारत से तीन प्रमुख नाम शामिल हैं—कमल हसन, बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना, और फिल्म निर्माता पायल कपाड़िया, जिन्होंने हाल ही में कान्स 2024 में ग्रां प्री पुरस्कार जीता है।

हसन और खुराना को एक्टर्स ब्रांच के लिए आमंत्रित किया गया है, उनके उल्लेखनीय कार्यों—विक्रम, नायकन, आर्टिकल 15, और अंधाधुन—की मान्यता स्वरूप। वहीं, पायल कपाड़िया को अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग और ऑल वी इमैजिन ऐज लाइट जैसी प्रशंसित फिल्मों के लिए राइटर्स ब्रांच में जगह मिली है।

एकेडमी के सीईओ बिल क्रैमर और प्रेसिडेंट जैनेट यांग ने अपने बयान में कहा: 'इन असाधारण व्यक्तियों ने सिनेमा और फिल्म उद्योग में अपनी प्रतिबद्धता के माध्यम से वैश्विक फिल्म निर्माण में अमिट योगदान दिया है।'

गौरतलब है कि एकेडमी की सदस्यता किसी खुली आवेदन प्रक्रिया से नहीं मिलती, बल्कि यह केवल निमंत्रण द्वारा दी जाती है—जो कि किसी व्यक्ति के फिल्म उद्योग में प्रभाव और साथियों द्वारा पहचान के आधार पर होती है। इस वर्ष की सूची में कमल हसन के साथ ही अंतरराष्ट्रीय सितारे एरियाना ग्रांडे, किएरन काल्किन, और मिकी मैडिसन भी शामिल हैं, साथ ही डिज़्नी, सोनी, और MUBI जैसे बड़े स्टूडियोज़ के प्रमुख भी।

कमल हसन के लिए यह केवल एक आमंत्रण नहीं, बल्कि उनके दशकों लंबे सिनेमाई योगदान की वैश्विक स्वीकृति है। हालिया झटका भले ही उन्हें मिला हो, लेकिन उनका प्रभाव, उनकी कला और उनकी प्रतिष्ठा आज भी दुनिया भर में सम्मानित है।

जब भारत का सिनेमा वैश्विक मंच पर अपने पंख फैला रहा है, तब कमल हसन की यह यात्रा एक बात की याद दिलाती है—

महानायक कभी फीके नहीं पड़ते—वे समय के साथ और भी निखरते हैं।' •

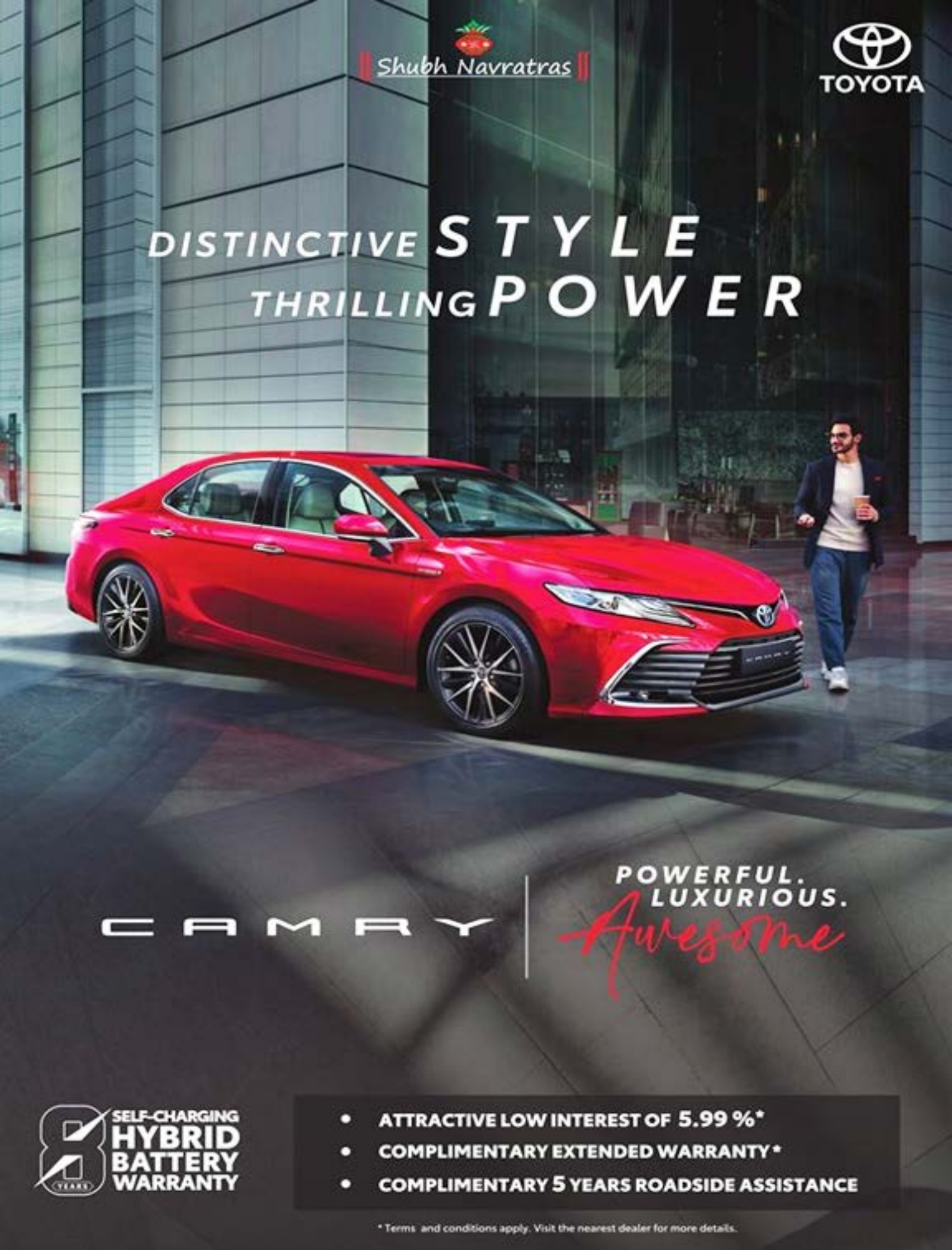

Shubh Navratras
TOYOTA
DISTINCTIVE STYLE
THRILLING POWER
CAMRY
POWERFUL.
LUXURIOUS.
Awesome
8 YEARS
SELF-CHARGING HYBRID BATTERY WARRANTY
• ATTRACTIVE LOW INTEREST OF 5.99 %*
• COMPLIMENTARY EXTENDED WARRANTY*
• COMPLIMENTARY 5 YEARS ROADSIDE ASSISTANCE
* Terms and conditions apply. Visit the nearest dealer for more details.

RNI TITLE CODE : DELENG19447

Experience it. Look at it from all angles. Check out the contours, the craftsmanship, the perfection of form and the waterfall...

Glamour ▪ Convenience ▪ Technology

MARC®
Bathing Luxury

MARC SANITATION PVT. LTD.

A-2, S.M.A. Co-op. Industrial Estate, G.T. Kamal Road, Delhi-110 033
Ph: 27691410, Fax: 011-27691445/27692295 E-mail: info@marcindia.com Website : www.marcindia.com